राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ६] तृतीय विधान सभा के नवम् सत्र, १९६६ का १८ वां दिवस [संख्या १५

बुधवार,

दिनांक १६ मार्च, १९६६

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.०१ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(उद्योग, सार्वजनिक निर्माण, वन, विद्युत्, यातायात, पंचायत, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, चिकित्सा, स्वास्थ्य, राजकीय उद्योग विभाग)

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री हनुमानसिंह चौधरी।

नावां-मारोठ सड़क की मरम्मत

२८१. श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नावां-मारोठ सड़क का निर्माण कब हुआ, व आज तक कितनी बार कब-कब इसकी मरम्मत की गई?

(२) उक्त सड़क के मेंटल रोड बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव स्थानीय पंचायत की ओर से कब से चले आ रहे हैं व उन पर आज तक सरकार ने क्या कार्यवाही की?

(३) क्या यह भी सही है कि केवल इस ७ मील के टुकड़े को बीच में छोड़कर इसके दोनों तरफ पक्की सड़कें मौजूद हैं? यदि हां, तो इसे आज तक पक्की नहीं बनाने के क्या कारण हो सकते हैं?

(४) क्या यह भी सरकार के ध्यान में है कि अत्यधिक वर्षा के कारण उक्त कच्ची सड़क बिल्कुल टूट गई है व हर रोज चलने वाली बसों के खराब होने से जनता परेशान है?

(५) इसे कब तक मेटल रोड बनाने का सरकार का इरादा है?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री परसराम मदेरणा) : (१) इस सड़क का निर्माण ११४६ में हुआ है। आवश्यकतानुसार वार्षिक मरम्मत होती रहती है।

(२) यह कार्य तृतीय योजना में स्वीकृत कर दिया गया है।

(३) जी हां, कार्य चल रहा है।

(४) वर्षा में प्रायः कहीं-कहीं खड्डे हो जाते है जिन्हें वर्षा के बाद ठीक कर दिया जाता है।

Page No. 2

(श्री परसराम मदेरणा)

(५) कार्य आरम्भ कर दिया है।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : कार्य अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है और यह बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। इसकी दो साल पहले स्वीकृति हुई थी।

श्री परसराम मदेरणा : दो साल पहले स्वीकृति नहीं हुई है। राज्य सरकार की स्वीकृति १२ मई, १९६५ को हुई और उसके बाद फाइनल। टेक्नीकल सेंक्शन ११ अक्टूबर, १९६५ को हुई है। उसके बाद टेन्डर २९-१-६६ को हुआ है और ठेकेदार को आॅर्डर फरवरी, १९६६ में दिया है। यह मेटल वर्क है, ग्रेवेल वर्क पहले की है। मेटल का काम शुरु हो चुका है।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : सेंक्शन कितनी है ?

श्री परसराम मदेरणा : २,४०,०००)। जो इस साल में न होगा वह चौथी योजना में लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

कोकन्दा–घनवास (झालावाड़) में बीड़ से लकड़ी बाहर ले जाने व उसके बेचान पर रोक

२८२. **श्री जुझारसिंह (चेचट)** : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि झालावाड़ में कोकन्दा-घनवास की बोड़ राणा प्रतापसागर के विस्थापितों व स्थानीय भील परिवारों को अलॉट कर दी गई है व जंगलात विभाग से इसका नियन्त्रण हटा लिया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि विस्थापितों द्वारा उनको स्थानान्तरित की गई भूमि पर ठेके से पेड़ कटवाये जा रहे हैं जो रामगंज मंडी व झालावाड़ पाटन तहसील में जलाने को बेचे जाते हैं व जिस पर स्थानीय अधिकारियों द्वारा माल हटाने पर रोक लगादी गई है ?

(३) क्या राणा प्रतापसागर के विस्थापितों पर जो रामगंज मंडी के बहुत से दूसरे गांवों में भी बसाये गये हैं, लकड़ी बाहर निकालने व बेचने पर पाबन्दी लगाई गई है ? यदि नहीं, तो झालावाड़ में पाबन्दी लगाने के क्या कारण हैं ?

(४) क्या सरकार कोकन्दा–घनवास में विस्थापितों द्वारा कटाई जाने वाली लकड़ी के बेचान व बाहर ले जाने पर से पाबन्दी के हटाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उप-मंत्री, वन (श्री रामप्रसाद लड्ढा) :

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां, किसी गलतफहमी के कारण वन अधिकारियों ने पाबन्दी लगादी थी जिसे समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जुझारसिंह : आपने आदेश कब जारी किए हैं ? मुझे कल तक तो यही खबर है कि कटाई की लकड़ी को उठाने नहीं देते हैं। अभी अगर एक आध दिन में आपने आदेश दे दिए हों तो बतायें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आदेश तो जब आपके द्वारा प्रश्न पूछा गया और हमारा ध्यान आकर्षित हुआ तब मामला एग्जामिन किया गया और आदेश १४-३-६९ को प्रसारित किए हैं, हो सकता है वहां नहीं पहुँचे होंगे लेकिन आज पहुँच जायेंगे और वे पाबन्दी हटा देंगे।

प्रश्न संख्या २८३

श्री अध्यक्ष: श्री मजलिस खां।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

वैद्य श्री गोविन्दसहाय !

गंगापुर-जयपुर रूट पर सीधी बस-सर्विस

२८४. **वैद्य श्री गोविन्दसहाय** (गंगापुर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान रोडवेज की बसें चलने से पहले गंगापुर से जयपुर सीधी बसें कितनी चलती थीं ?

(२) क्या यह सही है कि अब सीधी बस नहीं चलने के कारण दौसा में यात्रियों को कठिनाई होती है क्यों कि भरतपुर से बसें भरी हुई आती हैं ?

(३) क्या गंगापुर-जयपुर सीधी सर्विस चलाने का विचार है ?

उप मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) :

(१) राजस्थान रोडवेज की बसें चलने से पूर्व गंगापुर से जयपुर सीधी २२ बसें रोटेशन में चलती थीं। रोजाना ४ बसें गंगापुर से जयपुर आतीं और ४ ही जयपुर से गंगापुर जाती थीं।

(२) निगम द्वारा जयपुर-भरतपुर व जयपुर-आगरा के अलावा जयपुर-दौसा के लिए भी सर्विसें चलाई जाती हैं। अतः यात्रियों को कठिनाई होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) सन् १९६७ तक तो नहीं है।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय: दौसा से जयपुर कितनी बसें चलती हैं ?

श्री भीमसिंह : ४।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : यह जो ४ बसों का जाना और आना आपने बताया है उसी रूट पर आपने सीधा सवाईमाधोपुर से जयपुर दे रखा है, करौली से जयपुर दे रखा है तो गंगापुर से जयपुर जाने के लिए परेशानी होती है। आपने बताया कि दिक्कत नहीं होती है परन्तु परसों डेढ़ घण्टा मैं बस स्टैण्ड पर पड़ा रहा, वहां बसें भरी हुई रहती हैं, तो सवारी नहीं लेती हैं।

श्री भीमसिंह : जयपुर से दौसा ४ बार आती भी हैं और जाती भी हैं। बाकी जो आगरा-भरतपुर से बसें आती हैं। उनमें जगह खाली होती है तो लेते हैं, नहीं होती है तो नहीं लेते हैं।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन मु.) : क्या यह सही है कि मेला या अन्य प्रकार की छुट्टी हो तो यात्रियों को अधिक देर तक बस स्टैण्ड पर इन्तजार करना पड़ता है ?

श्री भीमसिंह : मेलों के समय अलग बसेज की व्यवस्था की जाती है फिर भी अगर रश होता है तो इन्तजार करना पड़ता है।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : इस रूट पर राष्ट्रीयकृत बसों की कब व्यवस्था होगी ?

श्री भीमसिंह : १६६७ के बाद जो नई योजनायें बनेंगी तब विचार किया जायगा कि राष्ट्रीयकृत चलाई जाय या नहीं ।

प्रश्न संख्या २८५

श्री अध्यक्ष : श्री मथुरेशबिहारी माथुर

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

श्री दिग्विजयसिंह ।

ग्राम पंचायत, नगर को आयोजित मेले से आमदनी

२८६. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या ग्राम पंचायत, नगर, पंचायत समिति देवली, जिला टोंक द्वारा कोई मेले का आयोजन किया जाता है ? यदि हां, तो कब से ?

(२) इस वर्ष इस मेले मे ग्राम पंचायत नगर को कितनी आमदनी हुई है ?

पंचायत मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हां। जब से पंचायतें बनी हैं तब से ग्राम पंचायत नगर द्वारा मांड करना पशु मेले का आयोजन किया जाता है ।

(२) रु० १६,५०१ और १६ पैसे ।

श्री दिग्विजयसिंह : मेले का आयोजन पंचायत ने कब से शुरू किया ? कौनसी तारीख से किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जब से पंचायत का काम वहां पर शुरू हुआ तब से मेले का आयोजन वह कर रही है । तारीख तो मेरे पास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री हरलाल मीणा ।

प्रतापगढ़—धरियावद सड़क

२८७. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ से धरियावद—उदयपुर सड़क को बनाने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सड़क बन चुकी है ?

(२) क्या यह सड़क उदयपुर से धरियावद तक डामर रोड बन चुकी है ? यदि हां, तो प्रतापगढ़ तक कब मिलाई जावेगी ?

(३) क्या यह सत्य है कि वर्षा काल में प्रतापगढ़ की तरफ के लोगों को धरियावद, उदयपुर व पारसोला जाने के लिये चितोड़ होकर जाना पड़ता है जब कि प्रतापगढ़ से सीधा उदयपुर का रास्ता काफी छोटा पड़ता है ? यदि हां, तो इस रास्ते को बनाने में क्या रुकावट आ रही है ?

(४) क्या यह भी सही है कि प्रतापगढ़ से धरियावद के बीच का इलाका पूरा आदिवासी लोगों का है ? अगर हां, तो क्या इस अकाल के समय में इस सड़क का काम चालू करने का सरकार का विचार है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री परसराम मदेरणा): (१) प्रतापगढ़ से धरियावद की स्वीकृति नहीं थी, केवल धरिया-

Page No. 5

(श्री परसराम मदेरणा)
वद से भटेवर वाया मण्डी रोड़ की स्वीकृति थी ।

(२) जी नहीं ।

(३) जी हां, अर्थाभाव ही रुकावट का कारण है ।

(४) जी हां । अर्थाभाव के कारण सड़क का कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है ।

श्री हरलाल मीणा : सड़क की हालत कैसी है ?

श्री परसराम मदेरणा : वह काफी लंबी है ।

श्री उदयलाल वर्दिया : (लसाड़िया) : जिसके लिए प्रश्न चल रहा है उसके दोनों तरफ रास्ता तो बन चुका है और थोड़ा सा बाकी है, यह कितना बाकी है ?

श्री परसराम मदेरणा : बीच में टुकड़ा नहीं बन पाया है ।

श्री उदयलाल वर्दिया : यह टुकड़ा कितना बाकी है ?

श्री परसराम मदेरणा : ६ मील धरियावद की तरफ और प्रतापगढ़ की तरफ में दो मील बन चुका है । १२ मील का टुकड़ा है ।

एक माननीय सदस्य : बीच बीच में छोड़ने का क्या कारण है ?

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : मध्यप्रदेश से लिंकड है मन्दसौर, प्रतापगढ़, धरियावद, मंगलवाड़ और उदयपुर । आप उससे इन्कार करते हैं लेकिन मैंने देखा है कि सड़क बन चुकी है, फिर क्या कारण है धरियावद से प्रतापगढ़ जो छोटा टुकड़ा है उसको मध्यप्रदेश से लिंक क्यों नहीं कर रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : आप जो रूट बता रहे हैं वह सक्यूंलस है । चित्तौड़गढ़ होकर आगे यह प्रतापगढ़ से धरियावद होकर जायगा ताकि उदयपुर के लिए सीधी सर्विस हो जाय ।

श्री अब्दुलजब्बार : १२ मील का सवाल नहीं है । मन्दसौर से प्रतापगढ़ जाती है जहां मध्यप्रदेश के रोडवेज चलते हैं, राजस्थान की टेरीटरी में आते हैं, प्रतापगढ़ से धरियावद और उदयपुर, तो यह प्रतापगढ़ और धरियावद के बीच जो १२ मील का टुकड़ा है उसको इमर्जेंसी में क्यों नहीं बनाते है ?

श्री परसराम मदेरणा : अर्थाभाव है ।

श्री अब्दुलजब्बार : १२ मील पर १२ लाख का ही तो खर्च है ।

श्री उदयलाल वर्दिया : आपकी चौथी योजना में भी नहीं है ।

श्री परसराम मदेरणा : चौथी योजना में जहां तक सड़कें बनाने का सवाल है, क्या उसकी रूपरेखा होगी, सरकार ने फाइनल नहीं किया, न कोई एलॉटमेंट किया गया है, न इन्डीकेशन्स दी हैं । जो नेक्स्ट फाइनेन्शियल ईयर है उसमें एक करोड़ का प्रावधान रखा गया है । यह प्रोवीजन कम है । पी० डब्ल्यू० डी० का एक करोड़ और ६७

(श्री परसराम मदेरणा)
लाख के जो अभी वर्क्स् चल रहे हैं उनको कम्पलीट करने के लिए प्रोपोजल्स बनाए थे, लेकिन राज्य सरकार ने कम करके जो बजट है उसमें एक करोड़ रखा है। उसमें जो कमिटेड वर्क है उसको भी कम करना पड़ेगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (ग्रांसपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से यह सड़क जो है धरियावद से देवरिया तक यह विशुद्ध आदिवासी क्षेत्र में है और यह क्षेत्र अकाल पीड़ित भी है और मेरे ख्याल में दो तीन घाटे इस सड़क में ऐसे पड़ते है कि राजस्थान भर में इतनी रद्दी और खतरनाक सड़क नहीं होगी। अगर ब्रेक बराबर नहीं हो तो बस खड्डे में पड़ सकती है। आपके लिये यह स्वर्णमय अवसर है। क्या सरकार इस आदिवासी क्षेत्र को राहत पहुँचाने के लिये इस सड़क के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था करेगी? यदि पक्की सड़क बनाने की व्यवस्था न कर सकें तो कम से कम इसके घाटे वगैरा ठीक करके अच्छी बनाने की कोशिश करें, घाटे आदि काटें और रिलीफ में बनायें। यह सरकार के लिये विचार करने की बात है।

(विराम)

श्री अध्यक्ष: श्री जोधसिंह।

श्री अब्दुलजब्बार: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने फरमाया है कि डिपार्टमेंट ने प्रोपोजल्स भेजे और राज्य सरकार ने इन्कार कर दिया। राज्य सरकार में बैठने वाले कोई टेक्निकल आदमी नहीं है। मंत्री महोदय आप ट्राई कराइये। सरकार इसके माने में कुछ नहीं जानती है डिपार्टमेंट में टेक्निकल हैड है वे ही जानते हैं।

श्री परसराम मदेरणा: सरकार को टेक्निकल नालेज परजेस करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न यह है कि टेक्निकल नालेज रखने वाले करोड़ों रुपयों के एस्टीमेट बना कर भेजे और राज्य सरकार के पास पैसा न हो तो उसको कैसे स्वीकार किया जा सकता है। मैंने यह नहीं कहा है कि राज्य सरकार ने कोई टेक्निकल डिफेक्ट निकाल कर वापिस कर दिया हो। इनकम्पलीट वर्क को पूरा करने की क्षमता, जहां तक अर्थ का सवाल है, वह नहीं है।

श्री अब्दुलजब्बार: प्रायोरिटी का कोई क्राइटेरिया बनाना चाहिये।

श्री उदयलाल वदिया: अध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। निवेदन यह है कि सारा फोरेस्ट शिड्यूल्ड एरिया है। उसमें १२ मील का टुकड़ा बनाया जाय तो लाख डेढ़ लाख रुपया खर्च होगा लेकिन उससे फोरेस्ट की आमदनी लगभग १० लाख रुपया प्रतिवर्ष होगी।

श्री अध्यक्ष: श्री जोधसिंह।

गवर्नमेंट प्रेस, उदयपुर में प्रिन्टिंग मशीनें एवं तकनीकी कर्मचारी

२८८. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा): क्या मंत्री, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) गवर्नमेंट प्रेस उदयपुर में कितनी प्रिन्टिंग मशीने है?

(२) हर मशीन की इम्प्रेशन पावर क्या है?

(३) हर मशीन पर कितने इम्प्रेशन निकलते है?

(श्री जोधसिंह चौहान)

(४) सन् १९६१-६२ में टोटल इम्प्रेशन पर डे क्या थे ?

(५) सन् १९६४, १९६५ में इम्प्रेशन पावर क्या रही ?

(६) अगस्त, ६५ में पर डे इम्प्रेशन पावर क्या रही ?

(७) सन् १९६१-६२ में तकनीकी कर्मचारियों की संख्या क्या थी ?

(८) सन् १९६५ में तकनीकी कर्मचारियों की संख्या कितनी थी ?

(९) क्या यह सत्य है कि इस समय गवर्नमेंट प्रेस, उदयपुर की इम्प्रेशन पावर पहले की अपेक्षा आधी भी नहीं है; जब कि कर्मचारियों की संख्या देखते हुए पहले से ज्यादा होनी चाहिये ?

(१०) सरकार ने सन् ६५ में गवर्नमेंट प्रेस, उदयपुर में कितने कर्मचारियों को राज्य सेवा में रखा ? पूर्ण विवरण दें ।

(११) सरकार को उपरोक्त कर्मचारी रखने पर कितना फायदा हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुद्रण एवं लेखन सामग्री मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) १५ प्रिन्टिंग मशीनें हैं ।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) इसका उत्तर प्रश्न भाग २ में दिया गया है ।

(४) कुल दाबें १,६०,५८,२८५ थी जो ६५,०४५ दैनिक होती हैं ।

(५) कुल दाबें २,०६,१४,११६ रहीं ।

(६) अगस्त ६५ में दाबें १५,४६,-७१३ रही है जो ६४,४४६ दैनिक होती है।

(७) तकनीकी कर्मचारी ८२ थे ।

(८) यह संख्या १३३ है ।

(९) जी नहीं । निर्धारित दाब से केवल ५४,८५,८८४ दाब कम हैं ।

(१०) सन् १९६५ में २० कर्मचारियों की नियुक्तियां हुईं ।

इसका विवरण निम्न प्रकार है:--

अक्षर योजक द्वितीय श्रेणी	५
मुद्रक	४
बन्धक	७
कम्प्यूटिंग (संगणक)	४

(११) कर्मचारियों की वृद्धि से विभिन्न कक्षों में कार्य में वृद्धि हुई है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

श्री जोधसिंह चौहान : सरकार ने खुद ने माना है कि कम हुए है तो कमी का क्या कारण है ?

श्री मथुरादास माथुर : नेचर ऑफ प्रिन्टिंग वर्क पर डिपेन्ड करता है । फार्म्स सिर्फ छपवायें जायं तो बहुत ज्यादा इम्प्रेशन आयगा, किताब जावेगी तो कम इम्प्रेशन आयगा । यह इम्पोर्टेन्ट फैक्टर है ।

Page No. 8

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : एफिशियेन्सी के लिये इम्प्रेशन को देखते हैं या प्रिन्टिंग मेटिरियल को देखते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : दोनों ही देखते हैं।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : इम्प्रेशन जो कम हुआ उससे गवर्नमेंट सेटिसफाइड हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : जी हां।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि जिस समय से इम्प्रेशन कम होना बताया गया वहां से ६४-६५ तक इम्प्रेशन कम होता गया हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : ज्यों ज्यों मशीनों की उम्र बढ़ती जाती है तो इम्प्रेशन देने की उम्र कम होती जाती है। इन सब बातों को देखते हुए निराश नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : कुमारी उमा माथुर।

महुवा व मालाखेड़ा स्टेशन पर लेवल क्रासिंग की मांग

२८९. **कुमारी उमा माथुर (रामगढ़)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि ग्राम महुवा पंचायत समिति उमरेण, जिला अलवर के निवासी करीब सात-आठ साल से महुवा व मालाखेड़ा स्टेशन के बीच माइल ५३।१३-१४ पर एक लेबल क्रोसिंग के लिये मांग कर रहे हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि महुवा रेल्वे स्टेशन के पास कोई लेवल क्रोसिंग नहीं है। इस कारण स्टेशन के दूसरी ओर से ग्राम महुवा तथा अन्य भी कई ग्रामों में खेतों पर से कोई सामान नहीं लाया जा सकता है ?

(३) क्या यह भी सही है कि रेल्वे लाइन से दूसरी ओर बैलगाड़ी आदि लाने का एक मात्र रास्ता पुलिया नं० ६३ है जो वास्तव में पानी निकलने का रास्ता है उसे भी रेलवे अधिकारियों द्वारा हाल में बन्द कर दिया गया है ?

(४) क्या यह भी सही है कि ग्रामवासियों की इस कठिनाई को रेल्वे अधिकारियों ने स्वीकार किया है और माना है कि यहां पर वास्तव में लेवल क्रोसिंग की आवश्यकता है ?

(५) क्या यह भी सही है कि करीब दो साल पहले रेलवे अधिकारियों की ओर से ग्राम वासियों की मांग को वाजिब मानते हुए एक पत्र कलेक्टर अलवर के पास आया था जिसमें उन्होंने ३०००) रुपये की मांग राज्य सरकार से की थी जिससे कि लेवल क्रासिंग बनवाया जा सके ?

(६) यदि हां तो आज तक इस संबंध में कलेक्टर अलवर ने क्या कार्यवाही की तथा रेल्वे फाटक अभी तक क्यों नहीं बना ?

उप-मंत्री, गृह-निर्माण (श्री परसराम मदेरणा): (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) जी हां।

(५) जी हां।

(श्री परसराम मदेरणा)

(६) जिस सड़क पर रेल्वे फाटक बनाने का प्रश्न है वह सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों की सूची पर नहीं है। अतः इस विभाग द्वारा रेल्वे फाटक बनाने की स्वीकृति देने का प्रश्न नहीं उठता।

कुमारी उमा माथुर : उस विभाग की ओर से मन्त्री महोदय जवाब दे रहे हैं, यह माना है। अध्यक्ष महोदय, पुलिया बनाने का प्रश्न गत ८ साल से चल रहा है और कलेक्टर के पास से पत्र आ जाने पर भी स्वीकृति नहीं दी गई है। इस स्थान से जाने के लिए एकमात्र रास्ता था वह भी रेल्वे के द्वारा एक महीने पहले बन्द कर दिया गया और मन्त्री महोदय ने यह जवाब दे दिया कि इस डिपार्टमेन्ट से सम्बन्ध नहीं है। मैंने खुद ने जी. ए. डी. में इसको भेजा था, सम्बन्धित विभाग के द्वारा ही इसका उत्तर दिया जाना चाहिये था, वह क्यों नहीं दिया गया?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि माननीय सदस्या ने इस प्रश्न को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में भेजा था। वहां से इसको पी. डब्ल्यू. डी. में ट्रांसफर कर दिया गया यह कह कर कि पुलिया बनाने का प्रश्न है। रात में यह प्रश्न मेरे पास आया था। मेरे लिए यह सम्भव नहीं था कि मैं इसका उत्तर न देता। जो मेरे डिपार्टमेंट से सम्बन्धित है उसका मैंने उत्तर दिया है। यह हो सकता है कि कलेक्टर के पास लिखा-पढ़ी की हो, कलेक्टर ने जी. ए. डी. को लिखा हो। हमारे पास तो जी. ए. डी. ने भेजा है। हमने उत्तर दे दिया कि लेवल क्रोसिंग बनाने में हम असमर्थ हैं। इसके लिए रेल्वे से बात की जाय। रेल्वे वाले कहते हैं कि इम्पोर्टेन्ट नहीं है तो हम नहीं बनायेंगे। यदि सरकार खर्चा करने के लिए तैयार है और मेन्टीनेन्स करने के लिए तैयार है तो हम सोच सकते हैं। यह सही है कि पहले अनमेन्ड लेवल क्रोसिंग था। कल्वर्ट ९३ था उसको बन्द कर दिया।

कुमारी उमा माथुर : यह बिल्कुल गलत है कि रेल्वे ने इम्पोर्टेन्ट नहीं बताया। रेल्वे ने स्वीकार किया है कि लेवल क्रोसिंग होना चाहिए और रेल्वे ने कलेक्टर अलवर के पास एक लेटर १९-८-६३ को भेजा कि आप तीन हजार रुपये का बन्दोबस्त करिये जो इस रेल्वे क्रासिंग को बनाने के लिए चाहिए वह बना दिया जायेगा। तब से निरन्तर ग्रामवासी, दस ग्रामों का इस क्रांसिंग से सम्बन्ध है, उस एरिया से कलेक्टर और राज्य सरकार को निरंतर लिख रहे हैं, आज तक न उत्तर दिया गया और न कोई ऐक्शन लिया गया। इसलिए मैंने इसके सम्बन्धित विभाग को लिखा था और इसका उत्तर इस रूप में मिल रहा है। एक पुलिया थी जिससे पानी आता जाता रहता था, उस पुलिया से आने-जाने का काम कर लिया जाता था, वह अन-ऑथोराइज्ड काम था इसलिए रेल्वे ने वहां पर कांटे वाले तार लगा दिये हैं और आज यह स्थिति है कि खेतों में सामान पड़ा है, वह नहीं ला सकते हैं। गांव की मवेशी चरने जाती हैं, एक तरफ स्टेंड हो जाती है। कई बार एक्सीडेन्ट हो चुके हैं बहुत सी मवेशियां मर चुकी हैं। जिस विभाग से भी इसका सम्बन्ध है वह फौरन ऐक्शन ले।

श्री परसराम मदेरणा : रेल्वे से सम्बन्ध है।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल !

कोटा में डी. सी. एम. फैक्ट्री के गन्दे पानी से मवेशियों की मृत्यु

२६०. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या उद्योग मन्त्री उत्तर देने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि कोटा की डी. सी. एम. फैक्ट्री का गन्दा पानी एक नाले में डाला जाता है ?

(२) क्या यह सही है कि उस नाले के पानी से कई गांवों में मवेशी पानी पीते हैं ?

(३) क्या यह सही है कि इस फैक्ट्री के पानी के कारण इस नाले का पानी जहरीला हो गया है ?

(४) क्या यह सही है कि इस पानी के पीने से सैंकड़ों मवेशी मर चुके हैं ?

(५) अगर हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उप-मन्त्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : इस प्रश्न का सम्बन्ध जन-स्वास्थ्य विभाग से है अतः वे उनकी टर्न के दिन इसका जवाब देंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : जब यह प्रश्न जन-स्वास्थ्य विभाग से पूछते हैं तो वे कहते हैं कि इसका सम्बन्ध उद्योग विभाग से है। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में सदन में स्थगन प्रस्ताव भी आया है। इस बारे में क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

खनिज मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : इसमें टालने की बात नहीं है कल के बाद जब मेरी बारी आयेगी इसका जवाब दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : Next श्री मोहनराज !

बाली में अस्पताल भवन का निर्माण

२६१. श्री मोहनराज (बाली) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बाली जिला पाली में नये अस्पताल भवन का शिलान्यास राजस्थान के स्वर्गीय मुख्य मन्त्री श्री जय नारायणजी व्यास ने १६५२ में "बड़ के बाव" नामक भूमि पर किया था ?

(२) क्या यह सही है कि सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों की लापरवाही के फल-स्वरूप आज तक उक्त भूमि एक्वायर नहीं की जा सकी है और बाली की जनता को नये अस्पताल भवन की सुविधाओं से वन्चित रहना पड़ा है ?

(३) क्या यह सही है कि अब उक्त भूमि अधिग्रहण करने हेतु आवश्यक विज्ञप्तियां राज-पत्र में छाया हो चुकी हैं ?

(४) क्या राज्य सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए उक्त भूमि को शीघ्र ही अपने अधिकार में लेने की आज्ञा जारी करेगी ताकि भवन निर्माण का कार्य शीघ्र सम्पन्न किया जा सके ?

स्वास्थ्य-मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां।

(४) भूमि को अधिग्रहण करने के लिय कार्यवाही की जा रही है। भूमि के अधिग्रहण होते ही चिकित्सालय भवन का

(श्री दामोदरलाल व्यास)
निर्माण कार्य चतुर्थ योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किया जा सकेगा।

श्री मोहनराज : भूमि के अधिग्रहण में सरकार देरी क्यों कर रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पहले जो नोटिफिकेशन जारी किये गये थे वे हाईकोर्ट में चेलेन्ज हो गए इसलिए अब दुबारा कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मोहनराज : हाईकोर्ट से केन्सिल होने के बाद भी एक नोटिफिकेशन निकल चुका है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके बाद भी तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए प्रोवीजन नहीं होने के कारण और ६५-६६ में प्रोविजन नहीं होने के कारण इस बारे में कार्यवाही नहीं की जा सकी ।

श्री मोहनराज : अब कब तक इस सम्बन्ध में कार्य आरम्भ हो जायेगा ।

श्री दामोदरलाल व्यास : चतुर्थ योजना के किन्हीं सालों में एडजस्ट करेंगे।

श्री मोहनराज : लेकिन वहां तक भूमि को लेने का सवाल था वह तो ली जा सकती थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उसके लिए भी पैसा देना पड़ता है ।

श्री मोहनराज : पैसा तो अवार्ड होने के बाद दिया जाता है तब तक भूमि लेने की तो कार्यवाही करते ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जब इसके लिये प्रोवीजन हो जायेगा उस वक्त बाकी की सब कार्यवाही भूमि आदि के एक्वीजिशन की सब कर ली जायेगी ।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : बिना भूमि को लिये सन् ५२ में किस आधार पर और किस भूमि का शिलान्यास कर दिया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वे इस एक्वीजिशन के लिहाज से एक्वायर कर रहे हैं, इस बिना पर शिलान्यास कर दिया ।

श्री अब्दुल जब्बार : जमीन तो प्राइवेट है और आपने बिना एक्वायर किये ही शिलान्यास कर दिया यह खूब रही ।

श्री अध्यक्ष : Next ।

प्रश्न संख्या २९२

श्री दलपतसिंह ।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

(प्रश्न संख्या २९३)

श्री जयनारायण सालोदिया) !

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री मोहनराज ।

गुजरात द्वारा राजस्थान को बिजली

२९४. श्री मोहनराज (पाली) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि गुजरात राज्य ने राजस्थान को बिजली देने की बात स्वीकार कर ली है और इस सम्बन्ध में दोनों

Page No. 12

(श्री मोहनराज)
राज्यों के दरमियान कोई समझौता हो गया है ?

(२) इस समझौते के अनुसार यह बिजली किन किन स्थानों से राजस्थान को दी जायेगी व राजस्थान के कौन से क्षेत्र इससे लाभान्वित होंगे ?

(३) कुल कितनी बिजली गुजरात राज्य से राजस्थान को उपलब्ध होगी व कितने वर्षों तक यह सप्लाई जारी रहेगी ?

(४) इस योजना पर कुल कितना खर्च लगेगा ? क्या केन्द्र से भी कुछ सहायता प्राप्त होगी ?

उप मंत्री उद्योग (श्री चन्दनमल वेद) : (१) जी हां, गुजरात विद्युत् मंडल ने राजस्थान को बिजली देना स्वीकार किया है। इस सम्बन्ध में दोनों राज्यों में कोई समझौता अभी नहीं हुआ है।

(२) अभी कोई समझौता तो नहीं हुआ है किन्तु अब तक के प्रस्तावों के अनुसार यह बिजली गुजरात में बाटवा से जो अहमदाबाद के पास है, राजस्थान के उदयपुर, चितौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर जिलों में मिल सकेगी।

(३) गुजरात विद्युत् मण्डल ने यह माना है कि २००००० किलोवाट बिजली दिसम्बर १९६६ तक देता रहेगा इस। अवधि के पश्चात् अक्टूबर १९६७ तक व्यस्त घण्टों (पीक आवर्स) को छोड़कर २० मेगावाट १८ घण्टे प्रतिदिन और तत्पश्चात् अक्टूबर १९६८ तक केवल ६ घण्टे २० हजार किलोवाट उपलब्ध हो सकेगी।

(४) इस योजना की लागत (अनुमानित) डेढ़ करोड़ रुपये हैं। केन्द्र की सहायता के विषय में अभी कोई निश्चित नहीं है।

श्री मोहनराज : जब इस वक्त राजस्थान में विद्युत् की कमी है इसके बिना हमारे उद्योग-धन्धों को नुकसान हो रहा है तो फिर गुजरात से प्राप्त होने वाली बिजली के लिए शीघ्र कार्यवाही क्यों नहीं हो रहा है, इसमें देरी क्यों लग रही है ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : इसमें दो प्रश्न जुड़े हुए हैं एक तो इस बात के लिए कि जो मिनिस्ट्री ग्रॉफ इरिगेशन और पॉवर है वह इस बात पर इनसिस्ट कर रही है कि १३२ किलोवाट की जगह २२० किलोवाट की लाइन खींची जाय।

जो बिजली हमको उपलब्ध होगी वह क्या हमको हमेशा के लिए उपलब्ध होगी या नहीं—इस प्रश्न को लेकर राज्य सरकार और विद्युत मंडल विचार कर रहा है।

श्री मोहनराज : क्या गुजरात सरकार ने पालनपुर की ओर से सरप्लस बिजली जो उपलब्ध है उसको लेने के लिये राज्य सरकार के पास प्रोपोजल भेजा है ?

श्री हरिश्चन्द्र : वह मन्जूर भी हो गया है दो मेगावाट बिजली का।

श्री मोहनराज : पालनपुर से बिजली का लेना कब से प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : इस विषय में श्री राव साहब की सूचना आयी है कि उन्होंने वह स्कीम मन्जूर कर ली है। उन्होंने कहा है कि आप काम शुरू करिये लेकिन यहां जब तक इस बात की व्यवस्था न हो जाय जो धनराशि

Page No. 13

(श्री हरिश्चन्द्र)

मुझे प्लान के अन्तर्गत मिली है उससे ग्रोवर एन्ड अवव जब तक नहीं मिलेगा तब तक काम शुरू नहीं कर पायेंगे।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : यह बिजली अस्थायी तौर पर मिलेगी या स्थायी तौर पर ?

श्री हरिश्चन्द्र : स्थायी तौर पर मिलेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

चूरू का विश्रान्ति भवन

२६५. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

१. क्या यह सही है कि चूरू में सरकारी विश्रान्ति गृह (Rest House) में आम तौर से अधिकारी व अन्य अधिकृत व्यक्तियों को ठहरने के लिए स्थान नहीं मिलता क्योंकि वहां जगह कम होने के कारण यह अक्सर भरा रहता है।

२. क्या सरकार इस विश्रान्ति गृह में और कमरे बढ़ा कर इस कमी को दूर करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

३. क्या सरकार इसको डाक बंगले में परिवर्तित करने का भी इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों।

उप-मंत्री सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : १. कभी कभी विशेष परिस्थितियों में स्थानाभाव होता है।

२. वह कार्य स्वीकृत नहीं है।

३. ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री मोहरसिंह : यह जो आपको सूचना दी गई है कि कभी कभी ठहरते हैं, यह गलत सूचना प्राप्त हुई है।

प्रश्न संख्या २६६

श्री अध्यक्ष : ext श्री हरिप्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित ! कृपया आगे देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

विद्युत संकट

२६७. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(१) क्या यह सही है कि गांधी सागर बान्ध में पानी की कमी के कारण राज्य में विद्युत संकट चालू है ? यदि हां, तो इसके हल के लिये सरकार ने क्या क्या कदम उठाये हैं ?

(२) क्या सरकार को यह जानकारी मिली है कि वर्ष १९६४ में जब यह संकट पैदा हुआ था तो उसका एक कारण यह भी था कि बांध में काफी सिंचाई के लिये छोड़ दिया गया था। यदि हां, तो क्या यह विद्युत् विभाग के इन्जीनियरों की सहमति से था ?

(३) क्या यह सही है कि कोटा क्षेत्र में बिजली की कमी को दूर करने के लिये जयपुर से बिजली सप्लाई की गई और जयपुर में बिजली की कमी को दूर करने के लिये रतनगढ़ से लाइन डाली गई ?

Page No. 14

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(४) इस समय राज्य में बिजली की कितनी कमी है और उसकी पूर्ति के लिये सरकार ने क्या उपाय सोचा है ?

उप-मंत्री उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) जी हां, राज्य में बिजली की स्थिति को सुधारने के लिये जो कदम उठाये गये हैं वे इस प्रकार हैं:—

(क) चम्बल से बिजली दिये जाने वाले क्षेत्र में भाखरा की अतिरिक्त बिजली लाने के लिये रतनगढ़ से जयपुर तक १३२ के० वी० सिंगल सर्किट ट्रान्समीशन लाइन का निर्माण किया गया है ।

(ख) १००० के० डब्लू० के तीन डीजल जनरेटिंग सैट पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से खरीदकर लगाये गये ।

(ग) वर्तमान थर्मल स्टेशन (स्टीम एवं डीजल) को सम्भावित अधिकतम सीमा तक शक्ति की पूर्ति के लिये चलाया गया ।

(घ) १० मेगावाट का एक गैस-टर्बाइन सैट खरीदा गया व कोटा में चालू कर दिया गया है ।

(ङ) ६४० किलोवाट के दो डीजल जनरेटिंगसैट मैसूर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से खरीद कर लगाये गये हैं ।

(छ) १००० किलोवाट के दो व ५०० किलोवाट के ३ डीजल सैट खरीद कर प्रायोरिटी पर लगाये जा रहे हैं ।

(२) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

(३) जी हां ।

(४) स्टेटमैन्ट सदन की मेज पर रख दिये गये हैं । ऊपर बताये गये उपायों के अलावा नीचे लिखे काम और किये जा रहे हैं ।

१. २५० किलोवाट के ८ डीजल सैट लगाये जा रहे हैं ।

२. सतपुड़ा बिजली घर लगाया जा रहा है जिसमें राजस्थान का हिस्सा १०३ एम० डब्लू० है ।

३. राणा प्रतापसागर व कोटा बांध बिजली घर से चम्बल योजना के अन्तर्गत लगाये जा रहे हैं । जिसमें राजस्थान का हिस्सा ७५ एम० डब्लू० है ।

४. हिसार से जयपुर तक २२० किलोवाट की लाईन डाली जा रही है ताकि भाखरा (राईट बैंक) से ४५ एम० डब्लू० और बिजली प्राप्त कर इस्तेमाल की जा सके ।

५. राजस्थान अणु-शक्ति घर से जयपुर तक २२० के० वी० लाइन डाली जा रही है ताकि अणु-शक्ति घर की बिजली का प्रयोग किया जा सके ।

६. गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से उनके धुवन पावर हाउस की बिजली लेने की बात की गई है । इसके लिए १६० मील की १३२ किलोवाट अहमदाबाद, उदयपुर लाइन डालने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट सी० डब्लू० पी० सी० को प्लानिंग कमीशन की मंजूरी हेतु भेजी गई ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

Page No. 15

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : १९६४ में गांधी सागर में पानी की कमी हुई उससे विद्युत संकट पैदा हुआ, क्या इसका कारण यह भी था कि पानी सिंचाई के लिए ज्यादा मात्रा में छोड़ दिया गया ? क्या सरकार इस बात की जांच करवायेगी कि कितना पानी छोड़ा गया ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : सिंचाई के लिए खर्च हुआ या नहीं, यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन यह बात जरूर है कि पानी जितना बरसना चाहिए था उतना नहीं बरसा। रोजाना से पानी कम बरसा, केचमेंट एरिया में बारिश की कमी हुई इसलिए बान्ध में पानी कम आया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : १९६४ में एक्सैस पानी सोईल इरिगेशन के लिए छोड़ा गया या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह तो मैं नहीं कह सकता। एक्सैस ड्रेन जरूर हुआ है इन्डस्ट्रिएलाइजेशन का टेम्पो उस समय बना था That is one of the reason.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस संबन्ध में पानी का संकट क्यों हुआ इस बारे में जाच कराई क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसमें जांच करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक्सेस ड्रेन हुआ तो क्या हुआ ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने निवेदन किया इन्डस्ट्रिअलाइजेशन का टेम्पो उन दिनों बना था थोड़ा उन्होंने ज्यादा खींचा, लेकिन फिर पानी बरसा नहीं दो साल से लगातार बरसात की कमी हुई इस वजह से भी पानी कम आया।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : सन् ६४ में गांधी सागर में पानी कम क्यों आया, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने जांच कराई थी क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह सूचना मेरे पास तो नहीं है। केन्द्रीय सरकार के पास होगी, अगर उसने कराई है तो।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : यह प्रश्न तो सप्लाई और डिमाण्ड का है। क्या मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में प्रकाश डाल सकते हैं कि डिजाइनिंग डिफेक्टिव है या क्या बात है ?

श्री हरिश्चन्द्र : डिजाइन डिफेक्टिव नहीं है। कुछ इस तरह की साइकिल्स आती हैं बारिश नहीं होने की। आप जानते हैं कि चम्बल का एरिया कैचमेन्ट का सारा मानसून पर निर्भर करता है और मानसून दो साल से फेल हो रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि ६३ जितनी ही ६४ में बारिश हुई है ? एवरेज रेन-फाल ६३-६४ का एक ही है। पिछली बार भी आपने सदन में यही आंकड़े दिये थे। यह जरूर कहा था कि ६४ में धीरे धीरे बरसा और काफी पानी रास्ते में ही ड्राई हो गया था।

श्री हरिश्चन्द्र : यह तो आप भी जानते हैं कि लगातार बारिश होने के बाद ही कैचमेन्ट भरता है। अगर पानी की मिकदार वही रहे, पर धीरे धीरे बरसे तो पानी रिज़र्वेयर में नहीं आता। यह

Page No. 16

(श्री हरिश्चन्द्र)
तो आप भी जानते हैं कि चम्बल की हिस्टोरीकल बैक-ग्राउन्ड रही है कि वहां मानसून तीन साल तक भी लगातार फेल हो जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस बात को आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते है ?

श्री हरिश्चन्द्र: मैंने कहा यूजुअली ऐसी साइकिल आती रहती है। पहले भी करीब साठ-सत्तर साल पहले पानी की कमी हुई थी उस एरिया में और उसके बाद मेरी जिन्दगी में तो यह पहला मौका है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जब आपको यह मालूम था कि ऐसी साइकिल आती रहती हैं तो चम्बल प्रोजेक्ट के चालू करने से पहले इसकी सम्भावना पर विचार व्यक्त किया गया था या नहीं कि दो-तीन वर्ष तक इस एरिया में ऐसी साइकल आती है और दो-तीन वर्ष तक वर्षा नहीं होती है ?

श्री हरिश्चन्द्र : जरूर किया गया होगा विचार।

श्री भैरोंसिंह : तो इसका आल्टर्नेटिव क्या सजेस्ट किया गया ?

श्री हरिश्चन्द्र : क्या सजेस्ट किया, करने का सवाल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आप कहते हैं कि निश्चित रूप से इस तरह से पानी की कमी की साईकिल आती है तो इसकी सम्भावना को ध्यान में रखकर कोई व्यवस्था भी तो सुझाई गई होगी ? इसका आल्टर्नेट प्रोपोजल भी तो कोई बताया होगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : यहां प्रोपोजल का प्रश्न नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : कैसे नहीं है ? पानी जब नहीं आवेगा तो बिजली का उत्पादन कम होगा, बिजली का उत्पादन कम होगा तो इन्डस्ट्रीज वगैरह ठप्प हो जाती हैं।

श्री हरिश्चन्द्र: इस तरह की साइकिल सिर्फ इन्डिया में ही नहीं और जगह भी आती हैं। आपने अखबारों में पढ़ा होगा अमेरिका में भी कुछ हिस्सों में पानी नहीं बरसा और आदमी तड़प रहे हैं। वहां पर साइकिल कभी घूम कर आती हैं। तो हमारे देश में भी ऐसी साइकिल आती है, यह मेरा मानना है। तो इसके लिए सी. पी. डब्ल्यू. डी. ने जरूर सोचा होगा, देखा होगा।

श्री भैरोंसिंह : देखा होगा तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह तो कह दिया कि देखा होगा पर जब ऐसी साइकिल आवेगी और बिजली उत्पादन में कमी होगी तो किस प्रकार से उस कमी की पूर्ति होगी इसका भी विचार किया गया है ?

श्री हरिश्चन्द्र : सी. पी. डब्ल्यू. डी. ने इस बात को जरूर देखा होगा। राजस्थान में जो इस वक्त नदियां हैं वे मानसून पर डिपेण्ड करती हैं और हम उस हाइडल पर डिपेण्ड हैं। एक तरफ भाखरा है और एक तरफ चम्बल है। मेरी मान्यता है कि इसके लिये सक्षम टरबाईन होने चाहिये जो ऐसी सूरत में बेस लोड ले सकें। यह इसकी परमानेन्ट रेमिडी होगी। फिर जो एटोमिक पावर प्लान्ट होगा वह भी बेस लोड प्रोवाइड करेगा।

श्री भैरोंसिंह: क्या यह भी मालूम है कि भाखरा में भी पानी का लेवल नीचे जा रहा है, और इस प्रकार का संकेत भारत सरकार ने कर दिया है।

श्री हरिश्चन्द्र : भाखरा में थोड़ी स्थिति दूसरी है। माननीय सदस्य जानते होंगे कि वहां पानी बर्फ का भी आता है और इस तरह वहां पेरिनियल रिवर हैं। और वहां पर ज्यादातर फ्लड में आता है और वर्षा का भी आता है पानी इसलिये भाखरा इज आन ए साउन्डर फुटिंग देन चम्बल।

चम्बल डिपेन्ड्स आन मानसून। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि भाखरा में भी कमी पड़ रही थी और इस साल अब बर्फ अच्छी पड़ गई है इसलिये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लेवल फिर राइज़ होगा।

श्री भैरोंसिंह : इस समय लेवल डाउन गया न।

श्री हरिश्चन्द्र : इस साल फिर लेवल बढ़ गया क्योंकि ऊपर काफी बरफ गिरी है।

श्रीमति लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि जांच कमीशन बिठाया जावेगा कि बरसात क्यों नहीं होती है?

श्री हरिश्चन्द्र : इसके लिये मैं कैसे बिठाऊं?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने यह बात स्वीकार की है कि वर्षा कमी का मुख्य कारण तो है ही, पर बाद में पानी कम होने का एक कारण यह भी है कि पहले पानी ज्यादा छोड़ दिया गया था और बाद में वर्षा नहीं हुई। इसलिये पानी कम हो गया। इसके लिये क्या इस प्रकार की कोई स्थायी व्यवस्था इन्जीनियरों ने मिलकर की है कि किस महिने में कितना पानी छोड़ा जाना चाहिये। इसको सेफ गार्ड करने के लिये क्या कोई फार्मूला बनाया है इस प्रकार का?

श्री हरिश्चन्द्र : सी. पी. डब्ल्यू. डी से मिलकर यह व्यवस्था कर दी गई है कि आगे जाकर इस तरह की स्थिति पैदा न हो। फिर पानी ज्यादा ड्रा किया गया, इसके लिये तो इरिगेशन मिनिस्टर बता सकेंगे, बाकी इन्डस्ट्रियल कन्जन्पशन के हिसाब से भी पावर ज्यादा ड्रा की गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमारी जानकारी यह है कि इरिगेशन परपज़ के लिये ज्यादा पानी निकाला गया।

श्री अध्यक्ष : कोई भी कारण हो, डिजाइन के हिसाब से भी शायद पहली साल पूरा भरने नहीं दिया हो; पर सदन ओवर आल यह जानना चाहेगा कि भविष्य में इस तरह की बात की पुनरावृत्ति न हो इसको रोकने के लिए राज्य सरकार ने क्या व्यवस्था की है।

श्री हरिश्चन्द्र: इस तरह की हमने एक कमेटी बनाई है जिसमें इरिगेशन के चीफ इन्जीनियर, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चीफ इन्जीनियर, मध्यप्रदेश के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चीफ इन्जीनियर और इरिगेशन के चीफ इन्जीनियर और सी. पी. डब्ल्यू. डी. के गाइडेन्स में एक ऐसी एनुअल टेबल बनायेंगे कि हर मास किस हिसाब से वाटर डिस्चार्ज होगा।

Page No. 18

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

ब्यावर-लाम्बिया सड़क निर्माण कार्य में विलम्ब ।

२९८. श्री मांगीलाल (रायपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे:—

(१) ब्यावर से लाम्बिया की सड़क के निर्माण की स्वीकृति कब हुई ?

(२) उपरोक्त सड़क का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ और कितने मील तक हुआ ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त सड़क का जो चार मील का हिस्सा अजमेर जिले में आता है उसका निर्माण कार्य पांच वर्ष पहले शुरू होने पर भी अभी तक भी पूरा नहीं हुआ ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त सड़क का जो हिस्सा पाली जिले में है उसका निर्माण कार्य बहुत देरी से प्रारम्भ हुआ और उसकी प्रगति बहुत धीमी है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(५) उपरोक्त सड़क के निर्माण में हुए विलम्ब के लिए कौन उत्तरदायी है और सरकार उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री परसराम मदेरणा) : (१) ब्यावर से लाम्बिया रोड की स्वीकृति वर्ष १९६१ में हुई है।

(२) इस सड़क का कार्य १९६०-६१ में आरम्भ हुआ है और अब तक पाली जिले में लगभग १२ मील ग्रेवल की सड़क बन चुकी है, अजमेर खण्ड में चार मील ३ फर्लांग का डामर व क्रास ड्रेनेज के कार्य को छोड़ कर सड़क का काम पूर्ण हो चुका है।

(३) सड़क का कार्य पूर्ण हो चुका है। डामर कार्य तथा क्रॉस ड्रेनेज का काम प्रगति पर है ।

(४) जी नहीं, कार्य योजनानुसार हो रहा है।

(५) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मांगीलाल : यह कार्य पांच साल से चालू है अब कब तक यह पूरा हो जावेगा ?

श्री परसराम मदेरणा : दो मील तो नहीं बना रहे हैं। पर जितना ईयरवाइज़ अलॉटमेन्ट है वैसा ही बना रहे है। तीसरी योजना में फेजिंग कर दिया गया था, बजट में जितना अलॉटमेंट था उसी के अनुसार काम लिया है।

श्री मांगीलाल : मैं पूछ रहा हूं जो बाकी है, वह कब तक पूरा कर दिया जावेगा ?

श्री परसराम मदेरणा : डामर का काम तो ६६ में पूरा हो गया और दूसरा जो काम है करीब १२ मील है बन चुका है; पांच मील से ९ मील का काम कम्प्लीट हो चुका है, २० से २२ का काम हाथ में लिया नहीं गया है और, अध्यक्ष महोदय, अगले साल प्रावधान नहीं है इसलिये इसे हाथ में लिया नहीं जा सकेगा ।

श्री मांगीलाल : प्लान में जैसा है उस हिसाब से क्या यह ठीक है ?

श्री परसराम मदेरणा : प्लान में देखिये कि दोनों अलग अलग है। ब्यावर से अजमेर

(श्री परसराम मदेरणा)
जोधपुर की बाउन्ड्री तक एक लाख एक हजार का है, जिसमें ५० हजार तीसरी योजना में ५० हजार चौथी योजना में है, तीसरी योजना तक का काम पूरा करीब करीब कर लिया है। कुल में २६० हजार खर्च होना था जिसमें से १३१ हजार तीसरी योजना में था और १२६ हजार चौथी में। फिर भी काफी वर्क लिया है अब दो मील ऐसी सड़क रह जाती है जो नहीं ले सकेंगे कम से कम अगले वर्ष तक।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत।

विकास कार्यों के लिए तखमीने की आवश्यकता

२६६. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि विकास कार्यों हेतु पंचायत समिति से अनुदान व ऋण स्वीकृत करने से पहले उस कार्य का टेक्निकल एक्सपर्ट द्वारा तखमीना बनाया जाना जरूरी है?

पंचायत मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): जी हां।

श्री तेजाराम गहलोत : क्या मंत्री महोदय को पता है कि पाली जिले में बहुत सी पंचायत समितियों में विकास कार्यों के लिए बिना तखमीने बनाये ही ऋण दे दिया जाता है और जिसकी वजह से न तो पैसे का सदुपयोग होता है और न पैसे का वेरीफिकेशन होता है और जितने भी काम होते हैं वे पूरे नहीं होते?

श्री दामोदरलाल व्यास : पाली जिले में कहीं हुआ हो तो मेरी जानकारी में नहीं है। माननीय सदस्य की अगर जानकारी में है तो मुझे लिख कर भेज दें तो मैं इन्क्वायरी कर लूंगा।

अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

जामसर ग्राम के निवासियों को बिजली

३००. श्री भीमसेन (लूनकरणसर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि बीकानेर से जामसर तक विद्युत् लाइन बिछाई जा चुकी है? अगर हां, तो उक्त गांव के निवासियों तथा रेल्वे स्टेशन पर बिजली कनेक्शन क्यों नहीं दिये जा रहे हैं?

उप-मंत्री विद्युत् (श्री चन्दनमल वैद): जी हां, बीकानेर से जामसर की लाइन १५-१२-६३ को चालू कर दी गई थी। कनेक्शन देने के लिए कभी इन्कार भी नहीं किया गया।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, वहां तो कई बार दरख्वास्तें दीं लेकिन इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड कह रहा है कि गांव के लिए बिजली नहीं दे रहे हैं।

श्री चंदनमल वैद : स्थिति यह है कि जहां लोग बिजली लेना चाहते हैं वह लाइन से पौना मील दूर है और बिजली विभाग के जो नियम हैं उनके अनुसार पौन मील लाइन खींची जानी है और उसका जो खर्चा आयेगा उसके अनुसार गारन्टी देना जरूरी है और जो भी कनेक्शन लेना चाहते हैं वह देते नहीं हैं इसलिए वह लाइन खींचने में असमर्थ है।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): एग्रीकल्चर लोड के लिए जहां मांग रहे है वह

Page No. 20

(श्री मोतीलाल चौधरी)

भी नहीं दे रहे हैं और गारन्टी देने के बाद भी नहीं दे रहे हैं।

श्री भीमसेन : वहां की मांग को देखते हुए क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वहां तक लाइन ले जायेगा ?

श्री चंदनमल वैद : हां, इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है कि गांव तक लाइन पहुँचा दी जाए और इसके लिए यदि धनराशि उपलब्ध हुई तो इसके ऊपर विचार किया जा सकता है कि बिजली की लाइन वहां तक दे दी जाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहर बाजार, जयपुर) वहां तक बिजली की लाइन नहीं पहुँचाने का एक कारण यह है कि खर्चा ज्यादा पड़ता है तो आपके जो पोल्स है जिनकी कॉस्ट ज्यादा हैं उसकी जगह लकड़ी के पोल्स लगा दीजिए इससे खर्चा कम आयेगा।

विद्युत मन्त्री(श्री हरिश्चन्द्र): लकड़ी के पोल्स में भी खर्चा उतना ही होता है। क्योंकि वह यहां उपलब्ध नहीं हैं। उनके ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में और सब में मिलाकर उतना ही खर्चा आता है। यह सीमेन्ट के पोल हम खुद ही बना रहे हैं हमारे वर्कशाप में।

श्री मोतीलाल चौधरी : क्या यह सही है कि बिजली विभाग के पास एग्रीकल्चुरल लोड देने के सम्बन्ध में कोई एक्सपर्ट्स नहीं है, कोई सेन्शन नहीं है और एग्रीकल्चुरल लोड देने के लिए वह चिंतित भी नहीं है। वह कहते है कि इस बारे में सोचने के लिए भी हम तैयार नहीं हैं।

श्री हरिश्चंद्र : यह कहना कि चिंतित नहीं हैं, यह तो मैं समझता हूं कि ठीक बात नजर नहीं आती। चिंतित नहीं होते तो आज ६१०० कुओं पर बिजली कैसे पहुँच जाती ? यह आप कह सकते हैं कि मांग राजस्थान के अन्दर बिजली की बहुत ज्यादा है, यह भी कह सकते है कि मांग इतनी है कि हर गांव के हर कुओं के ऊपर बिजली लेना चाहते हैं अब उस डिमाण्ड को हम फुलफिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास उतनी धनराशि नहीं है। पिछली साल हमको करीब २॥ करोड़ रुपये का प्रोग्राम भेजा था रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए उसमें से १॥ करोड़ रुपया मिला। इसलिए जो कुछ मिला उसका हमने काम किया और जैसा कि आपको बताया गया ६१०० कुओं के ऊपर हमने बिजली पहुँचाई। जहां तक बिजली कुओं तक पहुँचाने का ताल्लुक है हम उसके लिए बहुत उत्सुक हैं कि वहां बिजली पहुँचायें लेकिन हम उसी हिसाब से वह काम कर सकते है जितनी कि हमारे पास धनराशि है।

श्री मोतीलाल चौधरी : यह भी गलत है। बिजली की लाइन गयी हुई है। कुए हैं, आपका प्रोग्राम है उसके अनुसार मांग रहे हैं, एप्लीकेशन पड़ी हैं सब डिस्ट्रिक्ट का यह हाल है एक का ही नहीं है, फिर भी नहीं दे रहे हैं इसका कारण यह है कि एग्रीकल्चुरल लोड देने के लिए उत्सुक नहीं हैं। क्यों नहीं है ? यह कारण तो मुझे मालूम नहीं है। एग्रीकल्चरल लोड राजस्थान के अन्दर सारे लोड का ५ परसेन्ट भी नहीं है। बाकी लाइन भी खींच दी है, इनवेस्टमेंट भी हो गया है लेकिन देते नहीं हैं।

Page No. 21

श्री हरिश्चन्द्र : १ परसेन्ट से कहीं ऊपर है। We have now reached some where in the neighbourhood of over three percent.

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत !

टी० बी० क्लिनिक के लिए स्वीकृत स्टाफ

३०१. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य के टी० बी० क्लिनिक्स के लिये कितना स्टाफ केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित है ?

(२) क्या यह सही है कि राज्य के ग्यारह टी० बी० क्लिनिकों में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित स्टाफ से इस समय स्टाफ अधिक लगा हुआ है ?

(३) यदि हां, तो यह क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि मेडिकल विभाग ने सरकार को रिपोर्ट दी है कि यदि इस सरप्लस स्टाफ की उचित और अनुमोदित तरीकों से नियुक्ति की जाये तो इसी स्टाफ से राज्य में दस टी० बी० क्लिनिक और खोले जा सकते हैं ?

(५) यदि हां, तो सरकार ने क्या विचार किया है ?

(६) यह रिपोर्ट सरकार के पास कब आई ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास):

(१) अनुमोदित स्टाफ की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां।

(३) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ११ टी० बी० क्लिनिक खोले गये थे उस समय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित स्टाफ ही राजस्थान सरकार ने इन टी० बी० क्लिनिक के लिए मंजूर किया था। अब पिछले दो साल में अनुभव होने पर यह पाया गया कि अनुमोदित स्टाफ कम होना चाहिए। भारत सरकार के रिवाईज्ड पैटर्न की सिफारिश की राजस्थान सरकार ने मान कर रिवाइज्ड अनुमोदित स्टाफ ही देने का निर्णय लिया है।

(४) जी हां, केवल ७ टी० बी० क्लिनिक खोली जा सकती हैं।

(५) जी हां, सरकार इस विषय में विचार कर रही है स्वीकृति नये बजट से लागू होगी।

(६) तारीख २७-११-६५ को।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी का उत्तर राज्य के मिस मेनेजमेण्ट का एक आदर्श नमूना है। इधर तो राज्य सरकार कहती है कि हमारे पास स्टाफ ट्रेण्ड नहीं है, नर्सेस नहीं हैं, डाक्टर नहीं हैं कम्पाउन्डर्स नहीं हैं। जहां जरूरत है वहां स्टाफ भेज नहीं सकते और इधर इतना बेकार स्टाफ है कि जिससे केवल ७ टी० बी० क्लिनिक खोले जा सकते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो मैंने अर्ज कर दिया है, ७ टी० बी० क्लिनिक नये

Page No. 22

(श्री दामोदरलाल व्यास)

बजट के अन्दर खोल दिये जाने के लिए तय कर दिया गया है और वह खुल जायेंगे और पुराना स्टाफ भी भारत सरकार ने प्रेस्क्राइब किया था कोई राजस्थान सरकार ने तो किया नहीं था। अभी दिसम्बर, ६५ में भेजा कि दूसरा पैटर्न लगा दिया जाये इससे स्टाफ में जो कमी होगी उससे ७ नये क्लिनिक खुल जायेंगे। इसमें इन-एफीशियेन्सी की बात नहीं हैं, और रोज तो मैं मन्जूरी नहीं करूंगा कि वाकई गलती हुई है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंण्डावत : यह कब तक खुल जायेंगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि नये बजट के लागू होने तक।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

चूरू-भालेरी सड़क निर्माण में आई भूमि का मुआवजा

३०२. **श्री मोहरसिंह (चूरू)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चूरू से भालेरी सड़क निर्माण कब शुरू हुआ था और कब खत्म होगा ?

(२) इस सड़क के निर्माण में अब तक कितना रुपया खर्च हुआ ?

(३) क्या यह सही है कि यह सड़क चूरू से घटेल तक ६ मील तक टूट फूट चुकी है ?

(४) क्या यह सही है कि अभी तक चार मील की दूरी में इस पर तारकोल नहीं डाला गया है ?

(५) क्या इस सड़क के लिये ली गई भूमि का मुआवजा किसानों को दिया गया है ? यदि हां, तो कितना और कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री परसराम मदेरणा) : (१) सड़क निर्माण कार्य १९५४-५५ में आरम्भ हुआ था सड़क कार्य योजनानुसार पूर्ण हो चुका है। केवल सुधार कार्य प्रगति पर है।

(२) ७,६७,३५४) रु० खर्च हुआ है।

(३) सड़क की मरम्मत करा दी गई है।

(४) कार्य प्रगति पर है।

(५) जी नहीं, राजस्व विभाग से अवार्ड प्राप्त न होने के कारण मुआवजा नहीं दिया जा सका है।

श्री मोहरसिंह : राजस्व विभाग को अवार्ड प्राप्त करने के लिये कब लिखा गया था ?

श्री परसराम मदेरणा : यह तारीख उपलब्ध नहीं हो सकी है, हालांकि मैंने कोशिश भी की थी।

श्री मोहरसिंह : कितने वर्ष हो गए ?

श्री परसराम मदेरणा : वह कल ही कोशिश की थी। एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर के पास डेट नहीं थी इसलिए इस इन्फोर्मेशन के अभाव में मैंने मुनासिब नहीं समझा कि इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सके।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इस सड़क का निर्माण हुआ तो लैण्ड एक्वी-

(श्री भैरोंसिंह)
जीशन की कार्यवाही खत्म होकर राज्य सरकार ने निर्माण कार्य किया या पहले हो ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने कहा कि लैण्ड एक्वीजीशन की कार्यवाही अभी रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के पास जेरेतजवीज है इसलिए....

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न पी० डब्ल्यू० डी० से है। मेरा प्रश्न यह है कि आपने सड़क निर्माण करने के लिए इस भूमि पर आपने अधिकार प्राप्त किया वह लैण्ड एक्वीजीशन की कार्यवाही समाप्त होने से पूर्व किया या बाद में ?

श्री परसराम मदेरणा : पहले किया।

श्री भैरोंसिंह : आपको क्या अधिकार रखा दूसरे की जमीन पर इस तरह से अधिकार प्राप्त करने का ?

श्री परसराम मदेरणा : राजस्व विभाग को हमने लिखा है कि आप एक्वीजीशन की प्रोसीडिंग्स चालू करके उन्हें मुआवजा दीजिए। अब राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि ६ नये एक्वीजीशन ऑफिसर्स मुकर्रर किये जायें और पी० डब्ल्यू० डी० ने रेवेन्यू बोर्ड को लिखा....

श्री भैरोंसिंह : मेरा क्वेश्चन यह नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : बीकानेर के लिए भी अलग एक्वीजीशन ऑफिसर नियुक्त कर दिया है और इस बारे में सदन में काफी चर्चा हो चुकी है। माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे और राज्य सरकार भी जागरुक है कि ज्यादा से ज्यादा सतर्कता बरत कर जहां तक हो सके अधिकार करने से पहले मुआवजा मिले और समय पर मिले।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह तो एक्वीजीशन से पहले ही सड़क बना ली ?

श्री अध्यक्ष : यह तो हमेशा ही करते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप जमीन को एक्वायर करने के बाद में मुआवजा दीजिए और फिर अपना काम कीजिए। इसका क्या मतलब कि एक्वीजीशन नहीं हो और गवर्नमेंट अपनी चीज बना ले ट्रेस पास करके....

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह सही है। वैसे नार्मेली स्पीकिंग तो एक्वीजीशन प्रोसिडिंग्स पहले हो जानी चाहिए उसके बाद में सड़क बननी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन अगर उस कन्वेन्शन को फालो करने लगे तो मैं समझता हूँ कि आपका काम बहुत रुक जायेगा। It will not be possible.

श्री अध्यक्ष : एक्वीजीशन का काम जल्दी होने लग जायेगा। काम रुके या नहीं रुके लोगों के जो अधिकार हैं उनका हनन नहीं होना चाहिए। उनका हनन होता है इसलिए कहना पड़ता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह नहीं है कि आप लोगों के अधिकारों का एन्क्रोचमेंट कर के पहले अपना काम करलें। आप कानून को सरल बनाइये, स्पीडी बनाइये उसमें किस तरह से तरमीन की जा सकती है इस पर सोचें। यह कोई तरीका नहीं है कि चाहे जिसकी जमीन पर कब्जा कर लें।

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसे ही कन्सेन्ट से भी काम होते हैं।

Page No. 24

श्री अध्यक्ष : तो फिर प्रश्न नहीं आते।

श्री हरिश्चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्यों को मालूम हो कि ऐसी जगहों पर जहां........

श्री अध्यक्ष : यह क्या कम है, और तो न मालूम कितनी बकाया होगी। मुझे खेद तो इस बात का है कि यह सरकार अभी भी इसकी गम्भीरता को महसूस नहीं करती है और यह कहती जा रही है कि हम काम न करें तो काम ही न हो। इसका मतलब है कि जब तक हम इल्लीगल काम न करें काम ही न हो।

(विरोधी पक्ष की ओर से हियर-हियर की आवाजें)

मैं कहता हूं कि आप जितना स्टाफ के लिए सेंक्शन करते हैं उतना ही एक्वीजिशन के लिए भी सेंक्शन कीजिए। लोगों को बुनियादी अधिकार मिले हुए हैं संविधान के अन्दर। हमारे कानून कायदे हैं। अगर उनका पालन सरकार ही नहीं करेगी तो कौन करेगा ?

(विरोधी पक्ष की ओर से हियर-हियर की आवाजें)

श्री जुझारसिंह ।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत के सदन के नेता के स्थान पर बैठ कर योजना मंत्री, श्री मथुरादास माथुर से बात करने पर)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह मोहनलालजी सुखाड़िया आज महिला के रूप में बैठे हैं क्या ?

सांगोद अस्पताल

३०३. **श्री जुझारसिंह (चेचट)** : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) सांगोद कस्बे की आबादी व क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए क्या सरकार सांगोद अस्पताल में मेटरनिटी वार्ड खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(२) सांगोद अस्पताल में अब तक कितने बेड्स हैं ? क्या सरकार जन संख्या के अनुपात में इनकी संख्या में भी वृद्धि करेगी ? यदि हां, तो कब तक व कितनी ?

(३) सांगोद अस्पताल में मरीजों के लिये रसोई घर का प्रबन्ध कब तक किया जा सकेगा ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास):

(१) जी नहीं।

(२) सांगोद अस्पताल में ६ रोग शैयाएं स्वीकृत हैं। सांगोद कस्बे की जन संख्या १९६१ की जन गणना के अनुसार ७१७५ है एवं इस अस्पताल में गत वर्ष इनडोर मरीजों की औसत संख्या १-३ है।

(३) रसोई घर का निर्माण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हो सकेगा।

श्री जुझारसिंह : सुनाई नहीं आया, दुबारा बताइए।

श्री दामोदरलाल व्यास : दुबारा लीजिए

(१) जी नहीं।

(२) सांगोद अस्पताल में ६ रोग शैयाएं स्वीकृत हैं। सांगोद कस्बे की जन संख्या १९६१ की जनगणना के अनुसार ७१७५ है एवं इस हस्पताल में गत वर्ष इनडोर मरीजों की संख्या १.३ है।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(३) रसोई घर का निर्माण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हो सकेगा ?

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): मेटर्निटी वार्ड खोलने में कितना खर्चा आएगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह अलग प्रश्न है।

श्री जुझारसिंह : यह छः बैड जो अस्पताल में हैं वे तो पहले के हैं या स्टेट के मर्जर के बाद के ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं तो आपको मौजूदा स्थिति बता रहा हूं।

श्री जुझारसिंह : यह छः बैड तो कोटा स्टेट के टाइम के हैं। वहां पर बैड ही कम हैं इसलिए मरीज भी कम आते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मरीजों की संख्या मैंने बताई ना कि १.२ परसेंट मरीजों की औसत संख्या रहती है।

श्री अध्यक्ष : श्री अमरसिंह।

पालू—सांभर सड़क की मरम्मत

३०४. **श्री अमरसिंह** (दूदू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि अजमेर-जयपुर सड़क पर पालू से सांभर तक पुरानी सड़क के निशान मय पुलियाओं व डाक बंगलों के आज भी मौजूद हैं ?

(२) इसका जीर्णोद्धार चतुर्थ योजना में सम्मिलित कर लेने में क्या २ दिक्कतें हैं ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां।

(२) चतुर्थ योजना का क्या रूप होगा अभी तक निश्चित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण।

श्री जयनारायण सालोदिया : एक प्रश्न मेरा पहले का भी है।

श्री अध्यक्ष : वह भी आएगा। पहले तो इसे ले लें।

उद्योग चलाने की योजना

३०५. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या राजकीय उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या टोंक शहर में सरकार द्वारा कोई उद्योग चलाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

(२) क्या सरकार के ध्यान में है कि इस शहर के लोग बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं ?

राजकीय उद्योग मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग दो में मैंने पूछा है कि इस शहर के अन्दर बेरोजगारी है और माननीय मंत्रीजी जबाव देते हैं कि प्रश्न नहीं उठता। इसका क्या मतलब है ? क्या सरकार यह महसूस नहीं करती है कि वहां पर लोग बेरोजगार हैं और उनकी बेरोजगारी को मिटाने के लिए इंडस्ट्री खोली जाय। यह प्रश्न नहीं उठता का क्या मतलब ?

श्री मथुरादास माथुर : बेरोजगारी हल करने के कई तरीके हैं। सरकार के राजकीय उद्योग ही नहीं हैं....

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : यह भी एक तरीका है।

श्री मथुरादास माथुर : यह तरीका भी हो सकता है लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या टोंक शहर में सरकार द्वारा कोई उद्योग चलाने की योजना है, तो मैंने कहा कि जी नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : बेरोजगारी मिटाने के जो दूसरे तरीके हैं उन तरीकों में से सरकार ने कौन २ से तरीके अपनाए हैं? क्या सरकार ने सर्वे कराया है कि वहां कितने लोग बेकार हैं?

श्री मथुरादास माथुर : वह अलग प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या कभी सरकार ने यह सर्वे कराया है कि टोंक डिस्ट्रिक्ट में कौन २ सी इण्डस्ट्री पनप सकती हैं?

श्री मथुरादास माथुर : इसके लिए मैं निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता, लेकिन जब सारे राजस्थान का सर्वे कराया गया है तो उसमें टोंक भी शामिल होगा ही। आप इसके लिए अलग से प्रश्न पूछें, मैं आपको सब डिटेल्स बता दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या आपने इस बात की जानकारी की है कि टोंक में इंडस्ट्रियल पोइन्ट ऑफ व्यू से यह पोटेंशियलिटी है और यहां इस चीज़ की इंडस्ट्री लग सकती है?

श्री मथुरादास माथुर : आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में कह रहे हैं। यहां प्रश्न यह है कि स्टेट इन्टरप्राइजेज के तहत कोई इण्डस्ट्री लगाने की योजना है, तो मैंने कहा कि जी नहीं। बाकी और बातों के लिए आप अलग से प्रश्न पूछिए।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या वहां इंडस्ट्रियल एस्टेट कायम किया गया है?

(कोई उत्तर नहीं)

श्री अध्यक्ष : श्री हीराभाई।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री अब्दुलजब्बार।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : नम्बर एक।

एक माननीय सदस्य : यह नम्बर एक क्या है?

टोंक और निम्बाहेड़ा में इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स लगाने सम्बन्धी कार्य

२८०. **श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि टोंक और निम्बाहेड़ा में इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स लगाये जाने थे और क्या यह भी सही है कि उन्हें आर्थिक अभाव में रोका गया है?

(२) क्या यह भी सही है कि अब सरकार तुरन्त अपने पूर्व निर्णय को कार्य रूप में परिणित करने जा रही है? यदि हां, तो कब तक?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) जी हां। मगर यह सही नहीं है कि केवल आर्थिक अभाव के कारण इनको रोका गया है।

(२) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री अब्दुलजब्बार : तो क्या कारण है यहां इन्डस्ट्रियल एस्टेट नहीं लगाए जाने का ?

श्री चन्दनमल वैद : सन् १९६२ में सरकार ने जितने इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनाए उनका पूरा उपयोग नहीं हुआ और वहां पर बहुत से शेड्स खाली हैं, इसलिए इस स्कीम को ड्रोप कर दिया गया है।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बने हुए हैं उनमें भी कोई शेड्स अभी तक खाली हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : जो हां, कई जगह शेड्स खाली हैं।

श्री अब्दुलजब्बार : दूसरी जगह शेड्स खाली रहने से ही यह अनुमान कैसे लगा लिया गया कि अगर टोंक और निम्बाहेड़ा में इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स कायम की गई तो वहां पर भी शेड्स खाली रहेंगे ?

श्री चन्दनमल वैद : एक बार अनुभव कर लिया गया तो फिर सब जगहों पर अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए यह निर्णय लिया गया है कि अगर कोई व्यवसायी असिस्टेड इन्डस्ट्रियल एस्टेट बनाना चाहे तो उनको सरकार सहायता देने के लिए तैयार है। अगर कहीं पर इन्डस्ट्रियल एस्टेट बनाना चाहें तो व्यवसायी सरकार से सहायता प्राप्त कर असिस्टेड इन्डस्ट्रियल एस्टेट बना सकते हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : क्या सरकार ने यह तय किया है कि जो इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स में शेड्स हैं उनको किराये पर न देकर हायर परचेज पर दें।

श्री चन्दनमल वैद : जी हां, शेड्स को लेने के दो तरीके हैं। एक किराये का और दूसरा हायर परचेज का। अभी तक जितनी इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स चल रही हैं सब किराये पर चल रही हैं। हायर परचेज की व्यवस्था करने का अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री मोतीलाल चौधरी : क्या जयपुर इन्डस्ट्रियल एस्टेट में हायर परचेज पर देना शुरू कर दिया है ?

श्री चन्दनमल वैद : हमारे नियमों में यह व्यवस्था जरूर है कि अगर कोई हायर परचेज पर लेना चाहे तो ले सकता है।

श्री अब्दुलजब्बार : जो इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स आपने खोले हैं और उनमें शेड खाली रह जाने से आपने टोंक और निम्बाहेड़ा में भी इन्डस्ट्रियल एस्टेट नहीं खोलने का जो आपने निर्णय लिया है तो इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि टोंक डिस्ट्रिक्ट में इन्डस्ट्री नाम की कोई चीज अभी तक नहीं है। अगर वहां पर इन्डस्ट्रियल एस्टेट कायम होता है तो लोग वहां पर इन्डस्ट्री लगाने के लिए आगे आयेंगे जिससे वहां के लोगों की बेरोजगारी भी दूर होगी।

श्री चन्दनमल वैद : मैं अर्ज कर चुका हूं कि अगर कोई व्यवसायी कहीं पर असिस्टेड

(श्री चन्दनमल बैद)

इन्डस्ट्रियल एस्टेट खोलना चाहे तो सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा।

प्रश्न संख्या २८३

श्री अध्यक्ष : श्री मजलिस खां।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २८५

श्री मथुरेशबिहारी माथुर।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २९२

श्री दलपतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री जयनारायण सालोदिया।

एस० एम० एस० अस्पताल, जयपुर के बरामदों में पंखों की व्यवस्था

२९३. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर के बन्द बरामदों में जहां मरीजों को घण्टों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, एक भी पंखा नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार मरीजों की परेशानी को ध्यान में रख कर बरामदों में पंखे लगवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : जी हां, बरामदों में पंखे नहीं हैं, बरामदे अच्छे खुले हुए हैं; अतः हवा पूर्ण रूप से प्राप्त होती है और आजकल पॉवर की भी कमी है, अतः अभी बरामदों में पंखे लगाने की योजना सरकार के सामने नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के बरामदे बन्द हैं और उन बन्द बरामदों में मरीजों को घण्टों क्यू में खड़ा रहना पड़ता है। ऐसी हालत में मरीजों को खुली हवा मिल सके इसकी व्यवस्था होना जरूरी है। मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या कभी उन्होंने अस्पताल में जाकर देखा है कि अन्दर कमरों में तो दो-दो तीन-तीन पंखे लगे हुए हैं जिनका ज्यादा उपयोग नहीं होता है। मैं यह नहीं कहता कि आप उनको हटा लीजिये लेकिन बरामदों में भी पंखा लगाना जरूरी है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि बरामदे बन्द नहीं हैं, बड़ी २ खिड़कियां हैं, वायरगॉज लगे हुए हैं जिनसे काफी हवा आती हैं। इसके अलावा इस वक्त पॉवर की कमी की वजह से भी वहां पंखे लगाना संभव नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : पॉवर की कमी तो इस वक्त है। बरामदों में पंखों की व्यवस्था तो पहले से ही होनी चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : वहां हवा तो काफी आती है, इसलिए कोई आवश्यकता भी नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : वहां छोटी छोटी खिड़कियों के अलावा हवा की और कोई

(श्री जयनारायण सालोदिया) व्यवस्था नहीं है। शायद मंत्रीजी ने देखा ही नही है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि वहां बरामदों में पंखों की अत्यन्त आवश्यकता है, वहां मरीजों को घण्टों क्यू में खड़ा रहना पड़ता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह डिजाइनिंग का प्रश्न है। यहां जो बरांडे हैं वे मेरे ख्याल में वेस्टर्न सिस्टम पर बने हुए हैं। विंडवार्ड एण्ड लीवर्ड साइड ऑफ दी विन्ड को मद्देनजर रख कर नहीं बनाये गये हैं। अगर आप गर्मियों में विंडोज को, खिड़कियों को खोल देंगे तो भी हवा अन्दर नही आयेगी बल्कि बाहर की हीट अन्दर रेडियेट होगी। अगर बाहर की हवा अन्दर रेडियेट होगी तो जो अन्दर होंगे उनको पसीना होगा और पसीने से दुर्गन्ध पैदा होगी जिससे लोगों को परेशानी होगी। मेरा ख्याल है कि आपको इस बारे में विचार करना चाहिए। अभी जो पॉवर की कमी है, तो यह तो मिट जायेगी; लेकिन यह तो एलीमेंट्री कॉमनसेंस का प्रश्न है। मेरा ख्याल है कि विन्डोज होने के बाद भी आज की आधुनिकता की रीढ़ इलेक्ट्रिक फैन्स हैं उन्हें भी आप नहीं देते हैं तो यह तो आपकी अस्पतालों की दुर्व्यवस्था ही होगी। आप इस पर विचार करें।

(१२.०० मध्यान्ह)

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां तक अस्पताल में मरीजों का सवाल है, माननीय अध्यक्ष, वहां पर कूलर्स, पंखे आदि सब हैं........

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : बरान्डे में नहीं हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपके कहने का मतलब है कि बरान्डे में नहीं हैं जहां कि मरीज आउट डोर के लिए खड़े रहते है, मैं माननीय विरोधी दल के नेता से निवेदन करूंगा कि वे उसको देख लें। मैं बता रहा हूं कि वहां पर बड़ी बड़ी खिड़कियां है जिनमें वायर गॉज लगे हुए हैं। वह हॉस्पिटल आधुनिक ढंग से बना हुआ है, उसमें हवा वगैरह के रुख का ध्यान इस तरह से रखा गया है कि उनमें हवा काफी आती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यहां पर डेन्टल सर्जन का आउट डोर तो आपने देखा है वहां पर कोई, खिड़की नहीं है। उसमें किसी भी तरफ से हवा नहीं आ सकती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : डेन्टल सर्जन के लिए माननीय सदस्य ने कहा है तो इसमें कोई शक नहीं है कि वहां पर खिड़की नहीं है, मगर वहां पर क्रोस वेन्टीलेशन है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्रोस वेन्टीलेशन नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : एक्स-रे के दरवाजे से है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कम से कम इसको ओवरलुक तो न करें।

श्री जयनारायण सालोदिया : शफाखाने में एक खिड़की है, उसी से हवा आती है।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : मन्त्री महोदय ने कहा है कि पॉवर की कमी है इसलिए पंखे नहीं लगाये जा रहे हैं; तो क्या

(श्री दिग्विजयसिंह)
ग्रस्पतालों के लिए भी ग्रादेश जारी कर दिये गये हैं कि पॉवर कम खर्च हो ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने सबको दिये हैं।

श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल : 'No, no एक तो झूंठ यह बोल दें कि वहां पर खिड़कियां हैं ग्रौर दूसरा यह झूंठ बोल दें कि गवर्नमेंट का ऐसा ग्रॉर्डर है।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय ग्रध्यक्ष; यह झूंठ बोलने की बात कहना, एक गलत बात है।

श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल : ग्रसत्य है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने एक सवाल के लिए कहा था कि पॉवर कम करने के लिए इलेक्ट्रि सिटी बोर्ड ने कहा है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : माननीय ग्रध्यक्ष, झूंठ लफ्ज़ का बहुत ज्यादा उपयोग हो चुका है ....

श्री ग्रध्यक्ष : यह बिल्कुल गलत है। मैं ग्रापसे सहमत हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह ग्रसत्य लफ्ज़ कहा जाय............

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप भी ध्यान रखें।

श्री हरिप्रसाद शर्मा !

(ग्रनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

ग्रनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

कस्बा जुरहडा की बिजली की सप्लाई

२८२. **श्री मजलिस खां (कामां) :** क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि कस्बा जुरहड़ा के लिए भाखरा से ग्रधिक बिजली सप्लाई करने के लिए पंचायत समिति कामां ने मांग की है ? यदि हां, तो इस संबंध में राजस्थान सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(२) क्या यह भी सही है कि कस्बा जुरहड़ा के निकट ग्राम जुरहड़ी ग्रौर ग्राम जामनी में इस समय १० ट्यूब वैल्स के लिए कनेक्शन्स दिये जाने की मांग ग्राई हुई है ? यदि हां, तो यह कनेक्शन्स कब तक दे दिये जायेंगे ?

उत्तर

(१) जी हां। ता० ३-१-६६ को। किलोवाट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। पर कनवाड़ा क्षेत्र के साथ लगते ५० कुग्रों में बिजली लेना चाहते हैं ऐसा बताया गया है। इन स्थानों का सर्वे किया जा रहा है।

(२) जी हां, कुग्रों की मांग ग्राई है। ग्राम जुरहड़ी ग्रौर जामनी को किसी भी प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जा सका है।

बांदीकुई से मंडावर तक पक्की सड़क का निर्माण

२८५. **श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या बांदीकुई से मंडावर मन्डी तक नदेरा, महुखेड़ा, पातलखेड़ा, हीगोटा इत्यादि जगहों से होती हुई पक्की सड़क बनाने को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई है ? यदि हां, तो क्या इस सड़क की

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)
बाबत सर्वे हो कर एस्टीमेट इत्यादि बन चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

उत्तर

चतुर्थ योजना का क्या रूप होगा अभी तय नहीं किया गया है ।

करेली नदी पर रपट का कार्य, तहसील रेवदर

२९२. श्री दलपतसिंह (आबू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि रेवदार तहसील (जिला सिरोही) में करेली नदी पर रपट का काम जल्दी शुरू होने वाला था ?

(२) यदि हां, तो अभी तक क्यों नहीं हो रहा है ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।

(२) अर्थाभाव के कारण शुरू नहीं हो सका ।

नैनवा में डाक्टर की नियुक्ति

२९६. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि नैनवा ग्राम, जिला बूंदी में करीब एक वर्ष से डाक्टर नहीं है और करीब ३० हजार की जनता को डाक्टर नहीं होने से परेशानी है ?

(२) यदि हां, तो नैनवा से डाक्टर का तबादला क्यों किया ? क्या सरकार नैनवा में डाक्टर की आवश्यकता नहीं समझती ?

(३) क्या यह सही है कि डाक्टर नहीं होने से जनता में भारी असंतोष है और सरकार से डाक्टर की व्यवस्था करने की मांग कर रखी है ?

(४) यदि हां, तो नैनवा में कब तक डाक्टर भेजने की व्यवस्था की जा सकेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां, डाक्टरों की कमी के कारण। अब नैनवा जिला बूंदी में डा. आर. सी. सक्सेना डी. ए. एस. का ट्रान्सफर सवाई माधोपुर से नैनवा दिनांक १५-२-६६ को किया जा चुका है ।

(२) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(३) जी नहीं ।

(४) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

स्थगित प्रश्न
(२–३–६६)

६१. श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला बांसवाड़ा की तहसील कुशलगढ़ के ग्राम उदयगढ़ वसूनी की वन श्रमिक सहकारी समिति की शेयर केपिटल कुल कितनी है ?

(श्री हीराभाई)

(२) क्या यह सही है कि इस समिति में सरकार का हिस्सा भी है लेकिन सरकार ने अपने शेयर की रकम अभी तक समिति को अदा नहीं की है ?

(३) क्या यह सही है कि समिति द्वारा सदस्यों को वितरित की जाने वाली राशि में से सरकार का हिस्सा भी निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो बिना शेयर की राशि अदा किये सरकार यह हिस्सा पाने की हकदार कैसे है ?

उत्तर

(१) इस समिति की हिस्सा पूंजी ३२२५) रु० है ।

(२) समिति के उपनियमानुसार राज्य सरकार द्वारा हिस्से खरीदने का प्रावधान है लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने कोई हिस्से नहीं खरीदे हैं ।

(३) समिति के उपनियमानुसार राज्य सरकार को लाभांश का हिस्सा देने का प्रावधान है और उपनियमानुसार यह प्रावधान रखा अवश्य गया लेकिन राज्य सरकार को कोई राशि नहीं चुकाई और रकम समिति के पास ही है ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

हिन्डौन व दौसा–गंगापुर चलने वाली बसों पर बकाया कर

५६. वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर): क्या वित्त (कर) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

हिन्डौन से गंगापुर व दौसा से गंगापुर चलने वाली कितनी बसों में किस-किस वर्ष का कितना कितना यात्री कर बकाया है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कमला नेहरू अस्पताल-कांकरोली

५७. श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(१) कांकरोली में 'कमला नेहरू अस्पताल' का शिलान्यास कब हुआ था ?

(२) क्या इस अस्पताल का निर्माण कार्य हो चुका है ? यदि नहीं, तो इसमें कितना काम बाकी है ?

उत्तर

(१) कांकरोली, जिला उदयपुर में कमला नेहरू अस्पताल का शिलान्यास ठिकाने के समय में दिनांक ४-१-४६ को स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू के कर कमलों द्वारा हुआ था ।

(२) जी नहीं, इस अस्पताल का निर्माणकार्य अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

चित्तौड़िया कृषि फार्म

५८. श्री उदयलाल वडिया (लसाड़िया): क्या पंचायत मंत्री उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की धरियावद पंचायत समिति के

Page No. 33

(श्री उदयलाल वर्दिया)

तत्वाधान में एक कृषि फार्म चित्तौडिया में चल रहा है और उस फार्म में रवी (१९६४) की फसल की पैदावार में से गेहूं की चोरी हुई और उसकी कार्यवाही के कागजों को बिना किसी जांच के निर्णय के विकास अधिकारी धरियावद ने गोलमाल कर दिए ?

(२) क्या उसके लिए अब भी कोई कार्यवाही जिला स्तर से हो रही है ? यदि नहीं, तो क्या कोई कार्यवाही भविष्य में कराने का विचार है ?

उत्तर

(१) जी हां, सन् १९६४ तक चल रहा था। उसमें गेहूं की चोरी नहीं हुई।

(२) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

कन्डक्टरों के खिलाफ गबन के मामले

५९. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) रोडवेज के कितने कन्डक्टरों के खिलाफ गबन के केस चल रहे हैं ?

(२) कितने कन्डक्टरों पर एक से ज्यादा गबन के केस चल रहे हैं ?

उत्तर

(१) ६ कन्डक्टरों के खिलाफ गबन के केस चल रहे हैं।

(२) तीन कन्डक्टरों के खिलाफ एक से अधिक केस हैं।

उदयपुर डिवीजन में बिजली की कमी

६०. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि इस समय उदयपुर डिवीजन में बिजली की कमी है ? यदि हां, तो इसकी पूर्ति किस प्रकार की जा रही है और कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

जी हां। इसकी पूर्ति के लिये यत्न किये जा रहे हैं।

चूरू—राजगढ़ सड़क निर्माण कार्य

६१. **श्री मोहर सिंह** (चूरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या चूरू से राजगढ़ सड़क का निर्माण कार्य वर्ष १९६४–६५ में हुआ ? यदि हां, तो इस पर कितना रुपया खर्च किया गया ?

(२) क्या वर्ष १९६५–६६ में इस सड़क निर्माण हेतु कोई धन-राशि खर्च की जावेगी ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) सरकार इस सड़क का निर्माण कब तक पूरा कराने का विचार रखती है ?

(४) इस सड़क की लम्बाई कितनी होगी और अनुमानित खर्चा क्या होगा ?

उत्तर

(१) जी हां, वर्ष ६४–६५ में अकाल सहायता के रूप में इस सड़क के निर्माण पर १,४८,६००) रु० व्यय हुआ है।

(श्री सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(२) जी हां, १८०,०००) रु० व्यय होने का अनुमान है।

(३) वित्तीय स्वीकृति के अभाव में निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(४) इस मार्ग की लम्बाई ३४ मील है। यह कार्य तृतीय सड़क निर्माण विभागीय योजना में स्वीकृति नहीं है। यदि डामर रोड निर्माण कराया जाय तो २०,४०,०००) रु० अनुमानित व्यय होगा।

वेजिटेबल घी का कारखाना

६२. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

भीलवाड़ा में बन रहे वेजिटेबल घी के कारखाने को किस तारीख से बिजली दी जा रही है। प्रति माह कितनी कितनी बिजली जनवरी, १९६६ तक दी गई? सूची सदन की मेज पर रखी जावे?

इस कारखाने को २-२-१९६६ से कनेक्शन दिया गया है। अस्तु जनवरी से कितनी बिजली दी गई यह प्रश्न नहीं उठता।

(१२.५ म. प.)

वित्तीय समितियों विषयक व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: वित्तीय समितियों के सम्बन्ध में प्रस्ताव आज तीसरे पहर मुख्य मंत्रीजी प्रस्तुत करेंगे, जो कि अभी पेश होने वाला था।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): अध्यक्ष महोदय, ·····

श्री अध्यक्ष: किसके लिए?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: मैं सिर्फ ५ मिनिट बोलूंगा। दो पोइंट रह गये थे।

श्री अध्यक्ष: आय-व्ययक पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद।

स्थगन–प्रस्ताव

राजस्थान की सीमा पर पाकिस्तानी फौजों का जमाव सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तानी फोर्सेज का हमारी सीमाओं पर कन्सन्ट्रेशन के सम्बन्ध में मैंने एडजोर्नमेंट मोशन दिया है। सरकार की तरफ से आज हो सके तो आज, या कल हो सके तो कल, वह स्टेटमेंट आ जाये। वहां पर कन्डीशन्स बहुत खराब हो रही हैं। वहां पर पाकिस्तानी फोर्सेज कन्सेन्ट्रेट कर रही हैं अपने आपको। वहां पर लोगों में भय छाया हुआ है और गडरा रोड से २० परिवार बाड़मेर शिफ्ट हुए हैं, यह मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। कल रात टेलीफोन भी आया था और बाड़मेर से पत्र भी आया था। कल एक माननीय सदस्य ने सदन में इसकी चर्चा भी रखी थी। सरकार इसको गम्भीरता से ले। ताशकन्द एग्रीमेंट के कारण धोखा देकर पाकिस्तानी फौजें घुस पैठ कर दें, और भारत की भूमि पर कब्जा कर लें और फिर इधर–उधर परेशान रहें। इस सम्बन्ध में इमीजिएटली क्या पोजीशन है उसको बतावें। गडरा रोड से कुछ परिवार बाड़मेर आये हैं। कुछ लोग बोर्डर के पास में जाकर बसे हुए हैं उनमें भय और आतंक हैं। हमारी जानकारी है कि पाकिस्तानी फौजें वहां पर बड़ी मात्रा में कन्सेन्ट्रेट हो रही हैं।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

गडरा रोड और चौहटन में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि उसके लिए राजस्थान सरकार शीघ्रातिशीघ्र इस सदन में स्टेटमेंट दे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मन्त्रीजी बहस का जवाब देंगे तो संभवतः इस पर भी कहेंगे।

श्री फतेहसिंह (चौहटन): अध्यक्ष महोदय, जो अभी फरमाया गया है वह बिल्कुल सही है। वहां पर पाकिस्तानियों की हरकतें हो रही हैं और एक पूरी ब्रिगेड को ब्रिगेड वहां पर लगी हुई है। वह लोग जो वहां आ रहे है वे पाकिस्तान के नहीं हैं, फौरेन कन्ट्री के मालूम होते हैं। लम्बे चौड़े शरीर के हैं। जगह जगह मोर्चे खोले जा रहे हैं। उसमें उनकी सीमा के अन्दर इस प्रकार की हालत हो रही है और खोखारापर से करीब दो स्टेशन और मुनाबा से तीन स्टेशन से लगाकर उमरकोट तक १६ कोस यानी २५ मील में लम्बे और १५-१६ मील की चौड़ाई में, बहुत बड़ी तादाद में लाख के करीब फोज है। सरकार इस ओर ध्यान नहीं रखेगी, तो सड्न अटेक हो सकता है। इसका पूरी तरह से ध्यान रखा जाये। इससे पब्लिक में बहुत हैरेसमेंट हो रहा है।

दूसरी बात यह है कि वहां पर पब्लिक को जो बन्दूकें दी गई थीं, वह वापिस ले ली गई हैं; इससे और भी अव्यवस्था फैल गई है। उनको बन्दूकें वापिस दिलाई जावें जो कि सिविलियन राजस्थान के अन्दर रह रहे हैं और दूसरे लोगों को आश्वासन दिया जाये कि पूरा इन्तजाम करेंगे। यह अगर नहीं होगा तो बोर्डर एरिया बिल्कुल खाली हो जायेगा और उससे उनका (पाकिस्तानियों) का हौसला बहुत बढ़ जायेगा।

श्री भेरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, रात को बाड़मेर से इस तरह की सूचना मिली थी कि बाड़मेर की सरहद पर पाकिस्तानी सेनाओं का जमाव तो है ही, लेकिन गडरा रोड से एक मील की दूरी पर एक टीले के ऊपर एक अच्छा मोर्चा और ऑब्जर्वेशन पोस्ट भी बनाई है। उस ऑब्जर्वेशन पोस्ट के पास टैंक्स भी हैं। वहां पर ऐसी स्थिति बन रही है कि शायद पाकिस्तान के इरादे इस सीमा के लिए खराब हैं। पाकिस्तान की सीमा पर जो बसे हुए लोग हैं, उनका हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण करना शुरू हो गया है और हमारे क्षेत्र के अन्दर जितने लोग बसे हुए थे वे बोर्डर से आ रहे हैं। पाकिस्तान से जो शरणार्थी हिन्दुस्तान में आ गये थे और जिनको हमने उन गांवों में बसाया था जहां से कुछ व्यक्ति पाकिस्तान भाग गये थे। अब वे पाकिस्तान से आ रहे हैं और उनसे खाली करवा रहे हैं। उनसे काफी भय और आतंक है।

इन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो यह है कि जिन लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से सेना और आर० ए० सी० का सहयोग देने की दृष्टि से, पाकिस्तानी आक्रमण का मुकाबला करने की दृष्टि से जो हथियार दिये गये थे, वे उनसे वापिस लिये जा रहे हैं.....

श्री फतेहसिंह: लिये जा रहे हैं नहीं, ले लिये हैं।

श्री भेरोंसिंह: ले लिये हों या लिये जा रहे हों, कुछ लोगों से ले लिये हैं और कुछ में बाकी हैं। उस स्थिति में सबसे बड़ा संकट उन लोगों के लिये पैदा हो गया है जिन्होंने कि संकट के अवसर पर भारत सरकार, राजस्थान सरकार और राजस्थान की जनता का साथ

(श्री भैरोंसिंह)

दिया, जिन्होंने पाकिस्तानी आक्रमणकारियों का मुकाबला किया। अपनी जान जोखिम में डालकर उन हथियारों से गांव के लोगों की सुरक्षा की, अपने राजस्थान की सुरक्षा की और देश का सम्मान बढ़ाया। आज सरकार केवल मात्र राजनैतिक कारणों से उन हथियारों को वापिस ले रही है। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है। हथियार और तो चलाता नहीं, हथियार को चलाने वाले राजपूत लोग हैं। वे सारे इस आतंक के कारण और पाकिस्तानी आक्रमण के कारण बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। उन लोगों के पास हथियार थे, जिसके होने से पाकिस्तान सफल नहीं हो सका। उनसे हथियार आज इस समय लेना इसका मतलब यह हुआ कि जिस समय संकट आया था उसको कम करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान से दुश्मनी मोल ली और पाकिस्तान के उन तत्वों से दुश्मनी मोल ली जो भारत में रहकर भी पाकिस्तान का समर्थन करते थे; आज उनसे हथियार लेकर उनको भगवान के भरोसे पर छोड़ते हैं। अगर सरकार ने इस रवैये को नहीं रोका तो घातक प्रक्रिया का स्वरूप रहेगा, उनके लिये ही नहीं लेकिन देश के लिए और सुरक्षा के लिए यह चीज घातक होने वाली है। इस लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न अपने आप में गम्भीर है। और इस गम्भीर प्रश्न पर सदन में चर्चा की जानी चाहिए। संभवतः मुख्य मन्त्रीजी उत्तर देंगे लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न सीमा सम्बन्धी रह गये है, जिनका जिक्र न राज्यपाल महोदय के भाषण में हो सका है और बजट के समय किया जा सका है। इसलिए इस बोर्डर के प्रश्न पर एक दिन इस सदन के अन्दर इस स्थगन-प्रस्ताव के रूप में एक दिन की चर्चा रखी जाये तो कुछ ऐसे तथ्य सदन के सामने रखे जायेंगे, जिनसे कि हमारी सीमा-सुरक्षा का काम हमेशा के लिए एक अच्छे रूप में हमारे सामने आ जायेगा।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस स्थगन-प्रस्ताव के रूप में या जिस प्रकार भी उचित समझा जाये, इस प्रश्न पर निकट भविष्य में चर्चा की जाने की अनुमति इस सदन के अन्दर मिलनी चाहिए।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं भी दो शब्द सिर्फ आपकी इजाजत से निवेदन करूंगा।

जहां तक ताशकन्द समझौते का प्रश्न है, मेरा दल ताशकन्द समझौते को कार्य रूप में परिणित कराने के हेतु, सरकार का सहयोग देने के लिए तैयार है और तत्पर है, किन्तु जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी बताया कि वहां पर पाकिस्तानी फौजों का जमाव है, हमारी सीमा के बाहर है, लेकिन बिल्कुल सीमा के सन्निकट जमाव है, इसका भी कोई खास असर है ? मुझे वहां की स्थिति क्या है; इसका पता नहीं किन्तु जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया वहां भगदड़ हो रही है, लोग भाग रहे हैं। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि लोगों को हथियार दिये गये थे, मुझे मालूम है हथियार दिये गये थे, कोई भी हो, जाति विशेष से मतलब नहीं। हथियार क्यों दिये गये थे ? संकटकालीन स्थिति थी, उसका मुकाबला करने के लिए हथियार दिये गये थे। अब ताशकंद समझौते से वहां सरगर्मी नहीं रहती और आप उनसे हथियार ले लेते हैं, ऐसा आरोप सरकार पर लगाया गया। मेरे ख्याल

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

से यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, साइकोलोजिकल स्थिति क्या बनेगी ? आप हथियार देते हैं, और काम बन गया तो कहते हैं कि लाओ हथियार वापिस। दूसरी बार यदि ऐसी स्थिति बन गई तो कौन देने आयेगा आप की नीति बिना पैंदे की है। मैं नहीं कहता कि इस पर यहां पर बहस हो, लेकिन यह नाजुक सवाल है, इसके लिए आप ही निर्णय करें, लेकिन सरकार की तरफ से निर्णायक नीति क्या है, क्या व्यवस्था की जा रही है, इसके बारे में सरकार का उत्तर बहुत आवश्यक है और यदि सरकार का उत्तर असंतोषजनक है, एक तरह से अस्पष्ट है और राजनीतिक कारणों से मिली जुली भगत और घुसपैठियों के साथ सहानुभूति प्रकट करती है तो इस पर विचार हो सकता है। इसके बारे में मैं आगे आवश्यकता होगी तो निवेदन करूंगा। अभी जो स्थिति है उससे सरकार सदन को अवगत करावे। पूरी तौर से सदन का अधिकार है कि उसे अवगत कराया जाय कि वस्तु-स्थिति सीमा पर क्या है ? कच्छ का ड्रामा फिर रिपीट न हो जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ सद्भावना रखना चाहते हैं, लेकिन सद्भावना एक हद तक होनी चाहिए, आंख मीच कर न बैठ कर विजीलेन्ट होना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, जनसंघ के माननीय सदस्य ने, विरोधी दल के नेता ने जो कहा उसके लिए संभव है मुख्य मन्त्रीजी आज बजट की बहस के दौरान जब भाग लेंगे उस वक्त कई मुद्दे, जो उठाये गये हैं, इस एड्जोर्नमेन्ट मोशन में और पहले माननीय सदस्य ने जो कहा उसका जवाब देंगे। इसके बावजूद भी जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा ऐसे मुद्दे पर बहस होनी चाहिए या नहीं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम ने एक कन्वेन्शन कायम किया था, कि बोर्डर पर क्या हो रहा है; उसके बारे में विरोधी दल के सदस्यों को बुला कर आपस में चर्चा की जाय। ऐसी चर्चा हमने पहले भी की है। यदि माननीय सदस्यों के पास कुछ तथ्य हो जिस की वजह से सुझाव देना चाहे तो माननीय मुख्य मन्त्रीजी के भाषण के बाद यदि जरूरत हो, तो उसके लिये कदम उठाया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय मैं खेद के साथ कहना चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार की समितियों की चर्चा कर के मूल बात को भुलावे में डालने की चर्चा करती है। सरकार की जितनी कमेटियां हैं उनमें मैं भी जाता हूं, लेकिन वहां जाना हमें कमजोर करता है क्योंकि हम पर यह रेस्पोन्सिबिलिटि आ जाती है कि कमेटी में जिन बातों पर चर्चा हुई उनका जिक्र बाहर नही करना चाहिए। इसमे हमारे मन में घुटन होती है और सरकार काम करती नहीं। मैं यह मान कर चलता हूं और मैंने यह निर्णय किया है कि इस प्रकार की समितियों में भाग नहीं लेना चाहिये। इस प्रकार की समितियां बना कर हमें चुप करना चाहते हैं। जितनी समितियां बनाई जाती हैं उनकी पूरी इन्फोर्मेशन नही दी जाती है, उसकी प्रोसिडिंग्ज हमारे पास नहीं भेजी जाती। जो कागज वहां पर दिये जायं वे तुरन्त वापिस लिए जायें, जैसे हम पर इनका विश्वास नहीं है। ऐसी स्थिति में इन समितियों का कोई उपयोग नही है। हम सीमा के सम्बन्ध में चर्चा करना चाहते हैं, निश्चित रूप से कुछ

(श्री भैरोंसिंह)

बातें कहना चाहते हैं, उनके बारे में आप समितियों की मारफत हमारी जुबान बन्द करना चाहते हैं। समिति में जाने के बाद हमारी मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी हो जाती है कि जो चीज हम कहना चाहते हैं वह न कहें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे आप समिति बनायें या नहीं, अब तक हमने मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी के कारण बातें बाहर नहीं कही हैं, लेकिन अब हमें मजबूर हो कर कहना पड़ेगा। हम इस मजबूरी पर पहुंच गये हैं कि राष्ट्रीय हित में जो बातें कहनी जरूरी हैं, उनको कहा जाय। बोर्डर के बारे में जितनी मिटिंग हुई, सरकार ने जितने आश्वासन दिये उनको पूरा किया नहीं, उनमें से एक की भी जानकारी नहीं दी गई। आज फिर समिति की बात करते हैं; २३ सिम्बर को सीज फायर हुआ, उसके बाद क्या सरकार ने या मुख्य मन्त्रीजी ने उस समिति की राय ली थी? सीज फायर के बाद सीमा पर किस प्रकार अतिक्रमण हुआ, पाकिस्तान से जो शरणार्थी आये उनकी समस्या थी, उनके भूख की समस्या थी, कितने लोग पाकिस्तान चले गये कितनों को आने दिया, कितनों को नहीं आने दिया; इन सब बातों की कोई जानकारी नहीं दी गई। हमने जब इस बारे में प्रश्न उठाया तो कहते है डिफेन्स की अलग कमेटी बनायेंगे। इस कमेटी से कोई फायदा होने वाला नहीं है। यह राष्ट्रीय प्रश्न है। यह कोई मेरे और मथुरादासजी के झगड़े का प्रश्न नहीं है, न मेरे और सुखाड़ियाजी के झगड़े का प्रश्न है और न कांग्रेस और दूसरी पार्टी का प्रश्न है। बल्कि यह राष्ट्रीय प्रश्न है। सदन में आलोचनात्मक दृष्टिकोण को दूर करके क्या व्यवहारिक कदम उठा सकते है इस पर विचार करने की आवश्यकता है, इसलिये इस पर जब भी सरकार चाहे खुली बहस होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का यह कहना है कि समितियों की परम्परा बनी है उससे उनको संतोष नहीं है और सदन में सारी सुरक्षा की चर्चा करना चाहते हैं; मैं तो केवल यही कहूंगा कि आप सदन में या बाहर क्या चर्चा करें, न करें, समितियों में जो बताया जाये उसका किस हद तक पालन करें, यह स्वयं आपके विवेक पर निर्भर करेगा। यह आप मानेंगे कि कई बातें सदन में कहना उचित नहीं हैं, उनको न कहना चाहेंगे। इसलिये सारी समितियां समय-समय पर हुई हैं, उनमें जो कुछ कहा गया उनको बताना उचित नहीं है उसमे लाभ अवश्य हुआ है। इससे भी आगे और कोई प्रक्रिया चाहते हैं सदन में चर्चा के लिये, तो उस पर व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन ऐसी कुछ बातें हैं जिनके बारे में आप मुख्य मंत्री जी के साथ और अन्य लोगों के साथ बैठ कर चर्चा कर सकते हैं और व्यवहारिक हल निकाल सकते हैं; इसलिये मैं ज्यादा कहना उपयोगी नहीं समझता। मुख्य मंत्री जी आज बहस में भाग लेंगे उस समय जितनी उनको जानकारी है, और जो बातें बताई जा सकती है वे सदन में बतावें। बोर्डर पर जो हथियार बांटे गये हैं, उनके संबंध में सरकार की क्या नीति है; इसका स्पष्टीकरण वे स्वयं कर सकते हैं। इसके उपरान्त भी यदि आप चाहते हैं, कि यहां पर बहस हो तो सदन के नेता और विरोधी पक्ष के नेता से मिल कर व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन क्या बहस होगी, क्या न होगी, यह सोचने की बात है। इस चर्चा को अब यहीं समाप्त किया जाये।

श्री भैरोंसिंह : मैं सरकार की नीयत पर अविश्वास नहीं करता। हम यह नहीं कहते

(श्री भैरोंसिंह)
कि पाकिस्तान हमला करे और हम डिग जाये, यह न कांग्रेस चाहती है, न हम चाहते हैं और न कोई दूसरे चाहते हैं। हम यह भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान हमारी कमजोरी का फायदा उठा ले। हम ऐसा हल चाहते हैं, जो राजनीतिक दृष्टिकोण से सरकार को कमजोर न करे। हम कमेटियों में और समितियों में राजनीतिक कमजोरी के कारण चर्चा नहीं कर सकते, इसलिये हाउस में चर्चा हो तो निश्चित रूप से लाभ होगा। मेरा दल या दूसरा दल कोई ऐसी बात नहीं कहेगा, जिससे दुश्मन लाभ उठा सके। उसको लाभ उठाने देने के बनिस्पत हम चुप, मौन रहना पसन्द करेंगे। (हियर हियर) सरकार मन में तो अनुभव करती है कि करना चाहिये लेकिन राजनीतिक कारणों से कमजोरी अनुभव करती है। इसलिये यह काम कमेटी में बैठ कर चर्चा करने से नहीं होगा; विधान सभा में ही चर्चा करना उचित होगा, इसलिये मैंने इस संबंध में निवेदन किया था।

(१२.२० म. प.)

आय-व्ययक १९६६-६७ पर अग्रेसर विचार-विमर्श

श्री अध्यक्ष : अब बजट पर सामान्य वाद-विवाद !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता . . . . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Excuse me for interruption; गवर्नमेंट रिप्लाई कितने बजे शुरू होगा करीब, near about.

श्री अध्यक्ष : रिप्लाई का समय निश्चित नहीं है, पिछले घंटा-डेढ़ घंटा गवर्नमेंट रिप्लाई होगा और अन्य मंत्री महोदय बीच में बोलना चाहेंगे वह थोड़ी देर के लिए बोलेंगे।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : श्री नाथूराम जी बीच में इन्टरवीन करेंगे। फाइनेन्स मिनिस्टर जवाब देंगे और मुख्य मंत्री जी बोलेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जवाब कौन देंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : फाइनेन्स मिनिस्टर।

श्री दामोदरलाल व्यास : नाथूरामजी बोलेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : वह कह दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तीन बोलेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता के हित के लिए और राजस्थान की जनता की भलाई के लिए, राजस्थान सरकार जिम्मेदार है और खास करके वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री राजस्थान की जनता के हित के संरक्षक हैं—Custodian of the welfare of the people. बहस का आज आखिरी दिन है। मैं आंकड़ों में, आंकड़ों की उलझन में, आज ज्यादा नहीं पड़ना चाहता। आवश्यकता के अनुसार आंकड़ों का सहारा यदि लेना पड़ा, तो मैं निवेदन करूंगा। सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपके द्वारा, अध्यक्ष महोदय, कि स्वस्थ परम्परा के अनुसार बजट जैसी महत्वपूर्ण चीज जब सदन के समक्ष रखी जाती है, तो उसकी प्रतियां वितरित होने के लिए सुचारु ढंग से व्यवस्था होनी चाहिए। जो अब के, मैं समझता हूं, नहीं हो पाई है।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

सरकार अपने बजटिंग को अधिकांश रूप से पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर आधारित करती है। मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि तीन पंचवर्षीय योजनायें हो चुकी हैं चौथी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में अब हम विचार करने को जा रहे हैं। पंचवर्षीय योजनायें, अध्यक्ष महोदय, हैं, उनके सम्बन्ध में भी प्रशासनिक और आर्थिक रूप से मैं वित्त मंत्री जी के मनन के लिए पांच सूत्र रखूंगा। मेरा प्रथम सूत्र है—मितव्ययता, दूसरा सूत्र है–उत्पादन, तीसरा सूत्र है–परिवार नियोजन चौथा सूत्र है–भ्रष्टाचार, और पांचवा सूत्र, है–कंट्रोल। इन पर ध्यान आकर्षित करते हुए हर एक सूत्र पर मैं दो चार मिनिट के लिए आपके समक्ष, आपकी आज्ञा से, विवेचन करूंगा स्पष्टीकरण के रूप में।

अध्यक्ष महोदय, मितव्ययता के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि सरकार अगर अकाल-ग्रस्त राजस्थान के प्रति कोई सहानुभूति प्रगट करती है, कोई टेन्जिबल सिम्पेथी के रूप से आप कोई एक्शन लेते हैं, कोई काम करते है, तो सबसे पहले मैं समझता हूं कि मंत्रि-मण्डल की तादाद में कमी होनी चाहिए अगर आप यह करते हैं, मंत्रि-मण्डल की तादाद में कमी करते हैं, तो मैं समझता हूं, आप राजस्थान की जनता के साथ अपने आपको आइडेन्टीफाई करते हैं, सहानुभूति एक हद तक प्रदर्शित करते हैं। जिसके द्वारा आप अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकेंगे और मेरे ख्याल में विरोधी पक्षों की ओर से भी आप प्रशंसा के पात्र बन सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा मितव्ययता के सम्बन्ध में, मैं यह निवेदन करूंगा कि आपकी जो बकाया है, उस सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला है, मेरा भी अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी से आपके द्वारा यह निवेदन है कि इन एरिअर्स के सम्बन्ध में जो ठण्डी उगाही हो, जो बेड एरिअर्स हों उसके बारे में अभी विशेष विचार न करें, लेकिन इस सारे क्षेत्र को, आपके इस बकायात के क्षेत्र को दो हिस्सों में विभाजित करिये–एक ऐसा हिस्सा कि जिसको आप टेकल कर सकते हैं, जिसमें आप हाथ डाल कर वसूली की रफ्तार को बढ़ा सकते हैं। ऐसे क्षेत्र में मेरे ख्याल में करोड़ों का नहीं तो लाखों का रुपया होगा ही। ऐसे क्षेत्र में वित्त मंत्रीजी, आपको छाती पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूं क्या हो रहा है। छाती पर बैठ कर आप कोई इन्सेन्टिव क्रियेट करिये अपने अमले में और अपने कर्मचारियों में, यह आश्वासन दीजिये, अमुक समय में यदि किसी के द्वारा अमुक लाभ होगा, बकायात की वसूली होगी, तो उसको प्रोत्साहन दिया जायेगा, तरक्की दी जायेगी, उसको प्रशंसा दी जायेगी। यदि ऐसा सर्विसेज को इन्सेन्टिव होगा, ऐसा प्रोत्साहन आप देंगे, और छाती पर बैठ कर काम करेंगे, तो मेरे ख्याल में इस बारे में कुछ न कुछ प्रगति हो सकेगी।

दूसरे जो आपका राजकीय उद्योग है, स्टेट एन्टरप्राइज है, उसमें एक मिक्स्ड इकोनोमी है, मेरा उससे कोई विरोध नहीं है; मेरा कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आखिरकार यह मान कर चलें कि राजकीय उद्योग के नाम से राजकीय उद्योग है और इसलिये उसके अन्दर कोई पुनर्विचार न किया जाय यह सही कदम नहीं है, मेरे ख्याल में, यह गलत रास्ता है। अगर लगातार कोई राजकीय उद्योग दो साल,

Page No. 41

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

तीन साल, चार साल तक आपको रोजी नहीं करता, आपको कोई मुनाफा नहीं देता, वह नुकसान पर ही जा रहा है, घाटे पर ही चल रहा है, तो वित्त मंत्री का पुनीत कर्तव्य है कि केबिनेट में, मंत्रि-मण्डल में, बहस करके यह कहें कि टेक्स देने वाली, कर देने वाली जनता की गाढी कमाई के पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये। ऐसे स्टेट एन्टरप्राइज को आप कर्टेल करदें तो मेरे ख्याल में बहुत सारी धन राशि आप बचा सकेंगे और मितव्ययता के सम्बन्ध में, मैं समझता हूं कि आप कोई न कोई ठोस नीति निर्माण कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, जो भी यह राजकीय उद्योग हैं, इन राजकीय उद्योगों का नफा-टोटा का हिसाब जो है उसका ट्रेडिंग अकाउन्ट है उसको भी सदन के समक्ष बजट के अन्दर स्पष्टतया रखना चाहिए। वित्त मंत्री यदि अपना बजट लेकर के इस सदन के अन्दर आते हैं तो मेरे ख्याल में इस सदन को अधिकार है कि उनके बजट का निराकरण असैसमेंट हो और वह असैसमेंट नहीं हो सकता। जब आप व्यापारी के रूप को धारण करते हैं, जब व्यापारी का रूप सरकार धारण करती है, तो व्यापारी के रूप में सरकार को आना चाहिए और पूरे व्यवस्थित ढंग से, जैसे असेसी इन्कम टैक्स आफिसर के सामने अपना प्राफिट एण्ड लोस अकाउन्ट ले जाकर बताता है, उसी तरह आपको भी इस सम्बन्ध में ट्रेडिंग अकाउन्ट मुफस्सिल तौर पर बताना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है मितव्ययता के सम्बन्ध में कि जो बी. डी. ओज. की जगह हैं उनको खत्म कर दें। बी. डी. ओज को जो जीप्स हैं और उन जीपों के द्वारा जो पेट्रोल खत्म होता है, जो सरकार के वाहनों का दुरुपयोग होता है, उसके बारे में आज मेरे ख्याल में सारे राजस्थान में शिकायत है। बी. डी. ओज. कोई गांवों का भला नहीं करते हैं, वह राजनीति के अन्दर प्रधानों को गलत रास्ते पर चलाते है। मध्य प्रदेश में इस बी. डी. ओ. की संस्था को समाप्त कर दिया है, समाप्त करने के पश्चात् मध्य प्रदेश के सदन ने इसका स्वागत किया है और जनता ने भी इसको पसन्द किया है। मैं समझता हूं कि यह एक लक्जरी है, हमारे गरीब राज्य के लिए, यह सुपरफ्लुएटी है, यह बिल्कुल फिजूल खर्च है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, बी. डी. ओज., उनकी जीप्स और उनके अमले पर जो लाखों रुपयों का खर्च है, इस बारे मे कमी करने के लिए विचार करें।

इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री का ध्यान और चीफ मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, कि गरीब जनता का हजारों रुपया रोज खर्च होता है क्योंकि शासन की व्यवस्था की कमी, शासन में नियंत्रण की व्यवस्था के साथ साथ बहुत से मुकामी अफसर ऐसे होते हैं बिना कोई इत्तला छोटे-छोटे बहाने पर दौरे के नाम से सैर-सपाटे करने दौरे पर चले जाते हैं और लोग बेचारे आ आ कर वापिस चले जाते हैं। उनका समय और पैसा बरबाद होता है। मैं यह नहीं चाहता कि वे दौरे नहीं करें। आवश्यकता हो अवश्य करें, परन्तु आप यह व्यवस्था दें कि एक महीने में १५ दिन दौरे पर रहेंगे तो ठीक है अगर आप यह कहें, कि वे १८ दिन महीने में दौरे पर रहें तो भी

Page No. 42

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

मुझे कोई आपत्ति नहीं। मगर महीने में बिला बात के दौरे करें और २४ दिन दौरा करें और अपने साथ फाइलों के गट्ठे के गट्ठे ले जावें और उसको ज्यों के त्यों वापिस ले आवें, न तो डिस्पोजल हो और न कुछ कार्य हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपके एस. डी. ओ. और. बी. डी. ओ. जो भी हो, उनके लिए यह हो कि अमुक दिन महीने में हैड क्वार्टर पर रहेंगे। यदि उनको किसी आवश्यक कार्य के लिये जाना पड़े तो वे जावें मगर अपने एवज मे किसी को रख कर जावें। ताकि गरीब जनता को जो वहां पर आवे किसी प्रकार की परेशानी न हो और वे इस सम्बन्ध में खर्चे से और समय की बरबादी से बच सकें और उसको आने जाने की तकलीफ न हो।

बिल्डिंग, इमारतों के संबंध में मैं यह कहूंगा कि बहुत ज्यादा बड़े-बड़े बिल्डिंग वगैरा जो दुष्काल का समय है, आप न बनावें आप पुलिस के थाने हैं उसमें भी बहुत लेविशली पैसा खर्च करते है। इस समय आप आराम से रोक सकते हैं। कुछ समय बाद अच्छा समय आवे तो आप उन बिल्डिंग्ज को बनवा दें। स्कूलों के सम्बन्ध में मैं नहीं कहता, उनको प्राथमिकता दी जावे। मगर मैं होस्पिटलों, पुलिस के लिये बिल्डिंग्ज, पटवारियों और ग्राम सेवकों के लिये मकान बना रहे हैं, मेरे ख्याल से इस तरह की फिजूल खर्चों का समय नहीं है। हमारी आमदनी ५१–५२ को १६ करोड़ थी और अब यह ६६ करोड़ से ऊपर जा चुकी है। मुझे भी सदन में चार साल हो गये है। मैं यह देखता हूं कि सरकार के पास जो पैसा आता है उसको सरकार खर्च करती है और सरकार का यह ध्येय रहा है कि अधिक से अधिक पैसा प्राप्त करना और कम से कम जनता के पास पहुंचाना। मेरे ख्याल मे यह बजट निर्माण की सरकार की नीति है। आपने करोड़ों रुपये खर्च करके व्यावसायिक-व्यवस्थाएं कायम की हैं और उसमें अधिक रूप से फिजूल व्यवसायिक-संस्थाएँ कायम करके खर्च करते हैं। वह रुपया जनता तक नहीं पहुंचता है, वह रुपया रुक जाता है। इसलिये यह गलत नीति है और आपके आंकड़े हैं वे भी संतोषजनक नहीं हैं। मेरे ख्याल से इसमें भी खामियें हैं, मैं निवेदन करूंगा। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना बजट इस रूप से रखें कि उसको सामान्य जनता समझ सके, तो मेरे ख्याल से विशेष हितकर होगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सूत्र है उत्पादन। मैं इस बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि उत्पादन बढ़ा नहीं है घटा है। खाद्यान्नों का आयात घटा नहीं है बढ़ा है। हम स्वावलम्बन से परे धीरे धीरे निश्चित रूप से जा रहे हैं, मेरे ख्याल से स्वावलंबन से दूर जा रहे हैं और परावलंबन का रास्ता धीरे धीरे अपना रहे है। मैं इस सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से अभी उत्पादन के सम्बन्ध में ६ तारीख के समाचार पत्र में जो बात लिखी गई है, वह मैं निवेदन करूंगा:—

"The average yield per hectare of land in India is about one-fourth of that in the advance countries, according to figures available from the Food and Agriculture Organization (F. A. O.).

India's yield of 290 Kg. of wheat per hectare is the lowest in the

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

world. The yield in Britain is 4350 Kg., in West Germany is 3480 Kg., in the UAR 2610 Kgs., in Japan 2540 Kg., in Italy 2090 kg., in the U.S. 1,690 Kg., and in the Soviet Union 1,050 Kg.

The world average wheat yield is 1,260Kg ,per hectare. In rice too India fares no better. The yield per hectare is only 1,380 Kg., compared with Australia's 603?, the UAR's 5840, Italy's 5490, Japan's 5260, the United States, 4180 Soviet Union's 2190, Burma's 1690 and the world average of 1990 Kg.

ये आंकड़े देखने से भी स्पष्ट होता है अध्यक्ष महोदय, कि हमारा उत्पादन आधुनिक ढंग से भी नहीं है और मेरे ख्याल से इस ढंग का है कि जिसमे किसानों के अन्दर असंतोष पैदा करता है और यह आपकी गलत नीतियों के कारण। हमारी ७० प्रतिशत भारतवर्ष की कृषि प्रधान जनता है, जो खेती करती है, उस धन्धे को आप इन्डस्ट्री के रूप में नहीं लेते और कई गलत नीतियों के कारण आप उनके उत्पादन में भी ठेस पहुँचाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप कुओं निवाना बनाइये। जितने कुएं नहरें होंगे, उतना ही मेरे ख्याल से भविष्य में आपको लाभ मिलेगा।

लघु सिंचाई के लिये तालाबों के बारे में मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप इस पर भी विशेष ध्यान दीजिये और अकाल में पैसा खर्च करके देखें कि सही रूप से इससे उत्पादन हो। किसानों पर इतने टैक्स लग चुके हैं कि जितने टैक्स आज किसी दूसरी जगह पर नहीं लगे हैं। किसानों पर टैक्स लगाने से उनको रोष होता है और उत्पादन कम होता है। इसके अलावा आपके कानून भी इतने पेचीदे हैं कि मेरे ख्याल से बहुत सारे वकील उसको भले रूप में नहीं समझ सकते। जब वकील भी उनको नहीं समझ सकते तो बेचारे किसान क्या समझ सकते हैं? मेरे ख्याल से यह असंभव और मृगतृष्णा जाल है। यह सबसे बड़ा कृषि का धन्धा है, उसको आप धन्धे के रूप में समझिये और इसको धन्धे के रूप में समझेंगे, तो मेरे ख्याल से आपको इससे लाभ मिलेगा, वरना आप अपनी गलत नीतियों की वजह से हमारी खाद्यान्न की स्थिति को सुलझा नहीं सकेंगे और वह उलझती ही चली जावेगी।

मेरे पूर्व माननीय सदस्यों ने नॉन–टैक्स रेवेन्यू के सम्बन्ध में निवेदन किया। सरकार को नॉन टैक्स रेवेन्यू को डेवलप करने के लिये इन्वेस्टमेंट करना चाहिये, खर्च करना चाहिये, जिससे कि अधिक से अधिक राज्य को लाभ हो। राजस्थान मेरे ख्याल से खनिजों के सम्बन्ध में इतना समृद्धिशाली है कि जितना इस सम्बन्ध में नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने के लिये इन्वेस्टमेंट किया जायेगा, उतना ही अधिक आर्थिक लाभ राज्य को होगा।

अब मैं थोड़ा भूमि के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा। भूमि के अलॉटमेंट की आपकी व्यवस्था बड़ी भद्दी और बदतर है, बी. डी. ओ. वगैरह मिल कर राजनैतिक कारणों से भूमि का अलॉटमेंट करते हैं। १०–१५ बीघा भूमि किसी भूमिहीन किसान को दी, अवश्य दें, पर उस बेचारे के पास साधन नहीं, केपिटल नहीं, हल नहीं बैल नहीं,

Page No. 44

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

बिना इन साधनों के वह क्या खेती कर सकता है? तो मेरा निवेदन है कि कम से कम उनको साधनयुक्त करके भूमि का अलॉटमेंट करे, तब तो भूमि के अलॉटमेंट का अर्थ है वरना इसका कोई अर्थ नहीं। मैंने चन्द बार सुझाव दिये, पर अब तो जाना ही छोड़ दिया। एक एम. एल. ए. हूं, पर नाममात्र का एम. एल. ए. हूं। कोई भी कन्सट्रक्टिव बात कहें, वे उसके बिल्कुल विपरीत बात हो तो, मेरी प्रतिष्ठा के विपरीत है कि मैं क्यों जा कर अपना समय नष्ट करूं। भूमि अलॉटमेंट के बारे में इतनी भुलभुलैया वाली व्यवस्था है, लाबरिन्थ ऑफ रूल्स है कि इसमें सही माने में कोई लाभ नहीं होता। आसपुर पंचायत समिति के अन्तर्गत एक पंचायत है, सागोड़। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप इस तरह मुंह न मसकायें। सागोड़ पंचायत विशुद्ध आदिवासी क्षेत्र है; वहां के बीस-पचीस भूमिहीनों को तो एक बिस्वा भी जमीन अलॉट नहीं की गई और वहां के तीन मील पर सावला नाम का एक ग्राम है, वहां के व्यापारियों को भूमि अलॉट की गई। मैंने कहा कि यह अनुचित है, अन्याय की पराकाष्ठा है। एक साहब हैं जो प्री इन्डिपेन्डेन्स, स्वतन्त्रता से पूर्व कट्टर मुस्लिम लीग के अनुयायी थे, अवसरवादिता के आधार पर कांग्रेस के लाडले लाल बन गये, उनको भूमि वहां अलॉट की। कलेक्टर साहब को कहा कि क्या यह उचित है, तो उन्होंने कहा अनुचित है, जिसको कहा उसने यही कहा कि यह अनुचित है, रूल्स के खिलाफ है, पर अगर यह रूल्स के खिलाफ है तो अलाटमैंट कैन्सिल तो होना चाहिए।

श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रामीन्द) : अपील करें, उसका तो प्रोवीजन है, अपील का।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप भी क्या बात करते हैं, अपील करेगा वह बेचारा आदिवासी? वह अपील पर सकता है, सैकड़ों रुपया अपील कर खर्च करके और फिर कौन सुनता है। अपील भी की है, अपील का खर्चा भी मैं देने को तैयार हूं पर अपील में क्या होगा? होगा तो भी पांच वर्ष में, जब चिड़िया चुग गई खेत। इस अलॉटमेन्ट के सम्बन्ध में, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि वहां चरागाहों की बड़ी तकलीफ है। हमारे यहां कोई प्रेशर ऑन लैंड नहीं है, पर आंखें मींच कर अलॉटमेंट हो रहा है। चरागाह अगर नहीं होंगे, तो मवेशियों को खड़े रहने की जगह नहीं रहेगी, गांवों की सारी इकोनोमी अस्तव्यस्त हो जायेगी, इसके साथ ही साथ खाद्य की भी समस्या जटिल हो जायेगी, क्योंकि जमीन तो रबर है नहीं कि इसे खींच कर बढ़ा सकें और फिर आबादी भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, वह भी एक दानव रूपी समस्या बन रही है।

तीसरा मेरा सूत्र है-परिवार नियोजन। परिवार नियोजन के सम्बन्ध में जो कुछ आपने किया है वह ना-काफी है। आप कल्पना तक नहीं कर सकते, आज से ३४ वर्ष के बाद अगर हमारी आबादी १०० करोड़ हो जाती है तो हम क्या करेंगे? आस्ट्रेलिया की कुल आबादी १ करोड़ है, हम एक करोड़ सालाना के अनुपात से बढ़ रहे हैं। इस सम्बन्ध में कुछ नहीं करेंगे तो यह काबू के बाहर मामला हो जायेगा। काबू के बाहर मामला हुआ तो जनतन्त्र की चिड़िया है, यह भी हवा में उड़ जायेगी। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि आपको परिवार

Page No. 45

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

नियोजन के सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाना चाहिए। जापान और फ्रांस ने इस पर काबू किया और उन्होंने इस समस्या पर काबू पाया। मेरा निवेदन है कि उत्पादन के बाद परिवार नियोजन को हाइयेस्ट प्रायोरिटी दी जाये, सबसे बड़ी प्राथमिकता दी जाये। मुझे दो एक वर्ष पूर्व मुख्य मन्त्रीजी ने कहा था कि विरोधी पक्ष के लोग परिवार नियोजन का मजाक करते हैं और अनुचित लाभ उठाते हैं। मैं तो न मजाक करता हूँ और न ही इसका अनुचित लाभ उठाता हूं, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर सरकार को इस समस्या पर काबू पाने के लिए आवश्यक सहयोग देने को तैयार हूं, बशर्ते कि सरकार ईमानदारी से आगे आकर, योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही करे।

चतुर्थ सूत्र, भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है। मैं समझता हूं इस भ्रष्टाचार ने ही रेडटेपिज्म और दिलंगाई को जन्म दिया है। मेरे ख्याल में नोकरशाही इसमें आपाधापी करके, इसी में आनन्द और मजा मानती है कि मिसलों का निबटारा बिल्कुल रुक जायें, मिसलों का निबटारा हो ही नहीं, तो जब तक फाइल्स का निबटारा आप नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे? उस हालत में तो आप सरकार कहलाने की संज्ञा में भी नहीं आ सकते। मिसलों में से कागज फाड़ दिए जाते हैं, मिसलें गायब हो जाती हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बहस के समय मैंने कुंआ ग्राम एक भूतपूर्व ठिकाने की मांजी का प्रश्न रखा था। राज्य मंत्रीजी ने कहा कि मुझे मालूम होना चाहिए कि मिसल कहां है। मुझे तो मालूम नहीं। इन्टिग्रेशन हुआ तो राज्य सरकार को सारा रिकार्ड चला गया, कोई कहता है कि सागवाड़ा में है, कोई कहता है डूंगरपुर में है। मेरी चला जाने, मैं कैसे जानूं कि कागज कहां है? तो कागजों की फड़ाई, मिसलों का गायब हो जाना, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की एफिसियेन्सी नहीं आ सकती। मैं वित्त मंत्रीजी से कहूंगा कि इन्सेन्टिव पैदा करिये, जो लोग फाइलों को, मिसलों को दबा कर बैठे हैं, उनका सस्पेन्शन नहीं हो तो एक्सप्लेनेशन तो लें, अगर यह नहीं करते तो आप सरकार ही नहीं हैं भड़भूंजे की दुकान से भी बदतर हैं। आपकी ओर से कोई चेष्टा नहीं, इन्सेन्टिव नहीं, किसी को पकड़ कर सजा दिलाने की चेष्टा नहीं करते और न आपका विजीलेंस कमीशन ही काम करता दिखता है, आपका विजीलेंस कमीशन नान-विजिलेंट है। जब तक आप फाइलों के त्वरित डिस्पोजल की व्यवस्था नहीं करते, तब तक रेडटेपिज्म, भ्रष्टाचार और दिन-ब-दिन बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं।

अभी सदन के समक्ष मुआवजे का प्रश्न आया, सड़कें बनाते हैं। माननीय सदस्य, जनसंघ के नेता ने कहा, एक्विजिशन पहले करते हैं या नहीं। अगर एक्विजिशन पहले नहीं करते तो इल्लिगेलिटी को प्रोत्साहन देते हैं। अगर अव्यवस्थित ढंग से मुआवजे के प्रश्न को हल नहीं कर सकते तो फिर आप क्या करेंगे? यह तो इनकॉम्पीटेन्सी की पराकाष्ठा है। पांच–पांच, सात–सात साल से मुआवजे के मामले पड़े हुए हैं, यह अन्याय है। कोई भी योजना को हाथ में ले तो उसके साथ साथ लोगों को मुआवजा चुका दें। ऐसा ही पेन्शन का प्रश्न है। अंग्रेजों के शासन के समय, इन्डियन स्टेट्स के समय में कभी इस प्रकार की बातें नहीं होती थीं, कोई आदमी

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
रिटायर हुआ तो रिटायर होने के दिन से पेन्शन तय होकर चुका दी जाती थी। वह पेन्शन शुमार होने लगती थी। आज बेचारे लोग रिटायर हो जाते है, उनके पास एक कौड़ी भी नही रहती, ऐसे भी लोग डूंगरपुर के अन्दर है, जो जयपुर तक नही आ सकते। दो, तीन साल तक उनको पेन्शन नहीं मिल रही है। क्या गरीब फका-मस्ती करें? आखिर आप एहसान-फरामोश होकर उनकी पेन्शन की व्यवस्था न करें, यह तो अन्याय की पराकाष्ठा है।

एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट जो मंदिरों के संबंध में आई है, मेरे ख्याल आई-ओपनर (आंख खोलने) जैसी है, देखने लायक है। ७५०० मंदिर राजस्थान में हैं। कई मंदिरों के पास लाखों रुपयों की व्यवस्था है। औसतन अगर एक मंदिर की जायदाद हजारों रुपयों की हो तो ७५०० मंदिरों की जायदाद का क्या ठिकाना, आप अनुमान करें। देशी राज्यों के विलीनीकरण के बाद सरकार १८ वर्षों से निरंतर राज्य कर रही है। अभी तक उन मंदिरों की न तो कोई आपके पास लिस्ट है और न ही जायदाद कितनी है, जानकारी है और न कोई ऐसी लिस्ट है, सोने चांदी जवाहरात की। क्या व्यवस्था है नाथद्वारा में? अब सुना है, कि रिषभदेव के मंदिर से ७०० तोला सोना ले उड़ा, जिस तरह से रक्षा कोष का सोना इधर-उधर हुआ, तो यह दुर्व्यवस्था की पराकाष्ठा है। मैं सरकार को सेन्सर करता हूं और वित्त मंत्री से, आपके द्वारा, निवेदन करता हूं कि इस बारे में गंभीरतापूर्वक निश्चित रूप से दृढ होकर जांच करें और इस समस्या को कैबिनेट स्टेज पर लाकर आप हल निकालें।

माननीय सदस्य जो जायल से आये उन्होंने कल कहा कि राजस्थान में मंदिरों और धर्मादा संबंधी अचल जायदाद काशी, प्रयाग और दूसरे स्थानों पर लाखों रुपयों की जायदाद को हजारों के भाव में इधर-उधर राजनैतिक कारणों को लेकर बेच दी। इस बारे में भी कोई पूछताछ नहीं। इस बारे में कमीशन आफ इन्क्वायरी एपोइंट की जाये और इस समस्या की जानकारी प्राप्त करने के लिए, व्यवस्थित ढंग से उस कमीशन को काम करके अपनी रिपोर्ट सदन के समक्ष लाया जाये, यह मेरी मांग है।

जहां तक जंगल का प्रश्न है, ये तो लावारसी मिल्कियत की तरह पड़े हैं। वहां कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, मैं समझता हूं कि कानून के अनुसार काम नहीं हो रहा है। ठेके दिये जाते हैं, उनसे दस गुना क्षेत्र ठेकेदार काट लेते हैं, सड़कें बनाते हैं, दिन-दहाड़े अंदर लकड़ियां ले जाते हैं और लूट चल रही है। यह राष्ट्र-धन का सत्यानाश हो रहा है, मैं इसका कठोर विरोध करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि आप जंगलों की व्यवस्था करें। खास तौर से जिस तरह मेरे जिले के अंदर जंगल थे, मेरे ख्याल से उनका दशांश नहीं रहा है। जो अच्छे जंगल थे, वहां उनके १५–२० परसेंट जंगल रह गये होंगे। अच्छी लकड़ी जैसी कोई चीज नहीं रही, कई ठेकेदार तो गुजरात भी ले गये।

श्री उदयलाल वढ़िया (लसाड़िया): पांच परसेंट भी नहीं रह गये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: उदयपुर के पास देखिये, जहां पर सघन जंगल था वहां चट्टानें बाहर आ गई हैं। मैंने विश्वस्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त की है कि जमीन की बिक्री

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

में खास तौर से कैनाल लैंड की बिक्री, जो गंगानगर आदि क्षेत्रों में हुई है उसके लिए वहां के लोक सभा के प्रतिनिधियों से भी मुझे जानकारी प्राप्त हुई, कि इसमें लाखों रुपयों की धापा-धापी और गबन है। जो बेचने की व्यवस्था है उस पर सरकार जरा भी ध्यान नहीं देती, अगर देती है तो भ्रष्टाचार को पनपाने को प्रोत्साहन देती है।

आखिरी सूत्र मेरा है कन्ट्रोल की व्यवस्था के बारे में। आप चाहे लाइसेंस कहें, परमिट कहें, ये सब इसके अंतर्गत हैं, चाहे स्टेट एन्टरप्राइज कहें, चाहे कोऑपरेटिव्ज कहें। यह समाजवाद के प्रतिकूल व्यवस्था है, अनुकूल नहीं है। इनसे नागरिक स्वतन्त्रता का ह्रास होता है, इसमें संदेह नहीं है। इसी कन्ट्रोल के अन्दर आज भ्रष्टाचार व्याप्त है। ट्रैक्टर्स हैं तो स्पेयर पार्ट्स नहीं क्रूड आइल नहीं, सीमेन्ट नहीं, शक्कर नहीं, चावल नहीं, गेहूं नहीं। जिस चीज पर भी सरकार ने कन्ट्रोल लगाया वह चीज अन्डरग्राउन्ड चली जाती है। कन्ट्रोल का अर्थ है व्यवस्थित ढंग से वितरण होना, इसका यह अर्थ नहीं व चीज ही गायब। तो मेरे ख्याल से कन्ट्रोल की व्यवस्था एक घातक व्यवस्था है। इसका मैं कड़े से कड़े शब्दों में विरोध करता हूं और सरकार का पुरजोर शब्दों में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप डीकन्ट्रोल करें। आपको सब चीजों पर कन्ट्रोल नहीं करना चाहिए। यह प्रकृति के नियमों के विपरीत है, आपके पास अमला नहीं है, व्यवस्था नहीं है, आपके पास निष्ठावान् कर्मचारी नहीं हैं कि वे कन्ट्रोल की व्यवस्था के अन्दर सफलता प्राप्त करें। शक्ति से ज्यादा अगर कोई काम करना चाहते हैं, तो वह आपके बूते के बाहर होगा, तो फिर आपका सिर नीचे होगा और टांगें ऊपर होंगी। जयपुर में गेहूं का डीकन्ट्रोल हुआ, गेहूं आना शुरू हुआ। इस संबंध में हमारे माननीय नेता, श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने जो लेख लिखा है, वह पढ़कर बताता हूं; माननीय वित्तमंत्री भी सुन लें :

"Edmund Burke said that one of the most delicate problems in legislation was to determine what the State ought to take upon itself to direct by its wisdom and what it ought to leave with as little interference as possible to individual exertion.

Prof. Jewkes calls particular attention to the consequence of the expansion in size of undertakings, which fail to be adequately anticipated by governments. It is a common place that every organization, as it increases in size, must face the danger that further growth will bring decreasing efficiency.

There is a dangerous fallacy which has, in this connection been exposed by Prof. Jewkes. It is claimed that a government may take responsibility for some new public service but take the whole operation out of Politics and thereby escape any increase in its own administrative burdens. Experience in the past twenty years suggest that this view is naive. Nationalisation has not

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

taken industries out of the political arena. It has pushed them more firmly into it. Cabinets will always be tempted to court popularity by given way to democratic pressures for the provision of goods and services on exceptionally favourable terms or to uneconomic ends.

It has proved impossible to give any real meaning to the distinction between matters of national interest or major policy on the one hand and matters of day-to-day importance, on the other. The process of administration cannot be split up in this way. Wise policy on major matters can only be built up by careful scrutiny of day-to-day matters. No event, in the first instance can be levelled as a minor or a major matter. The manner in which a minor event is dealt with may determine whether it becomes a major one in the operation of the organization. The very choice of what is a major and what is a minor matter (which function must surely be regarded as part of major policy) can only be regarded as part of major policy, can only be exercised through day-to-day attention to what would normally be regarded as detail.

Even if it seemed otherwise desirable that the Government should undertake some new task, it is not always able to collect the necessary knowledge and develop the techniques to do what it sets out to do.

Public enterprise relies to a much greater degree than private upon statistics and measurements as instruments of control. A small manufacturer knows from long experience the details of his own business and will depend to a lesser degree upon figures than a government department which is operating a national industry and has to determine proper scales of output and correct regional and local distributions and so own. Some eminent statisticians have for long been warning us of the rickety statistical structures upon which most economic reasoning in these days is based. Quite recently, Professor Morgenstern has left us in no doubt as to the perils we run. He shows that even with American and British figures, which are perhaps the best in the world, critical statistics are being relied upon which have very wide margins of error."

(१. म. प.)

आपके आंकड़े भी गलत हैं। आगे यह भी कहा है :

"The big error fostered by over-confidence in the accuracy of economic statistics is the belief

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

that the economic future can be predicted. That way lies nothing but disenchangment.

Prof. Jewkes sums up what is as easy, as it is important, to remember, viz., that a government has nothing to distribute save what it first collects from the community, and that big organizations are not necessarily more efficient than smaller.

Size, far from being a virtue, constitutes the most persistent and troublesome peoblem in dealing with nationalized undertakings. This is a lesson which has been learnt in Great Britain. Nationalization has lost all its original attractions in Great Britain. But in India we have the experiment of the State Trading Corporation persisted in, notwithstanding the obvious handicaps arising out of size and heterogeneity incompatible with any effort at centralized management. That a State-managed monopoly can enable the Government to supply needy groups at low prices has proved to be an illusion. The plea is no longer heard now. The over-head charges arising out of bigness render such efforts futile. Even when a plan for improving the national level of economic prosperity has failed in respect of a near period, government expects to produce better results over a long period. This is based on the extra-ordinary belief, says Prof. Jewkes, "that the distant future can be more clearly seen and understood than the immediate".

Prof. Jewkes is convinced that the deeper a government involves itself in the working of the economic system, the more likely it is that it will allow its so-called economic decisions to be vitally influenced by political expediency.

Some of the greatest tyrannies have had their origin in the frustrations of those who have sought to do good by methods which were doomed to failure."

आपका जो इरादा है वह एक हद तक पाक है, लेकिन आप जो चीज करना चाहें, वह अगर नहीं कर पाते तो मेरे ख्याल से आपको पुनः विचार करना चाहिए। कन्ट्रोल्स के अन्दर स्केयरसिटी होती है। अन्ततोगत्वा जितने कन्ट्रोल्स बढ़ेंगे, वस्तुओं के भाव बढ़ेंगे। मैंने गत वर्ष इस सदन के समक्ष यह निवेदन किया था कि लाइसेंस, परमिट, कोटा, जो आपको इश्यू करनी हो वह मंत्री मंडल के द्वारा न दी जाये, बल्कि एक निष्पक्ष लाइसेन्सिग ऑथारिटी, कोई अराजनैतिक संस्था हो, कमीशन हो, कमेटी हो तो उसको दे दें। उसको आदेश दें कि वही परमिट व लाइसेंस दे। हर एक चीज का लाइसेंस और परमिट हो। आपको कन्ट्रोल का इतना अनुभव हो चुका कि क्या परिणाम इसका होता है, इसलिए जितना जल्दी इसको छोड़ेंगे उतना जल्दी राजस्थान का हित होगा।

चौथी योजना में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। आपको चाहिए कि पहली तीन योजनाओं

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
के संबंध में आप सिंहावलोकन करें और खामियों को ठीक करें, टैक्स कम करें, नॉन-टैक्स रेवेन्यू बढ़ाएं और डिकन्ट्रोल करें। विकास किस कीमत पर आपने किया है, इस संबंध में आपको गहराई से विचार करना होगा, विकास हुआ है या विनाश हुआ है. यह सोचिए। इस विकास के साथ भ्रष्टाचार का विकास हुआ है या नैतिक विकास हुआ है, यह सोचिए। वास्तव में अव्यवस्था का विकास हुआ है। मैं समझता हूं कि सिवाय नौकरशाही का बोल-बाला होने के, उसका विकास होने के और कोई विकास विशेष हुआ हो, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता।

अब मैं अकाल के संबंध में प्रकाश डालता हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने यहां पर निवेदन किया कि अकाल के संबंध में आपको कोई फेमिन रिलीफ फंड के नाम से संस्था को स्थापना करनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से उत्तम हो जाये। आपके पास पैसा नहीं बचता; अगर बचे तो फेमिन रिलीफ के रूप से कोई न कोई फंड क्रीएट करें।

आर्म्ड कॉन्सटेब्यूलरी और अकाल के संबंध में वित्त मंत्री ने कहा कि बहुत खर्चा करने से बजट पर भार पड़ा है। मेरा निवेदन है कि आर्म्ड कॉन्सटेब्यूलरी के संबंध में केंद्र को आप आमादा करें कि यह सुरक्षा के संबंध की व्यवस्था है, वह खर्चा केन्द्र को वहन करना चाहिए न कि राजस्थान को। अगर राजस्थान देता है तो गलत है। आपने केंद्र के सामने गलत आधार रखा है। केन्द्र को आप मजबूर करें कि अगर सारा नहीं तो ३।४ खर्चा वह वहन करें। अगर यह नहीं होता है तो वह आपकी कमजोरी है।

फेमिन रिलीफ के संबंध में आप कहते है कि डेढ़ करोड़ खर्च किया है। अगर ९६ करोड़ में से डेढ़ करोड़ खर्च किया है तो नगण्य है।

सोशियल वेलफेयर बोर्ड की ऑडिट के संबंध में हमारी पार्टी के एक माननीय सदस्य ने कहा कि १० वर्ष तक ऑडिट नहीं हुई। इस ओर जब आपका ध्यान आकर्षित किया गया तो आपने मजबूरन शर्म से और लज्जा से, अपने मुंह को झुका दिया, आंखें झुका दीं और शर्म का पर्दाफाश करके क्या व्यवस्था की?

अध्यक्ष महोदय, मैंने विन्ड मिल्स के सम्बन्ध में भी प्लानिंग बोर्ड की सब-कमेटी में एक सुझाव रखा था। विन्ड मिल्स मारवाड़ में पीने के पानी के सम्बन्ध में स्थापित किये जा सकते हैं। विन्ड मिल्स को मैंने हॉलैन्ड में देखा है, इन्डिया में, मैसूर में, मद्रास में, देखा है। यदि ये राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में भी काम में लाये जावेंगे, इसको आजमाइश करके देखिये, मेरे खयाल से अवश्य लाभ होगा। न बैल का खर्चा, न तेल का खर्चा, न इन्जन लगाना पड़ता है, बाल बीयरिंग से ही चलाने पड़ते हैं। अपको एक चेबचे की आवश्यकता पूरी करनी पड़ेगी। हवा चलेगी और हवा के जरिये से घूमेगा और चेबचे में पानी आता जावेगा। यदि आप हमारे क्षेत्र में पांच-पांच मील के एरिया में भी स्थापित करें तो कुछ का कुछ हो सकता है। भूमि-हीन को जमीन देना है तो आप विन्ड मिल्स स्थापित करियेगा, तो भूमि-हीन को जमीन देने का कोई अर्थ है नहीं तो विन्डो ड्रेसिंग है। जमीन का अलॉट-मेन्ट कर दिया उससे वह क्या अपना कपाल फोड़े?

इसके अलावा मैं निवेदन करूं, अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि १३

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

करोड़ का ऋण लेना पड़ा है मैं इसको समझ सकता हूं । लेकिन सरकार मितव्ययता की तरफ ध्यान देती, और प्रॉपर प्रॉयोरिटीज की तरफ ध्यान देती तो, १३ करोड़ के बजाय ६ करोड़ का ही ऋण लेना पड़ता । आप कहते हैं कर्ज लेना अच्छा है । 'अति सर्वत्र वर्जते', एक हद तक कर्ज लेना ठीक है । राष्ट्र है वह सद्गृहस्थ है । एक सद्ग्रहस्थ की आमदनी पन्द्रह हजार सालाना है और यदि वह ३० हजार रुपया सालाना खर्च करता है तो वह सद्गृहस्थ नहीं है, दिवालिया है । माननीय वित्त मंत्री की थाली और लौटे में छेद पड़ गये हैं और वे छेदों को बन्द करना चाहते हैं, तो उनकी थाली में इतने छेद पड़ चुके हैं, कि वह छलनी हो गई है । उसमें जो कुछ आता है सब निकल पड़ता है । आप अपने भेजे को खामख्वाह सड़ाते हुए छेदों को बन्द करना चाहते है वे तो बड़े बन रहे हैं । मैं तो कहता हूं कि 'cut your coat according to cloth' अपनी हैसियत के अनुसार व्यवस्था कीजिये। मानता हूं गोइंग इकॉनोमी है । नाम मात्र की छलनी देकर वह व्यवस्था करते हैं तो दुर्व्यवस्था की पराकाष्ठा है । माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करूं, कि वे सोचें तो सही कि यदि पी. एल. ४८० के अन्तर्गत अमेरिका से गेहूं न आवे तो क्या स्थिति हो हमारी ? इस पर सोचिये ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यदि नहीं देगा अमेरिका, तो मुकाबला करेंगे परिस्थितियों का ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : करेंगे । आपके विचार हैं ! मत-मतान्तर है ! इससे मैं सहमत नहीं हूं, अध्यक्ष महोदय !

अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री महोदय, ने टैक्स लगाये । वाहनों पर टैक्स लगाया, यात्री पर टैक्स लगाया, पशुओं पर टैक्स लगाया । इसी सदन में पहले पशुओं पर टैक्स लगाया, तो बड़े परिश्रम से हमने उसको मंसूख कराया । आपने पशुओं पर फिर टैक्स लगा दिया इससे बड़ी-भारी इस सदन की तौहीन और क्या हो सकती है ?

आपने तेल, घी पर टैक्स लगाया । इस तरह चुटकियां भर-भर कर कब तक घाटा पूरा करेंगे ? दोनों एन्ड्स मीट कहां होते हैं ? इतना घाटा है कि छोटे-मोटे टैक्स लगाने से कोई लाभ नहीं । नॉन-सीरियल की सिंचित खेती पर भी टैक्स लगाया । मैं समझता हूं इससे खुशहाली नहीं आ सकती है । खुशहाली आ सकती है, टैक्स घटाने में, मितव्ययता करने में, उत्पादन बढ़ाने में, भ्रष्टाचार, लाइसेन्स, कोटा और परमिट को घटाने में ।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही निवेदन करके मैं यह निवेदन करूंगा कि आज राजस्थान राज्य की आर्थिक दशा बुरी है और मैं उसको बुरी की संज्ञा देकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : (कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) श्री महार बोलेंगे, फिर मंत्री महोदय ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अध्यक्ष महोदय........

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): उनकी तरफ से बहुत बोल चुके हैं ।

Page No. 52

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : मैं बोल लूं और जो दूसरे मुद्दे आवेंगे उनका फिर दूसरे मंत्री जवाब दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : आप पहले बोल लीजिये।

श्री मानसिंह महार : मैं आपके बाद फिर बोलूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, बजट की जनरल बहस के सिलसिले में हमारी बहस का आखरी दौर चल रहा है। उस सिलसिले में, मैं अपने विचार सदन के सामने रखना चाहता हूं। पिछले चार दिनों से लगातार सभी माननीय सदस्यों की बहस को सुन रहा हूँ और इस बजट के सिलसिले में जो वातावरण सदन के माननीय सदस्यों ने बनाने की कोशिश की, उसको जैसा मैं समझ पाया उसको ध्यान में रखते हुए, मुझे यह अहसास हुआ कि हम कई बार काफी वस्तु-स्थिति से परे जाने की कोशिश करते हैं और जो हमारे सामने वास्तव में गहन और मुख्य मुद्दे हैं, उनके ऊपर जितनी तवज्जह देनी चाहिये, और उसके बारे में जितना इसका एक रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये, उसकी हमारे यहां पर कमी रहती है। इस बजट के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने, विरोधी पक्ष के लोगों की बात छोड़िये। समर्थन में भी जो कुछ बातें कहीं और वे समर्थन करेंगे, उससे मुझे ऐसा अहसास हुआ है कि हम कई बार इस सदन में बैठ कर यह सोचते हैं कि बजाय जो कुछ हो रहा है या जो कुछ काम जारी है और जिसको करने के लिये और भी गुन्जाइश हो सकती है उन मुद्दों के बारे में विशेष चर्चा न करके उन्हीं बातों की तरफ ज्यादा जोर देते हैं कि जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि इस बजट में गावों के लिए, किसानों की सुविधा के लिये, राज्य की जनता के लिये, उनकी तरक्की के लिये, उनकी बेहतरी के लिये, कुछ नहीं हो रहा है। इस प्रकार का अहसास जब सदन में चारों तरफ से आने लगता है, तो सरकारी बैन्चेज में बैठने वाले लोग हैं उनके मन में भी इस प्रकार का दुःख होता है कि सचमुच में आज सोचने और करने की बहुत बड़ी गुन्जाइश है और करना चाहिये, क्योंकि राजस्थान और इस देश में प्रजातन्त्र के जरिये से ही, विधान सभाओं और पार्लियामेंट के जरिये से ही, हम को देश की आर्थिक स्थिति को सुधारना है।

तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि यह बजट जैसा अभी विरोधी पक्ष के माननीय नेता ने कहा, हमने जब से राजस्थान बनाया और राजस्थान बनने के बाद में यह १५ वें वर्ष का बजट है, हम कहां से शुरू हुए और कहां तक पहुँचे हैं ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : रसातल में पहुँचे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप मेहरबानी करके खामोश रहें तो अच्छा है।

रसातल में तो आप चले ही गये हो और चले जाओगे। तो मैं निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, पहले १६ करोड़ का बजट और प्रथम पंचवर्षिय योजना में १८ करोड़ का बजट जहां से हम शुरू हुए आज हमारा ६६ करोड़ का बजट है। बजट को इस सदन में राजस्थान की जनता के सहयोग से राजस्थान की इस सरकार ने पेश किया। ६६ करोड़ का बजट जो इस साल के लिये इस प्रान्त की जनता को आगे

(श्री नाथूराम मिर्धा)

बढ़ाने के लिए है, जो बजट हम बनाते हैं, वही देश का उत्पादन बढ़ाने के लिये, कारगर होता है। सदन के सभी लोग मानते है कि प्रजातान्त्रिक तरीके से देश की आर्थिक स्थिति को ऊंचा करना है तो योजनाओं का सहारा लेना पड़ेगा। इन योजनाओं में ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करके, जरूरत की चीजें है उनको मुहैया करके उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा।

अगर हम इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं, योजनाबद्ध तरीके से आर्थिक जीवन का आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हिन्दुस्तान के विधान की जो परम्परा है, जो परम्परा हमने अपने विधान द्वारा अपनायी है, वह दुनियां के किसी देश के साथ मेल नहीं खाती। इन सारी बातों को अगर ध्यान में रखें तो वित्त मंत्री महोदय ने जिस नीति का प्रतिपादन अपने भाषण में किया है, जितना साफ शब्दों में रखा है, जिस प्रकार स्पष्ट रूप से आंकड़ों द्वारा उस स्थिति को रखा है, वैसा पहले कभी नहीं रखा गया था। इन्होंने इस राज्य की आर्थिक तस्वीर पूरी तरह से सच्चाई के साथ सदन के सामने रखने का प्रयास किया है वह तारीफ के काबिल है। यह मैं समझता हूँ इन पन्द्रह वर्षों में यह अपनी तरह का पहला प्रयास है। फिर भी सदन में आलोचनायें होती हैं। विरोधी पक्ष के सदस्यों ने ही नहीं, इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने भी इसको कोसा है। कर्जों का बोझ बढ़ता जा रहा है, टैक्सों के भार से जनता दबी जा रही है। करों से जनता की हड्डी टूट गई है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : यह तो वित्त मंत्री खुद मानते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं सब जानता हूं, आप हमेशा करों का विरोध करते रहे हैं। सदन में और सदन के बाहर भी, आपने विरोध किया है। आपने लोगों से यह भी कहा है कि यह सरकार दिवालिया होती जा रही है। योजनायें चला-चला कर दिवालिया होती जा रही है। आपके कहने के अनुसार टैक्सों का भार खतरे की स्टेज तक पहुंच गया। संभल कर कदम नहीं रखते हैं, ज्यादा कर्जा करते चले जा रहे हैं। हम यह मानते हैं कि हमने कर्जा किया है अल्प-बचत योजनाओं के जरिये जो रुपया आता है वह भी प्राप्त किया है, लेकिन जैसा हमारे विरोधी पक्ष के नेता कहा करते हैं कि अपना कोट उतना ही काटना चाहिये, जितना कपड़ा है। मैं उनकी इस राय से सहमत नहीं हो सकता। मैं इस सिद्धान्त से भी सहमत नहीं हूं। हमें तो कोशिश यह करनी है कि इस देश की जनता जो पिछले हजारों वर्षों से पुरानी राज्य-प्रणाली के कारण उनके तौर-तरीकों के कारण जो जनता दबी हुई थी, जो गरीबी बेकारी और भुखमरी फैली हुई थी, उनको खूनी क्रान्ति के जरिये दूर न कर, हमारे विधान के अन्दर विश्वास रखते हैं वे इस देश के अन्दर प्रजातान्त्रिक तरीके से आर्थिक सुधार करने की व्यवस्था करते हैं। इस सदन में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस समय सदन में नहीं हैं, बाहर बैठे हैं। वे अपने तरीके से अपना काम कर रहे है जिसको वे अपने दृष्टिकोण से रचनात्मक काम समझते हैं। ऐसे लोगों ने अपने देश में एक प्रकार का रवैया बना रखा है कि देश में किसी भी तरह से हो अशान्ति के कीटाणुओं को पैदा किया जाय और उन दूषित कीटाणुओं से देश के वातावरण को बिगाड़ा जाय, इसमें उनको सफलता मिली है। बंगाल में जो कुछ हुआ

(श्री नाथूराम मिर्धा)

वह इन्हीं लोगों के कारण हुआ। आज देश में कई जगह ये हालत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब की जो समस्या थी उसको जिस प्रकार सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है उसमें भी दूषित वातावरण किया जा रहा है। इससे भी कुछ लोग अपने नतीजे हासिल करना चाहते हैं। आज देश इस प्रकार की स्थिति से गुजर रहा है। आज स्थिति यह है कि हमें इन सारी बातों की तरफ सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्या हम इस तरह से चारों तरफ अशान्ति पैदा करके इस जनतन्त्र को कायम रख सकेंगे, लोगों के आर्थिक जीवन को ऊंचा उठा सकेंगे? आज हमने जिस प्रणाली को अख्तियार किया है दुनिया के किसी देश में वह प्रणाली चालू नहीं है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आप शासन के कारनामें ठीक करिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप जरा ठंडे दिमाग से सुनिये।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपके इस प्रकार के भाषण सुनते-सुनते चार वर्ष हो गये।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो प्रणाली यहां हमने अपनायी, अपने देश की जनता ने अपनायी है उसी के आधार पर हम देश में आर्थिक विकास करना चाहते हैं। उसी से देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं! हिन्दुस्तान की बहुतायत जनता इस प्रणाली को ठीक मानकर चल रही है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : इस प्रकार के उपदेश तो चौपड़ पर देना शुरू करें।

श्री नाथूराम मिर्धा : आज हम देश में इस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं कि देश के लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रजातंत्र में आस्था रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें और देश की जनता की आर्थिक स्थिति सुधारे। बहुमत इस सदन में भी इस प्रणाली में विश्वास रखता है। आज जिन हालतों में हमारा देश गुजर रहा है उसमें सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। आज देश में जिस प्रकार की स्थिति चल रही है उसका भार आज इधर बैठने वाले सदस्यों पर पड़ता है उतना ही भार माननीय सदस्य उधर बैठे हैं उन पर भी पड़ता है। अगर हमें योजनाओं को आगे बढ़ाना है ज्यादा से ज्यादा लोगो का विकास करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हालत को सुधारना है, पर केपिटा इन्कम बढ़ाना है, लोगों के लिये रोजगार की व्यवस्था करना है, तो हमें योजना की रफ्तार ज्यादा तेज करनी होगी। हमारे प्रान्त के अन्दर हमारे राज्य के लोगों पर टैक्स के दृष्टिकोण से बोझ ज्यादा है वह अन्य राज्यों से तीसरे नम्बर पर आता है। भूमि के लगान का बोझ दूसरी स्टेट्स से तीसरे या चौथे नम्बर पर आता है। दूसरी तरफ कर्ज का जो भार हमारी स्टेट पर है वह अन्य स्टेट्स से नीचे तीसरे नम्बर पर है.......

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आप यह तो बताइये, प्रति व्यक्ति आय आपके इन योजनाओं से कितनी बढ़ी है?

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सदस्य जरा शान्त रहें। मैं भैरोंसिंहजी से निवेदन करूंगा कि वे अपने दल के सदस्य को जरा शान्त रहने के लिये कहें।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े तो कल ही बता दिये जबकि आप हाजिर नहीं थे।

श्री नाथूराम मिर्धा : कल कुछ आंकड़े दिये। वे आंकड़े राज्य सरकार बनाती है, वे आंकड़े सही हैं। जहां प्रति व्यक्ति पर खर्च का सवाल है, हमारी स्टेट के प्रति व्यक्ति पर दूसरे राज्यों की सिरीज में दूसरी या तीसरी सिरीज में है। पर केपिटा जो एक्सपेन्डीचर कर पाते हैं उसके हिसाब से दूसरे कई राज्यों के हिसाब से काफी बड़ा बोझ टेक्स का हमारे राज्य की जनता पर है।

इस राज्य की पुरानी परम्परायें थीं वे सब इन सभी चीजों के लिये जिम्मेवार हैं। पहले यह राज्य बाईस हिस्सों में बटा हुआ था, अलग-अलग सब जगहों का बजट था जब एकीकरण हुआ। एकीकरण के बाद टैक्सेज के नये सोर्सेज बने, सबके लिये एक प्रकार के कॉमन सोर्सेज बने। ज्यों-ज्यों हमने ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ने की कोशिश की उससे ज्यादा बोझ जनता पर पड़ा है। यह बात हम नहीं सोचते हों या हम इस बारे में जागरूक न हों, यह बात नहीं है। यह हम जानते हैं कि काफी बड़ा बोझ पिछले पन्द्रह वर्षों में योजनाओं को चलाने के लिये राजस्थान की जनता ने उठाया है; उसमें चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे पूंजीपति हो इन सब पर ज्यादा बोझ आया है। इस तरह से जहां हमने योजनाओं का विस्तार किया है लोगों पर करों का बोझ पड़ा है। आज जिस स्थिति से हमारा प्रान्त गुजर रहा है, हमारा देश गुजर रहा है उसमें हमें आने वाले दस वर्ष और मुश्किल के निकालने पड़ेंगे।

अभी तक आने वाली दो योजनाओं के अन्दर राजस्थान की जनता को यहां के लोगों को अपने पांवों पर यदि आर्थिक दृष्टिकोण से खड़ा होना है तो आने वाले दस साल के लिये विरोधी पक्ष के नेता महोदय को कमर खींचनी पड़ेगी........

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : आपका बहुमत है, जो भी आप करेंगे उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : आज बहुमत है, आगे क्या होगा, यह मैं नहीं कहता। लेकिन मैं जो यह निवेदन कर रहा हूं वह अगर आप भी इस जगह पर आये तो आपको भी इस बारे में सोचना पड़ेगा, नहीं तो लोग आपको छः महीने भी टिकने नहीं देंगे।

अगर हम इन तरीकों से योजनाओं के जरिये लोगों की आर्थिक स्थिति, उनकी बहबूदी बढ़ाना चाहते हैं तो आने वाले दस सालों के लिये हमें कष्ट उठाने पड़ेंगे। जब राजस्थान राज्य बना उस समय बिजली का नामो-निशान नहीं था। सिंचाई के लिये कुंओं का प्रबन्ध नाम मात्र था। काली डामर की सड़कें केवल शहरों को छोड़कर देखने को नहीं थीं।

शिक्षा के अन्दर, कुल राजस्थान में प्राइमरी स्कूलों की संख्या ४०० थी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप बीस साल पहले की बातें करते हैं। आप यह भी कह सकते हैं राणा सांगा और प्रताप के समय में ऑटोमेटिक वेपन्स नहीं थे, हाइड्रोजन बॉम्ब्स नहीं थे। उस समय की व्यवस्था के अनुकूल उस समय चीजें थीं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपकी बात हमने सुनी। अब आप मुझे थोड़ा कहने दीजिये। २४।। हजार प्राइमरी स्कूलें हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सारे राजस्थान में प्राइमरी स्कूलों की संख्या पहले ४०० ही थी? मैं इसे चैलेन्ज करता हूं। अकेले मेरे वक्त में डूंगरपुर में १५० थीं और शिक्षा के स्तर में आज के स्तर से कहीं अधिक ऊंची थी, कम तो किसी कदर नहीं थीं।

श्री नाथूराम मिर्धा : I am sorry, चार हजार थीं।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आपने एक बिन्दी तो बढ़ाई, एक और बढ़ा दीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : I am sorry, चार हजार थीं; अब यह संख्या २४।। हजार हो गई है।

राजस्थान में कुल मिलाकर ६०० लाख सिंचाई योग्य धरती में से कुल दो लाख में पहले खेती होती थी और सिंचाई का परसन्टेज कुल मिलाकर ३० लाख एकड़ का था और नहरों की सिंचाई से ९ लाख धरती में सिंचाई होती थी राजस्थान बना उस वक्त।

अब उस राजस्थान में जहां सिंचाई के साधनों को बढ़ाने की व्यवस्था करने की आवश्यकता है, बिजली फैलाने की आवश्यकता है, सड़कें गांव-गांव में पहुंचाने और बड़ी-बड़ी सड़कों के जरिये छोटी-छोटी सड़कों को लिंक करने की आवश्यकता है, स्कूलों को बढ़ाने की आवश्यकता है और उद्योग-धन्धे बढ़ाने के लिए बिजलीकरण की आवश्यकता है—इन सब आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर १८ करोड़ से बजट बढ़ता-बढ़ता आज ९६ करोड़ का हो गया।

अब जो कहा गया कि गांवों की बहबूदी के लिए कुछ नहीं है इस बजट में, मैं बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल की योजना के बजट में जो ३६।। करोड़ का है उसमें से १२ करोड़, १६ करोड़ की राजस्थान नहर की व्यवस्था, ५।। करोड़ की अलग व्यवस्था है, उसे छोड़ दीजिये, १६ करोड़ की सिंचाई की योजना, ८ करोड़ की एग्रीकल्चर को सुधारने की व्यवस्था—यों कुल ३६।। करोड़ रुपयों में इन तीन मदों का ही बड़ा-बड़ा हिस्सा है जो गांव और किसान की बहबूदी के लिए है। इस पर आप कहते हैं किसान और गांव की तरफ ध्यान नहीं, यह सही नहीं है।

श्री मानसिंह महार : कमाल कर रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे हिसाब से तो बिलकुल कमाल ही है।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि जहां इतने बड़े-बड़े प्रावधान गांवों और किसानों की बहबूदी के लिए किये गये हों वहां सदन के माननीय सदस्य कहें कि गांवों की तरक्की के लिए गौर नहीं किया है....

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०) : फिर भी अन्न नहीं मिल रहा है, लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, आपको कोस रहे हैं; ऐसे दिन कभी नहीं देखे! अमेरिका से भीख मांग रहे हो।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो इन मामलों में आप राजनैतिक दृष्टिकोण न अपनावें, कि वस्तु-स्थिति से ही परे चले जावें। इतनी छोटी छोटी बातों को मैग्नीफाई करके चर्चा करना, यह वस्तु-स्थिति से परे जाना है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सदन से निवेदन करना चाहता हूं, कि राजस्थान में जब हमने इन योजनाओं के काम को हाथ में लिया, मैंने पहले भी कहा था, तो कई बार सदन में चर्चाएं आती है कि खाद्यान्न उत्पादन तेजी से बढ़ाना चाहिये जो कि देश का प्राथमिक काम है क्योंकि जितना ज्यादा हम इसे पैदा करेंगे वह काम में आने वाला है; तो जैसा मैंने निवेदन किया खाद्यान्न के उत्पादन में भी हम आगे बढ़े हैं। २६ लाख टन से चलते चलते ६४-६५ में हम ५२ लाख टन के लगभग पहुंच गये। ६१-६२ में हमने ५४ लाख टन का उत्पादन किया। इस साल २४ जिलों के १२ हजार गांवों में अकाल की स्थिति है। इसके उपरान्त भी जो कुछ भी आंकड़े हैं वे सामने नहीं आये हैं, पर जैसा मैंने पहले भी कहा था कम से कम ५५ परसेन्ट का उत्पादन रबी और खरीफ का दोनों मिलाकर हमने किया है।

स्वर्गीय श्री शास्त्रीजी की अपील पर गांव गांव में चेतना आई। सरकारी विभागों ने भी ज्यादा जिम्मा हाथ में लेने की कोशिश की। लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के बारे में तुरन्त प्रोग्राम बनाया गया। किसानों ने उत्साह से इसमें हिस्सा लिया और माननीय अध्यक्ष महोदय, खास तौर से सीकर झुंझुनू जैसे इलाके में कम से कम इस बार २०-२२ हजार एकड़ में नया इरिगेशन, जो कई वर्षों में नहीं हुआ या पुराने कुओं को ठीक करने का टारगेट अचीव किया।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : सीकर, झुंझुनू जिले में एक साल में ?

श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) : यह तो लोगों ने किया जो कुछ किया, सरकार ने क्या किया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं तो यह निवेदन और करना चाहता हूं कि जो यह कहते हैं कि लोगों को सरकार की योजनाओं में विश्वास नहीं है, जनता में विश्वास नहीं है उनको मालूम हो जाना चाहिए कि लोग कितना विश्वास करते हैं और लोग अपने पांव पर खड़े होना जानते हैं और इस वजह से सरकार से सहयोग करते हैं और इसी वजह से जनता ने सीकर और झुंझुनू जिले में १२ हजार एकड़ में अतिरिक्त उत्पादन किया है। आपको ताज्जुब हो रहा है ?

श्री भैरोंसिंह : ताज्जुब तो यह हो रहा है कि आप गलत बोल रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : सदन में खड़े होकर बोलने से काम नहीं चलता है, डिटेल में जाने की आवश्यकता है। आप बीमार थे, उधर जा नहीं सके फिर आपका वह क्षेत्र नहीं रह गया अब। आपका क्षेत्र जयपुर हो गया। सीकर झुंझुनू में आपको विशेष रूचि भी नहीं है।

फिर सरकार के विशेष प्रयत्न के जरिये १२ हजार एकड़ में लिफ्ट इरिगेशन उस जमीन में हुआ, जो खारड़ा और खड्डों में पड़ी थी। हमने कोशिश करके उसमें उत्पादन बढ़ाने और रबी का प्रोडक्शन अकेले जालोर

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जिले में ४० हजार एकड़ में इरिगेशन के साधन बढ़ाकर बढ़ाया । एक साल में । झालावाड़ जिले में दस हजार एकड़ में उत्पादन बढ़ाया । इन सारी चीजों में एक एक की डिटेल में जाकर देखते हैं, केवल भाषण नहीं देते है ।

इसलिए मैं बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि चम्बल की चर्चा चल पड़ी कि वैज्ञानिक लोग खड़े होकर कहने लगे कि पानी ज्यादा तो ड़ा नहीं कर लिया ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपका मतलब यह है कि हम कोई बात ही नहीं कहें ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बात कहें, पर सोच समझ कर कहें । मैं आपके मुंह पर ताला थोड़े ही लगा सकता हूं । पर जो कुछ कहें मुद्दे की बात कहें ।

(शोरगुल—अश्रव्य)

तो मैं निवेदन कर रहा था माननीय अध्यक्ष महोदय, कि चम्बल का प्रोजेक्ट जिस दिन से ......

(शोरगुल—अश्रव्य)

... जीवराजजी, तशरीफ रखिये ।

चम्बल के इस प्रोजेक्ट की ऐसे नक्षत्रों में नींव लगी कि कोटा-बूंदी के खास तौर से जो वोकल एलीमेंट्स हैं, उनको अच्छा नहीं लगा । प्रोजेक्ट को दो तीन फेज में बनना है पहला फेज पूरा हो गया, मामूली सी छोटी मोटी बात को छोड़कर । इसमें सरकार ने ६२ करोड़ की धनराशि खर्च की । वहां के किसानों को एक लाख ६० हजार एकड़ भूमि में रबी का पानी दिया । कहीं पर एक बार, कहीं पर दो बार और कहीं पर तीन बार ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अब की बार गांधीसागर में पानी की कमी है, इसमें आपकी गलती नहीं है, पर आप आंकड़े जो बता रहे हैं कितनी कितनी बार दिया पानी, वह गलत है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : एक बार, दो बार तीन बार और चने को तो दिया दो बार ।

श्री हरिप्रशाद शर्मा (पाटन) : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, ये मन्त्री महोदय,....

(व्यवधान)

मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है । अध्यक्ष महोदय, जो सूचना माननीय मन्त्री महोदय दे रहे हैं उसके बारे में आंकड़ों में हो सकता है कि इतना दिया हो और मैं उन गांवों में अभी अभी होकर आ रहा हूं, लोग बड़ी परेशानी में हैं । आप गलत पैसा वसूल कर रहे हैं । आप बता सकते हैं कि आप कितना पैसा-लेंगे ? सही तथ्य तो यह है कि लोगों को पानी नहीं मिला है और हजारों एकड़ में गन्ना सूख गया है और उसके विपक्ष में आप उनसे पूरी रकम वसूल कर रहे हैं । तो आप इसकी जानकारी करें और सदन को गलत सूचना नहीं दें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में तो कल पूरा एक दिन है, उस समय मैं खुलासा बताऊंगा । आप कटौती के प्रस्ताव रखिये और उस पर बोलिये, मैं जवाब दूंगा और जरूर दूंगा । मैं तो इस समय जनरल टाइप में मोटी मोटी बातें कह रहा हूं । छोटी छोटी बातें तो कल कहूंगा ।

Page No. 59

(श्री नाथूराम मिर्धा)
एक दिन पूरा है और आप पूरी तरह मे दिलभर कर बातें कहिये, मैं सुनूंगा और दिन पूरा है फिर उनका दिल भर कर जवाब दूंगा। अगर कोई गलती रही तो उसकी आगे व्यवस्था करेंगे। आपका कहने का काम है और मेरा सुनने का काम है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चम्बल के बारे में कई डिफेक्ट्स हैं। मैं इसको डिनाई नहीं करता। ६२ करोड़ रुपये का खर्चा करके ५ लाख एकड़ की व्यवस्था की। यह तो मोटा काम हुआ। मैं नहीं कहता कि उन छोटे छोटे कामों में अव्यवस्था नहीं हैं। अव्यवस्थायें सभी जगह हैं और उनको दूर भी किया जाता है।....

श्री अध्यक्ष: यह ५ लाख एकड़ का कब होगा?

श्री नाथूराम मिर्धा: इसका ५ लाख का इरिगेशन होगा।

श्री अध्यक्ष: उसमें से कितना हुआ है?

श्री नाथूराम मिर्धा: २ लाख ६० हजार एकड़ के अन्दर किया है लास्ट ईयर।

श्री भैरोंसिंह: इसी बीच में मन्त्री महोदय बतायेंगे कि थर्ड फाईव ईयर प्लान का लास्ट ईयर का अपना फेज प्रोग्राम था; इरिगेशन पोटेन्शियल को कितने परसेन्टेज मे यूज करना है वह यह सही है कि पूरा नहीं हुआ।

श्री नाथूराम मिर्धा: मैंने आपसे निवेदन किया कि जहां तक इसका प्रश्न है मैंने आगे भी कहा था कि Rajasthan stands at the top in the whole of India.

श्री भैरोंसिंह: क्वेश्चन यह नहीं है कि वह आल इन्डिया में टोप स्टेन्ड करता है।

श्री नाथूराम मिर्धा: 92 per cent of water stored has been used last year in Rajasthan.

श्री भैरोंसिंह: मेरा क्वेश्चन यह भी नहीं है। मेरा क्वेश्चन है कि आपके प्लान के अनुसार जो आपका फेज प्रोग्राम है उसके अनुसार जो टारगेट्स थे वे आपने एचीव किये या नहीं?

श्री नाथूराम मिर्धा: वह कल बता दूंगा। आज तो मैं बड़ी बड़ी बातें कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में इरिगेशन के बारे में थोड़ी सी बातें इसलिये कह दीं और भाखरा की भी कहूंगा, फ्लड कन्ट्रोल के बारे में भी कल कहूंगा, क्योंकि कल पूरा दिन इसी के लिए है और कृषि के लिए भी बहुत डिटेल में जाने के लिए एक दिन रखा है। इसलिए उस दिन कृषि के ऊपर भी बहुत डिटेल मे कहूंगा। मैं मोटी मोटी बातें इसलिए कह रहा था कि इस योजनाओं के मोटे पहलुओ मे जिसमें करोड़ों रुपयों की व्यवस्था की है और इस साल भी ३६॥ करोड़ में जहां १२ करोड़ बिजली पर १० करोड़ कृषि और सिंचाई के ऊपर, और १६ करोड़ सिंचाई की परियोजनाओं के ऊपर खर्च करने जा रहे है और इसके अलावा बाकी थोड़ा बहुत बजट सोशियल एमिनिटीज के ऊपर रखा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार में बैठने पर मुझे यह स्वीकार करने में एतराज नहीं है कि पिछली साल की योजनाओं

(श्री नाथूराम मिर्धा)

में जो प्रावधान था वह ४८-४९ करोड़ का था और इस साल क्योंकि कोर ऑफ दी प्लान को हमने माना है और इसलिए उसमें कुछ कटौती करनी पड़ी है। जिसके बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी बोलेंगे उस समय बतायेंगे, इस समय ३६।। करोड़ रुपये की योजना कर पाये हैं। यह हमारे लिये दुख की बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि देश जिन परिस्थितियों में से गुजरा वह सभी को भली भांति मालूम है। पाकिस्तान का हमला हुआ, चीन की तरफ से गड़बड़ी रही और सीमान्त के ऊपर हमारा इतना अधिक खर्च हो और भारत सरकार की तरफ से राज्य सरकार को कान्ट्रीब्यूशन इस योजना में मिला था वह २८ करोड़ रुपया इस साल राज्य सरकार को मिला है इसलिए हमारे साधन भी सीमित थे और भारत सरकार से भी कम आया तो जितना बड़ा आकार हम चौथी योजना के अन्दर बनाकर चले थे उस स्कीम से कुछ नहीं कर पाये हैं उसके लिए हमें दुख है और इसके लिए हमें और भी ज्यादा तेज गति से काम करना पड़ेगा और यदि हम बड़े आकार को लेकर चलना चाहते हैं तो सदन के इन माननीय सदस्यों का कर्त्तव्य हो जाता है कि हम ज्यादा से ज्यादा उसके लिए साधन इकट्ठे करें।

बहुत बड़े आंकड़े माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट में दिये हैं और कहा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो भी तस्वीर पूरी की उस योजना के आकार के बारे में जितना हमने सोचा था उसमें ज्यादा किया। हम साधन जितने जुटा पाये वह जनता ने और सरकार ने मिलकर दोनों ने योजनाओं में लगाकर उनको पूरा किया और जो हमने उधार लिया था वह भी वादा हमने पूरा किया। अल्प बचत के अन्दर जो भी माना था उसके अन्दर थोड़ा कम रहा। इतने साधन जुटाने के बाद योजना का आकार कम रहा, उसका कारण था कि राजस्थान के दूसरे खर्चे जो बढ़ जाते हैं कर्मचारियों के कुछ सहूलियतें देने के संबन्ध में, फेमिन की अवस्था को मीट करने के लिए। सदन के सभी माननीय सदस्य विचार करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में अकाल की साइकल इतनी तेज घूमी कि ५ वर्षों में ३ वर्ष हमें उसका सामना करना पड़ा और इसी कारण फेमिन वर्क्स पर ज्यादा खर्च करने की वजह से योजनाओं के अन्दर हम बहुत ज्यादा खर्च नहीं कर पाये और फेमिन के कामों में ज्यादा पैसा लग गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, फेमिन के बारे में भी वही काम सरकार ने प्रायोरिटी से अपने हाथ में लिये हैं जो कि अलग अलग इलाकों में हैं। ११,५०० गांवों में हमारे यहां अकाल रहा वहां लोगों को काम काज मिला. वहां पर लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था की। इन सब कामों को करने के लिए हमने अन्दाजा लगाया है कि ७-८ करोड़ रुपये की धनराशि आने वाले महीने के अन्दर खर्च करनी पड़ेगी। अगर हमारे यहां अकाल नहीं होता तो यह ८ करोड़ की धनराशि हम दूसरे कामों में लगाते और उससे हमारी योजनाओं का आकार बड़ा होता।

इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल की बात आदमी के हाथ में नहीं होता, यह ईश्वर के हाथ की बात है और ईश्वर की बातें इन्सान के हाथ की बात नहीं होती। इन्सान तो अपनी कोशिशें कर सकता है कि

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जो परिस्थितियां हैं और जो साधन उसके पास हैं उसके अंदर अच्छी से अच्छी क्या व्यवस्था हो जिससे लोगों को दिक्कतों से और तकलीफों से दूर निकालने का अवसर मिले। अकाल के कामों में जो कुछ अव्यवस्थायें हुई ठीक ढंग से उनको जमाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं।

अनाज का सवाल है, अभी माननीय विपक्ष के नेता ने कन्ट्रोल के बारे में कहा। उनकी पार्टी की नीति के दृष्टिकोण से भी स्वीकार नहीं है। जो उन्होंने आलोचना की, कन्ट्रोल के नाम को लेकर की; परमिट से भ्रष्टाचार होता है, लोगों की स्वाधीनता में फर्क पड़ता है और एक लेख भी उन्होंने पढ़ा। हम समझते हैं कि उनका अखबार हमारे पास आता है और हम उसको पढ़ते हैं और मुझको उसकी जानकारी पूरी रहती है लेकिन हमको यह सोचना है कि किस प्रकार लोगों को पहुँच सकती है। उन्होंने भी इसको स्वीकार किया और सदन में बैठने वाले माननीय सदस्य इसको स्वीकार करेंगे कि इस देश के अन्दर आज हर चीज की कमी है। खाने की चीजों की कमी है, सीमेंट की कमी है दूसरी सभी चीजों की कमी है सिवाय कुछ चीजों को छोड़कर। एक तरफ तो देश के अन्दर चीजों की कमी है दूसरी तरफ देश की जनता जिस स्तर पर और जिस जगह पर आज खड़ी है उसमें इतनी ही विभिन्नता है कि उसको यह मानकर चलें कि सब चीजें कुछ कुछ लोगों को मिलनी चाहिए यानी वे चीजें उनको मुहैय्या नहीं हो सकती हैं तो कमी की स्थिति को पूरा करने के लिए दो ही रास्ते हो सकते हैं। एक तो यह कि जो कमी की चीज है, "Lessee's fare lessee's free, जैसे डिमाण्ड एण्ड सप्लाई होता है उसके सिद्धांत पर चलने दें जिसमें लेने की शक्ति है वह ले लेगा और जिसमें लेने की शक्ति नहीं है वह नहीं ले सकेगा; वह राम राम करे, जो स्वतन्त्र पार्टी कहती है करो। हम कहते हैं कि हम उस रास्ते को अख्तियार नहीं कर सकते। हमारा दायित्व है कि समाज के तबके की आर्थिक स्थिति सुधरे और उसके साथ ही साथ जरूरत की चीजों का उत्पादन हो ताकि समाज के सब लोग उस माल को खरीद सकें और हमारा मानना है कि रीजनेबल प्राईस पर और रीजनेबल तरीके से डिस्ट्रिब्यूशन हो तो उसका दूसरा रास्ता कन्ट्रोल होता है। और कन्ट्रोल के रास्ते पर एक नियम का अंग बनाकर हमको हिन्दुस्तान के अन्दर हमें एक व्यवस्थित ढंग से आर्थिक ढांचे को ऊंचा करना है और समाज के सब तबकों के लोगों को और उन सारी चीजों के वितरण की ठीक ढंग से व्यवस्था करनी है तो बुनियादी तौर से कन्ट्रोल को मानकर चलना होगा, क्योंकि देश की आर्थिक व्यवस्था में····

श्री भैरोंसिंह : यह तो कांग्रेस ने भी नहीं माना है।

श्री नाथूराम मिर्धा : क्या कहा ?

श्री भैरोंसिंह : यह कण्ट्रोल का सिद्धांत तो कांग्रेस ने भी नहीं माना है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने कंट्रोल की जो बहुत बडी बातें की हैं मैं उनके बारे में कह रहा हूं, मेरा मतलब कन्ट्रोल से है, कमाडिटिज के कंट्रोल से नहीं है। कंट्रोल से मतलब है कि न तो कोई लाइसेंसिंग पद्धति होनी चाहिये न कोई लाईसेंस होना चाहिए, न कोई परमिट की व्यवस्था होनी चाहिए·······

श्री भैरोंसिंह : मैंने तो आपके कंट्रोल को समझ लिया।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं तो आप वाले (विरोधी पक्ष के नेता की ओर मुखापेक्ष) कंट्रोल की बात कर रहा हूं। धान और कंट्रोल की तो बहुत छोटी बातें है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा इस वक्त........

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपको जो कुछ कहना है कहने दिया जाय, मैं तो रोकना नहीं चाहता; लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मैंने यह कहा था कि लाइसेंस, परमिट, कंट्रोल जो भी आपको रखना आवश्यक हो तो रखें; लेकिन इसकी व्यवस्था किसी निष्पक्ष संस्था द्वारा होनी चाहिए।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं तो आपके दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स पर आता हूं।

श्री भैरोंसिंह : कंट्रोल हटाते ही बाजार में गेहूं कैसे आ गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपका एक आर्ग्यूमेंट है जिसके लिए आपने किसी इंग्लिशमैन का कोटेशन भी दिया था, जिसका सारांश यह था कि राज्य का कम से कम इन्टरफियरेंस होना चाहिए, व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर कम से कम नियन्त्रण होना चाहिए, यह बहुत बड़े सिद्धांत की बात कही थी, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आपकी छोटे वाले सिद्धांत की बात पर देर में आऊंगा। यहां के छोटे मोटे कंट्रोल की बातों पर तो मैं नेक्स्ट में आऊंगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा था माननीय अध्यक्ष महोदय, कि इस प्रकार की बातों में कि ट्रेड लाइसेंस फी होना चाहिए, कोई भी व्यापार करना चाहे तो व्यापार कर सके, इंडस्ट्री लगाना चाहे तो इंडस्ट्री लगा ले, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। इस नीति को इस देश के अन्दर जो आज की राज्य सरकार है वह स्वीकार नहीं करेगी और न ही करना चाहिए, मेरी राय में। यह इसलिए नहीं करना चाहिए कि आज इस देश के अन्दर हमें कई सेक्टर्स को डेवलप करना है। हम को कॉपरेटिव सेक्टर को डेवलप करना चाहते हैं, हम स्टेट सेक्टर को डेवलप करना चाहते है, हम इण्डीवीजुअल व्यक्तिशः सेक्टर को भी डेवलप करना चाहते हैं। इस देश में किन चीजों की कमी है और किनको प्रायोरिटि देना है, इन चीजों को अगर हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो सरकार के अलावा कौन ध्यान में रखेगा ? और इसके लिए लाइसेंसिग प्रणाली और कंट्रोल की जरूरत होगी। अगर आप देश में विधिवत् व्यवस्था कायम रखना चाहते हैं तो हमें इस बात को स्वीकार करके चलना पड़ेगा, हमको यह व्यवस्था माननी होगी अगर हम इन योजनाओं के तरीके से देश के अन्दर उत्पादन और डिस्ट्रिब्यूशन के अन्दर तालमेल रखना चाहते हैं, इनको व्यवस्थित ढंग से चलाना चाहते हैं तो थोड़े बहुत हद तक कंट्रोल की व्यवस्था को मान कर चलना होगा। इन सारी चीजों को जब आप मानते हैं और फिर आपका यह कहना कि सरकार ठीक एजेंसी नहीं है, तो फिर कौनसी एजेंसी होगी। क्या कोई पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह कोई तीसरी एजेंसी खड़ी की जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्रता से आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की इण्डिपेंडेंट बोडी, जिस देश में हम लोग रहते हैं और जिसमें इस प्रकार योजनाओं के द्वारा कार्य होता है, वह क्या हो सकती है........

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इसके लिए पाबन्दी नहीं है। आप बेकार परिश्रम

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
कर रहे हैं। अगर आप मेरी मांग को ही पूरा कर दें तो फिर आप में और मेरे में फर्क ही क्या रहे।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपकी बात सिद्धान्त रूप से सही है। सरकार को ही इन बातों पर ध्यान देना होगा, जो जनता की चुनी हुई सरकार है उसको ही ध्यान देना पड़ेगा और उसको ही फैसला करना पड़ेगा कि किस प्रकार की व्यवस्था देश में हो। देश में जो वितरण की कमी है या उत्पादन की कमी है, तो किस चीज को प्रायोरिटि देकर कमी को पूरा किया जाय इसकी व्यवस्था जनता की चुनी हुई सरकार को ही करना होगा। आज के कंट्रोल के बारे में जो आपके सुझाव हैं उसको राज्य सरकार न तो नीति के तौर पर मान सकती है और न ही उसको मानना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने एक छोटी सी पुस्तक इस सदन के माननीय सदस्यों को भेजी है। राज्य सरकार के तमाम विभागों की तरफ से ही इस प्रकार की पुस्तकें माननीय सदस्यों को भेजी जाती हैं जिसमें उस सत्र से लगाकर इस सत्र तक क्या क्या प्रगति की गई है, उसका विवरण उन पुस्तकों में होता है। कोई महकमा उसको छपवाता है, कोई साइक्लोस्टाइल करवा कर बंटवाता है। उनको अगर आप माननीय सदस्य अच्छी तरह से पढ़ कर, उनमें जो कमियां रहती हैं उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करें तो इस सदन का बहुत कुछ समय का अच्छा सदुपयोग होगा और हम को भी गाइडेंस मिलेगी कि आगे हमको क्या करना चाहिए और इसके साथ साथ आप भी उसको पढ़ने से रीयलिटि के ज्यादा नजदीक पहुंचेंगे। मैंने आपके सामने एक छोटी सी मिसाल रखी। एनीमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से एक छोटी सी पुस्तक निकाली गई है, उसमें ग्राफ्स देकर और आंकड़े देकर बताया गया है कि पंचायत समितियों में हमने केस्ट्रेशन के प्रोग्राम में कितनी प्रगति की है। जो अच्छी नस्ल के सांड हैं उनके वितरण से गांव के आर्थिक-जीवन में कितना फर्क आया है, कहीं सेंट परसेंट, कहीं सेवन्टी फाइव परसेंट, कहीं ट्वन्टी, कहीं ट्वन्टीफाइव परसेंट तक काम हुआ है और उसकी वजह से हमारे देहातों के आर्थिक जीवन में कितना फर्क आया है, इसकी एक छोटी सी तस्वीर मैंने आपके सामने रखी है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय कि आज हम यह नहीं मान कर चल रहे हैं कि हमने सारे काम पूरे कर लिये हैं और आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बल्कि काम की एक दिशा है, उस दिशा की ओर हम बढ़ रहे हैं और उस दिशा पर पहुंचने के लिए हम काम कर रहे हैं। इस पर अगर सदन के माननीय सदस्य गम्भीरता से विचार करेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि योजनाओं का आकार बड़ा होना चाहिए।

राजस्थान की आज जो स्थिति है, जहां पर हमारा पर-कैपिटा खर्चा आज भी कम है, जहां पर हम उद्योगों का विकास करना चाहते हैं, जहां पर हम विद्युत की गति को तेज करना चाहते हैं, जहां पर सिंचाई के साधनों को बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर योजनाओं का आकार बड़ा करना ही होगा और योजनाओं को पूरा करने के लिए

(श्री नाथूराम मिर्धा)

साधन जुटाने होंगे। जो कर्जा हमको मिलता है, भारत सरकार से मिलता है तो वह हमको लेना होगा, दूसरी एजेन्सियों से हमको मदद मिल सकती है तो वह भी लेनी होगी, कर्जा लेने की आवश्यकता होगी तो वह भी लेना पड़ेगा और लेंगे। जो कुछ तस्वीर आपके सामने रखी गई है तो उसमें आपने देखा होगा कि आखिर जो कर्जा लिया है वह फालतू जगह तो खर्च नहीं किया है। जिस प्रकार खर्चा किया गया हो उसके बारे में अभी दूसरे दूसरे व्यक्तियों ने आपको बताया है, कल स्टेट एन्टरप्राइज और इण्डस्ट्रीज विभाग के बारे में जवाब दिए गए हैं और दूसरे लोग भी जवाब देंगे। इसलिए यह कहना कि शासनतंत्र में कमियां है, जैसा बढिया शासन आप चाहते है और हम भी चाहते हैं कि शासनतंत्र बहुत बढ़िया हो, सब लोग ईमानदारी से काम करें, सब लोग तेजी से काम करें, पर सब आपके और हमारे चाहने से ही पूरा नहीं हो जाता। आप सब जानते हैं कि किसी भी प्रजातांत्रिक देश की जड़ इन्सान हैं, इन्सान का चरित्र है, इन्सान का काम करने का तरीका है, उसका आचरण होता है, कितना उसका आदर्श है, वह क्या करता है, यह मेटीरियल है। जिस देश का आचरण और जिस देश का चरित्र ऊंचा होता है उस देश की तरक्की की गति भी तेज होती है। जहां इसमें कमियां रहती हैं उनकी गति भी उतनी ही मंद बनी रहती है। इस बात को हम भी मानते हैं कि इस ओर आपको और हमको सब को मिल कर पूरा प्रयत्न करना चाहिए।

जिस प्रकार की भावना आपने शासनतंत्र के बारे में व्यक्त की है वह वाजिब हो सकती है और हमको भी उसको शिरोधार्य करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें करों की वजह से न तो कोई जनता को बहुत ज्यादा भड़काने की आवश्यकता है और न इसका ज्यादा राजनैतिक उपयोग करने की आवश्यकता है। उनको हमको और आपको सिखाना पड़ेगा, आपको और हमको उनको बताना होगा कांकरीट रूप में कि करों की वजह से आखिर देश की व्यवस्था में फर्क आयेगा। करों का विरोध तो सभी कर सकते हैं; हो सकता है कि राजनैतिक दृष्टि से सभी लोग करों के विरुद्ध कहने की कोशिश करते हों, पर आप यह मानकर चलें कि किसानों को भी अगर इस देश में चल रही योजनाओं का फायदा उठाना है तो उसके लिए उन्हें भी कुर्बानी और त्याग करना पड़ेगा, उनको भी कर देने होंगे, चाहे वे घी के टैक्स के रूप में हों, चाहे जानवरों के लगान के रूप में हों। फिर भी अगर इस सदन की मंशा हो और हमारे वित्त मंत्री जी और मुख्य मन्त्रीजी सब लोग बैठकर स्वीकार करें कि किस वक्त में क्या कदम उठाया जाय और जो बीस तीस लाख का घाटा रहता है उसको दूसरे तरीके से किस प्रकार पूरा किया जाय तो इसके लिए आप भी कोई आॅल्टर्नेटिव उनके सामने रख सकते हैं सुझाव के रूप में।

एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि यह भी अच्छा नहीं है वह भी अच्छा नहीं है तो मैंने कहा कि क्या अच्छा है, तो कहने लगे कि वह हमारा काम नहीं है, यह तो आप सोचो, आपका काम है।

श्री भैरोंसिंह : आपकी क्या राय है मवेशियों पर टैक्स लगान चाहिए या नहीं ?

(२. म. प.)

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपसे कहूं कि मेरी राय तो यह है कि मैं हमेशा इस पक्ष में हूं कि हमसे जितना बोझ उठाया जा सकता है उतना उठाया जाना चाहिए। वह बोझ किसान को भी अपने हिस्से का उठाना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : कृषि मंत्रीजी, आखिर राजस्थान का जितना पशु धन है उसकी निगरानी और बहबूदी के लिए आप जिम्मेदार हैं, और उनके जरिये से जो किसानों को राहत मिले, इसके भी आप जिम्मेदार हैं। इन पर जो अभी कोल साहब ने टैक्स लगाया है उस टैक्स के कारण यदि किसानों का नुकसान होगा. ....

श्री नाथूराम मिर्धा : वह गवर्नमेंट ने लगाया है और उसमें मेरी भी सहमति है।

श्री भैरोंसिंह : उसमें आपकी राय बतायें कि लगना चाहिए कि नहीं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : कह दें कि किसानों का फायदा किया।

श्री भैरोंसिंह : ताकि हम कन्विंस हो जायें।

श्री नाथूराम मिर्धा: उसके बारे में फैसला मैं करने वाला नहीं हूं। मैं अपनी राय कह रहा हूं कि किसी भी एक्शन के जरिये या योजना के जरिये चाहे वह जानवरों की हों उस जानवरों की योजना के जरिये ऐसी स्थिति पैदा होती हैं कि उसमे किसान को लाभ मिलता है तो a farmer should be prepared to share a part of the burden.

श्री अध्यक्ष : आज तो बात सिद्धान्त के ऊपर हो रही है। आप छोटी छोटी बातों पर क्या कर रहे है।

श्री नाथूराम मिर्धा : ये छोटी छोटी बातों पर अड़ जाते है।

माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन कर था....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अभी दो मिनट में ही खत्म कर देता हूं।

श्री भैरोंसिंह : इनकी बात पर घंटी बजा कर तो आपने सारा ही मामला खत्म कर दिया।

श्री नाथूराम मिर्धा : राजस्थान की जनता में सही प्रकार का वातावरण हो उसका उत्तरदायित्व इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले दोनों ही पक्षों के ऊपर है। इसलिए सही मनोबल पैदा करने के लिए और साहस के साथ योजनाओं को बढ़ा कर चलने की आवश्यकता पैदा हो, ऐसा वातावरण हमारे इस सदन में बनना चाहिए। और इसी दृष्टिकोण से, केवल राजनैतिक ही नहीं, राजनैतिक तौर पर तो आप और हम सब काम करते रहेंगे तो और ज्यादा तरक्की करेंगे, लेकिन रचनात्मक दृष्टिकोण को सदन के सामने रख कर योजनाओं को मजबूती से चलाने की आवश्यकता इसी सदन मे पैदा करें। मैं यह बात कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, जो सन् १९६६-६७ का बजट सदन में पेश हुआ है, इस बजट को मैंने देखा है। मैंने देखा कि इसमें आमदनी और खर्च दोनों

(श्री मानसिंह महार)

साथ-साथ बढ़ते जाते हैं। तो बजट तो एक पैटर्न होता है जो कि देश भर में उसी प्रकार से चलता है। सेन्टर में अगर बैलेन्स्ड बजट है तो प्रान्तों में भी उसी प्रकार का बजट होगा। बजट के आंकड़ों मे जाना तो मैं समझता हूं कि इसी प्रकार की मूर्खता होती है, जैसी कि प्लानिंग मिनिस्टर कर रहे थे। दो आंकड़े इधर के डाले और दो उधर के डाले और वह एक दूसरे के कन्ट्राडिक्ट्री थे, और लोगों ने टोका तो बिल्कुल खिन्न भिन्न हो गये। तो मैं आंकड़ों की बातों में ज्यादा न जाकर मैं कुछ तथ्यों की ओर जाऊंगा और वित्त मंत्रीजी से कुछ बातें करूंगा।

मैंने जब बजट देखा और इसके आंकड़ों के जंजाल में गया तो मैंने सोचा कि हमारे कृषि मंत्रीजी के कुछ सिद्धान्तों की बातें भी इस बजट में है कि नहीं। तो मैं बजट में सिद्धान्तों को ढूंढने लगा, अध्यक्ष महोदय, तो सिद्धान्त ढूंढते-ढूंढते मैंने देखा कि राजस्थान की जनता को डेवलपमेंट के जरिये बहुत चीजें मिली है, लेकिन न्याय बड़ा मंहगा होता जा रहा है। दिन प्रति दिन न्याय मंहगा हो रहा है तो मैंने कहा कि इस सरकार ने न्याय के लिए क्या क्या बातें की तो पहली चीज जो मैंने सोची वह यह थी कि अब तो आन्ध्र प्रान्त जो बनने वाला था वह भी बन गया एक आदमी के जल के मरने से। महाराष्ट्र और गुजरात भी दो अलग अलग प्रान्त बन गये, और अध्यक्ष महोदय, आखिर में जाकर पंजाबी सूबा भी इस सरकार ने कन्सीड कर दिया। तो मैंने सोचा कि इस बजट में हमारे वित्त मंत्रीजी ने हाई कोर्ट की बेन्च जयपुर में कन्सीड करी कि नहीं। यह दुर्भाग्य का विषय है कि उस ओर सरकार का ध्यान नही गया। लेकिन मैं सरकार को और हमारे लॉ मिनिस्टर को चेतावनी देना चाहता हूं कि आप लोगों की इस भावना को कि यह सरकार को जहां दबाया जाता है वही दबती है, बढ़ावा मत दो। शरीफ आदमी की तरह प्रार्थना की जाये तो नहीं मानती है। हम तोड़-फोड़ में विश्वास नही करते है कि पंजाब में पंजाबी सूबा की बात करते हैं तो दिल्ली के चांदनी चौक में लड़ाई झगड़े होते हैं। हम इस चीज को नहीं मानते हैं, लेकिन हम कहते आ रहे हैं मतवात्तिर कि हाई-कोर्ट की बैन्च जयपुर में होना चाहिए, राजस्थान का तीन-चौथाई हिस्सा यह मांग करता आ रहा है, हमारे शिक्षा मंत्रीजी तो बड़े पुजारी हैं इसके, लेकिन उन बैन्चों पर बैठकर शायद उनकी जबान बन्द हो, लेकिन मैं उनसे आशा करूंगा कि सरकार पर दबाव डालें, और मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी बैंच की मांग को अब जब से पंजाबी सूबे की मांग को कमजोर सरकार सेन्टर की ने मन्जूर किया है उसके बाद पुरजोर रूप से इस सरकार के सामने रखेंगे। मैं इस सरकार को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हमारा जो आन्दोलन है वह किसी प्रकार की तोड़-फोड़ में तो जायेगा नहीं, लेकिन हम इस आन्दोलन का श्री गणेश इस तरह से करेंगे कि लॉ मिनिस्टर, या धौलपुर-राजगढ़ से आये हुए मंत्री, कोटा, बूंदी, या अजमेर के मंत्री वहां आया करेंगे तो उनके लिए गधों की व्यवस्था करेंगे और उनको उन पर बैठाकर यहां लायेंगे, अगर उन्होंने इस छोटी सी वाजिब मांग को नही माना तो। तो मैं आप से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी पहली मांग यह है कि इस बजट को पारित करने से पहले, पहले हाई कोर्ट की बेन्च को जयपुर में लाने की बात को मन्जूर करके इसका एलान करें।

(श्री मानसिंह महार)

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद दूसरा विषय जिसके बारे में मुझे दुःख हुआ वह है यह कि सरकार ने इस मंहगाई के जमाने में अपने कर्मचारियों की अवहेलना की है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप और सब को छोड़ दीजिये, लेकिन एक गरीब चपरासी या एक गरीब पुलिस का सिपाही या क्लर्क्स वगैरह ले लें, आज उनकी क्या हालत है ? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उनकी हालत की ओर देखें और फिर हमारे वित्त मंत्रीजी के बजट जिसमें हर मद में खर्चा बढ़ता जा रहा है, हर मद में बढ़ता चला जा रहा है उस बजट को अगर हम देखते हैं तो उन कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं है। बस यह कह कर कि हम कुछ भंडार खोलेंगे चुप रह गये। वह भण्डार किस के होंगे, उनका क्या मतलब है ? उन भण्डारों से तो आपके भरे हुए भण्डार और भरेंगे। वित्त मंत्रीजी यह मैं और आपको बतादूं कि उन गरीब कर्मचारियों को कोई रिलीफ आपके भण्डार देने वाले नहीं हैं। मैं सही कहता हूं कि अगर आप सरकारी कर्मचारियों को संतुष्ट नहीं रख सकते हैं, तो देश को एक ऐसी तरफ ले जा रहे हैं कि जो आपके लिए घातक है। आपके लिए तो है ही लेकिन देश के लिए भी बहुत घातक है। जो सरकार अपने कर्मचारियों को सन्तुष्ट नहीं करेगी वह उस देश को कम्युनिज्म की तरफ ले जायगी। मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं कि आप राजस्थान को छोड़ कर और प्रान्तों की हालत देखिए कि वहां पर आज कम्युनिज्म क्या बखेड़े करा रहा है। जितने भी दंगे वगैरह हुए हैं वे कम्युनिस्टों के कारण हुए हैं। तो आप खुद ही सोचिये। पहले से ही लोग मजबूर करें, उससे ये सरकारी कर्मचारी उन कम्युनिस्टों के चंगुल में जायें और आपको मजबूर करें। नल और बिजली कर्मचारियों ने भूख हड़ताल की और उसके बाद आप जैसी कि आपको आदत है आप उनके सामने सरेन्डर करें, यह आपके लिए बहुत घातक है। आपके लिए ही नहीं, इस देश के लिए भी। तो मैं यह आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप इस देश के अन्दर सच्ची डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, तो आप उन कर्मचारियों को आपके विरुद्ध आन्दोलन करने के लिए बाध्य न करें। आप उनको अपनी तरफ से सहूलियत दीजिए, जिससे कि वह कोई ऐसी बात न करें।

मैं आपसे, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो यह देश में अनरेस्ट की भावना फैली हुई है उसका मुख्य कारण यह है कि हमारी सरकार में, यह मैं डाइरेक्ट हिट कर रहा हूं, कुछ ऐसे तबके बैठे हुए हैं कि जो अन्दरूनी तौर से कम्युनिज्म के समर्थक हैं। आपके मंत्रीमंडल में भी श्री एच० के० व्यास के मित्र बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से एच० के० व्यास ही नहीं उनके राइटिस्ट कम्युनिस्टों को जैल में नहीं बन्द करके बाहर आज आपके खिलाफ घृणित से घृणित प्रचार करने के लिए कई एच० के० व्यास खुले फिर रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं कि इनमें कोई राइट, लेफ्ट नहीं है, ये सब एक हैं। इन लोगों के लिए कहा जाता है यह राइट कम्युनिस्ट हैं, वह लेफ्ट कम्युनिस्ट है यह कुछ नहीं है सिर्फ फरेब बाजी है, बेवकूफ बनाने का बहाना है। सदन में जब बात आती है तो कहते हैं, मोहन पूनमियां की जान खतरे में है, ये राइट कम्युनिस्ट कहते हैं लेफ्ट कम्युनिस्ट के लिए जब इनके स्वयं के गिरफ्तारी की बात आती है तो कहते हैं, हम तो राइट कम्युनिस्ट हैं लेफ्ट से दूर हैं, हम चीन के समर्थक नहीं हैं हम तो रूस समर्थक हैं। यह तो आपकी आंखों में धूल झोंकने लायक बात है। अनेक

(श्री मानसिंह महार)

प्रकार के खर्चों को बढ़ावा नहीं देकर यदि देश को कम्युनिस्टों से बचाना है तो राइट और लेफ्ट की बात को छोड़िए और फौरन इन सब को घाटगेट पहुँचाइये, उस पेलेस में इनके लिए समुचित व्यवस्था कीजिए। मुझे दुःख होता है जब आप इनको पोलिटिकल प्रिजनर्स की संज्ञा देते हैं और वे कहते हैं कि उनकी फेमिलीज को अलॉउन्स नहीं देते। देश द्रोहियों की फेमिलीज को काहेका अलॉउन्स उनकी फेमिलीज को कोई अलॉउन्स नहीं मिलना चाहिए। लेकिन दुःख का विषय है कि जब वे अलाउन्स की बात करते हैं तो मुख्य मंत्रीजी उठकर लिस्ट पढ़ते हैं कि फलां को इतना अलॉउन्स दिया जाता है और फलां को इतना दिया जाता है। यह सरकार की कमजोरी है। आपकी कमजोरी से हमको लाभ उठाना चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं कि आप देश को रसातल में पहुँचा रहे हैं, तो हमको विरोध करना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस बजट में लेफ्ट और राइट कम्युनिस्टों की फेमिलीज के लिए अलॉउन्स की व्यवस्था की गई है, तो उसको रोकिये और मैं सरकार से कहता हूं कि ऐसे देश द्रोहियों की फेमिलीज को कोई अलॉउन्स या सहायता नहीं देनी चाहिए। मैंने यह बात कही, कम्युनिस्टों के बारे में।

जब मैं गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स की फेमिलीज के बारे में यह बताना चाहता हूं कि उनकी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मेरे उधर बैठने वाले मित्र सरकारी नौकरों को अधिक तनख्वाह देने के विरुद्ध हैं और सरकार की यह नीति है कि बड़े अफसरों को दो ढाई हजार रुपया देकर वह समझती है कि हम सरकारी कर्मचारियों को बहुत देते हैं। आपकी यह नीति अच्छी नहीं है। क्योंकि जो वाकई योग्य आदमी हैं वे सरकारी नौकरी में नहीं आते हैं और जितने भी योग्य आदमी हैं वे बड़ी बड़ी फर्म में नौकरी करते हैं जहां उनको पांच पांच हजार, दस दस हजार रुपया तनख्वाह मिलती है। सरकारी नौकरी में वे आना पसन्द नहीं करते, क्योंकि आप २ हजार रुपये उनकी तनख्वाह कर देंगे तो बहुत हद होगी। मैं कहता हूं तनख्वाह योग्यता के आधार पर होनी चाहिए।

आपको एडमिनिस्ट्रेशन सही ढंग से चलाना है, तो जितने सरकारी कर्मचारी हैं, जितनी तनख्वाह पाते हैं, उनको मंहगाई के हिसाब से जरूर अलॉउन्स देना चाहिए, चाहे वे न्यून तनख्वाह पाने वाले हों, चाहे बड़ी तनख्वाह पाने वाले हों।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : बड़ी तनख्वाह वालों की तो बढ़ी है, लेकिन छोटे वालों की नहीं बढ़ी।

श्री मानसिंह महार : आप सब की बढ़ाइये। मैं अब बहुत बड़े अहम मसले पर आता हूं वह है फेमिली प्लानिंग। इसके बारे में, मैं निवेदन करूंगा कि इनके जितने प्लान हैं, मैं समझता हूं आपने ३ प्लान हमको दे दिए। आपके प्लान जब शुरू होते हैं, तब बड़ा सब्ज बाग दिखाते हैं। आपका प्रथम प्लान सन् ५२ में चालू हुआ। अध्यक्ष महोदय, उस समय हमको वह सब्ज बाग दिखाया कि हमने इनके टैक्सेज को स्वीकार किया। दूसरी बार भी वही नक्शा दिखा दिया। तीसरी बार भी जनता को गारत कर दिया, लेकिन अब चतुर्थ प्लान आया है। एक बार कोई बात कहते हैं तो मान लेते हैं, दूसरी बार भी मान लेते हैं, लेकिन तीसरी

(श्री मानसिंह महार)
बार कोई कोई मूर्ख मान लेते हैं, लेकिन चौथी बार कोई नही मानता। यदि आप जनता को कोन्फीडेन्स में लेना चाहते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि चतुर्थ प्लान को स्क्रेप कर दीजिये, पांच वर्षो के लिए छुट्टी कर दीजिए..

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप भी छुट्टी ले लेंगे क्या ?

श्री मानसिंह महार : हां मैं भी छुट्टी ले लूंगा यदि कांग्रेस सरकार यह कह दे कि प्लानिंग पर जितना फालतू खर्चा होता है वह नहीं होगा, तो मैं चुनाव नहीं लडूंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अब फेमिली प्लानिंग पर आजाइये।

श्री मानसिंह महार : अभी तो मैं चतुर्थ प्लान के बारे में कहता हूं। फेमिली प्लानिंग पर आऊंगा तब मालूम होगा कि यह क्या है ? कुछ उधर बैठने वालो को प्लानिंग फोबिया हो गया है, प्लानिंग के बिना वे जी नही सकते। यह ठीक बात है क्योंकि उनकी पोलिटिकल लाइफ सन् ५२ के बाद शुरू हुई है, वे क्या समझें कि जनता की उन्नति बिना प्लानिंग के कैसे हो सकती है। उधर देखते हैं तो कहा जाता है रूस में प्लानिंग होती है, चीन में प्लानिंग होती है, इसलिए वे क्या समझें कि प्लान से छुट्टी देने का क्या अर्थ है। इसलिए मैं पहले उनको प्लान से छुट्टी देने की बात समझा दूं।

मैं निवेदन करता हूं कि मेरे नेता महोदय ने कहा कि विकास अधिकारी को हटा दीजिए। विकास अधिकारी को हटाने का मतलब केओस करने से नही है। हमारे मुख्य मंत्री के परम मित्र मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने दिल्ली में बहुत सहयोग दिया था, उन्होंने अपने यहां विकास अधिकारियों और विकास जीपों को हटा दिया। यही नहीं स्वर्गीय प्रधान मंत्री लालबहादुरजी ने भी यह कहा था कि सही माने में विकास करना है तो विकास अधिकारियों के पास जो जीप्स हैं उन्हें सरकार को वापिस लेना चाहिये लेकिन अभी जब एमरजेन्सी आई, हिन्दुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई के समय उनकी जीप्स बॉर्डर पर चली गई थीं मुझे इससे बड़ी खुशी हुई क्योंकि विकास अधिकारी बिना जीप के पंचायत समितियों में ठहरने लगे और काम करने लगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि लड़ाई खत्म होते ही उनके पास जीप्स वापिस आ गई। इनको जीप्स देने से नुकसान क्या होता है, यह मैं बताता हूं आप जयपुर में ही देख लीजिये, जगह-जगह जीप्स खड़ी हुई मिलेंगी। जिन पर विकास खण्ड का नाम लिखा हुआ होगा। जब भी मामूली सी भी जरूरत हुई विकास की जीप लेकर चले गये। जितने डिस्ट्रिक्ट हैड क्वाटर्स हैं, वहां पर विकास अधिकारी मामूली से मामूली काम लेकर पहुँच जाते हैं।

मैं कृषि मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि गांव वालों की बहबूदी के लिए काम नहीं करके, इधर-उधर घूमने का काम करते हैं। यदि यह बिमारी विकास अधिकारियों में ही होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उनकी देखा देख प्रधान भी बहती गंगा में डुबकी लगा लेते है। वे भी बी० डी० ओ० के साथ साथ घूमते है। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विकास अधिकारी और उनको जीप को अलग करके बी० डी० ओ० कम एस० डी० ओ० या छोटी विकास समिति हो, तो तहसीलदार कम बी० डी० ओ० रख

(श्री मानसिंह महार)

दीजिये। आप जितना प्लानिंग करते हैं; मैं निवेदन करता हूं, खास कर पंचायत मंत्रीजी से कि विकास की जड़ ग्राम पंचायत है। तीन योजनाएं खत्म हो गईं, लेकिन दुःख का विषय है कि पंचायतों के साधन किस प्रकार बढ़ाये जायें इसके बारे में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। मैं फैक्ट्स के आधार पर कहता हूं और एक सरपंच की हैसियत से कहता हूं कि ९० परसेन्ट पंचायतें दिवालिया हैं। उनके पास क्लर्क और चपरासी के लिए पैसा नहीं है क्योंकि इस मंहगाई के समय भी एक-एक पंचायत को चार-चार सौ रुपये की सहायता सरकार उनको देती है। आप प्लानिंग करना चाहते हैं, योजना को सफल बनाना चाहते हैं, क्लर्क और चपरासी रखने के लिए पंचायतों के पास पैसा नहीं है, तो कैसे आप योजना को सफल करेंगे। आपकी तीन योजनाएं खत्म हो गईं, चौथी योजना में प्रवेश करना चाहते हैं, आप के पास कुछ नहीं, आप इस प्रकार की पंचायतों को फापर बनाकर चलते हैं, इससे बढ़कर दुर्भाग्य की बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। इसलिए मैं कहता हूं कि इस प्लानिंग को पांच वर्ष के लिए छुट्टी दीजिये। अगर आप पांच वर्ष बहुत अधिक समझते हैं, तो चौथी योजना को चार वर्ष की बना दीजिये और एक वर्ष की छुट्टी लेकर देखिये। और वाकई में अगर आपको फायदा हो तो बाद में भी छुट्टी कीजियेगा वरना मत कीजियेगा। प्लान के बारे में मैं कहूं आप प्लॉनिंग कितना ही कीजिये मगर जब तक पंचायतों को मजबूत नहीं बनाते हैं, तब तक आपका प्लॉनिंग कभी कामयाब नहीं होगा। आपने आज जिला परिषद् को तो कम पावर दी है, लेकिन पंचायत समितियों को आज पावरफुल बना रखा है। आज जितने गांव वाले हैं उनकी निगाह पंचायतों की तरफ नहीं होती कि पंचायत क्या करती है। उनकी निगाह तो पंचायत समिति की तरफ होती है। मैं कहता हूं, जितने भी आपके लोन्स वगैरह आते हैं, उनका बटवारा आप समान तरीके से कर दीजियेगा। आप पहले से सूचना दे दीजियेगा उनको, जो जो अगले वर्ष के अन्दर आप काम पंचायत समिति में कराना चाहते हैं–उसकी एक लिस्ट समिति में भेज दीजियेगा कि हम समिति को इतना रुपया इस चीज के लिए देंगे, इतना रुपया इस चीज के लिए देंगे और फिर उनका बटवारा समान रूप से सब पंचायत समितियों में कर दीजियेगा, तो काम हो सकता है।

आज ऐसी-ऐसी पंचायत समितियां मौजूद हैं; जहां पर दो सौ, चार सौ रुपया भी खर्च नहीं होता। आप कहेंगे कि इतनी बड़ी विचित्र बात कहते हो। इस तरह कैसे हो सकता है। इसका नमूना आपको देता हूं कि सन् १९६०-६१ के अन्दर ए०पी० दीवान कलेक्टर जयपुर थे वह हमारी पंचायत समिति गोबिन्दगढ़ में पंच और सरपंचों के सम्मेलन में गये। कुछ पंचायतों ने उनसे शिकायत की कि, अध्यक्ष महोदय, हमारी पंचायत में पैसा बिल्कुल नहीं आता है। कुछ इम्पॉटेन्ट सरपंच या इम्पॉटेन्ट पंचायतें हैं या जो प्रधान के ज्यादा नजदीक हैं वह सारा पैसा ले जाते हैं। मिस्टर दीवान ने दो हजार रुपया प्रत्येक पंचायत के हिसाब से इमिजियेटली एक एडहोक ग्रान्ट दिला दी ६८ हजार रुपया की और उन्होंने कहा–यह आपकी ३४ पंचायतों में समान रूप से बांट दीजियेगा। मैं देखूंगा कि इसका

(श्री मानसिंह महार)

पंचायतों में दो हजार रुपये का किस प्रकार से सदुपयोग करते हैं। पंचायत समिति की कोई राय नहीं, कुछ नहीं उन्होंने यह काम प्रधान वगैरह की राय से किया लेकिन प्रत्येक पंचायत को एक इक्विल ग्रान्ट दे दी– वह एक न्यायोचित चीज थी और जितने हमारी पंचायत समिति के सरपंच थे, उनकी जुबान बन्द हो गई। वे यह नहीं कह सकते थे कि मेरे पास पैसा नहीं आया, इसलिए डवलपमेंट नहीं हो सका। जो चतुर सरपंच थे उनके यहां तो दो हजार की बजाय दस पन्द्रह हजार रुपये का काम हुआ और जो ऐसे थे कि हमेशा पंचायत समिति से पैसा ले जाते थे वहां दो हजार रुपये में से एक हजार रुपये का काम भी नहीं हुआ। मैं कहता हूं, इस प्रकार का तरीका अपनाइये जिससे पार्टीबाजी को प्रोत्साहन न मिले और जिससे समानता आये।

तकावी लोन्स के लिए मैं कृषि मंत्रीजी को निवेदन करूंगा कि आप तकावी लोन्स बहुत दे रहे हैं। मैं नहीं कहता कि नहीं दे रहे हैं। आप कुए गहरा करने के लिए और कुए नये बनाने के लिए लोन्स भेज रहे हैं। लेकिन आप वहां यह कम से कम डाइरेक्टिव दे दीजिये कि पंचायात समिति अपने लोन्स को समान तरीके से बांटे। यह नहीं कि सरपंच साहब ने, जो किसी समिति का अध्यक्ष है, अपने बाप के नाम से पांच हजार रुपये ले लिए भतीजे के नाम से पांच हजार रुपये ले लिए और अपने रिश्तेदारों को दिला दिया और जो लाखों का लोन गया वह दो तीन पंचायतों मे बांट कर खत्म कर दिया। यह तरीका नहीं होना चाहिए। मैं फेक्ट अर्ज कर रहा हूं। अगर पंचायत मंत्री चाहेंगे, तो उसके आंकड़े भी दे दिए जायेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं कृषि मंत्री से कहता हूं, क्योंकि उन्होंने अभी लम्बी चौड़ी सिद्धान्तों की बात कही, उनकी सिद्धान्त की बात सुन कर मैंने भी सोचा कि एक आध सिद्धान्त की बात समझाऊं, ताकि उन्होंने जो मोटी-मोटी बातें हमको कही हैं, उनकी मोटी बातो के आधार पर एक मोटी बात मैं भी कह दूं, जो उनकी मोटी बुद्धि में आ जाये और प्रान्त का उत्थान हो जाये। इसलिए कृषि मंत्री को खास तौर से सम्बोधित करके प्रार्थना करता हूं कि इस चीज के बारे में भी सोचें वह।

इसके बाद डेवलपमेंट के अन्दर आप जो धनराशि फेमिली प्लानिंग के लिए रखते है, वह वास्तविक रूप में कम है। आज उत्पादन बढाने की बात करते हैं, आज और बातें कहते हैं, लेकिन कितना ही उत्पादन बढाइये, आप कुछ भी करिए, लेकिन जब तक आप फेमिली प्लानिंग नहीं कर सकते, देश में तब तक आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते यह आप निश्चित रूप से मान लीजिए, क्योंकि अगर आप पचास हजार आदमियों के खाने के लिए अधिक पैदा करते है वहां लाखों पैदा हो जाते हैं तो बताइये आप कैसे कामयाब होंगे। इसलिए इस फेमिली प्लानिंग को आप एक बार फुटिंग पर ले आइये। आप गांव–गांव में जाइये, फेमिली प्लानिंग के लिए। लेकिन गांव–गांव में जाने का, अध्यक्ष महोदय, यह मतलब नहीं होता है कि राजस्थान के पंचायत मंत्री एक बहुत बड़ी मोटर लेकर जायें, सो–दोसो रुपये उनके टी. ए., डी. ए. में खर्च हों, बड़े-बड़े डाक्टर लोग जायें, केम्प लगें, बहुत बड़ी-बड़ी

(श्री मानसिंह महार)

बातें हों और अन्त में जाकर अगर देखें तो या तो दो तीन आपरेशन हुए या आठ-दस लूप लगे हुए मिलें। इस प्रकार काम नहीं चलेगा। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आप जब इस प्रकार की बात करें तो आप देखिये कि आप अगर हजार रुपये खर्च करते है, किसी केम्प पर या पन्द्रह सौ रुपये खर्च करते है तो आप पांच सौ ऑपरेशन कराने की बात सोचा करिये, आप पांच सौ लूप लगाने की बात करिये। आपके यहां अभी अजमेर के अन्दर एक लूप लगाने का अभियान चला था, वह काफी कामयाब हुआ, क्योंकि उसको पब्लिसिटी मिली थी। लेकिन हेप-हैजर्ड तरीके से कोई बात होती है तो वह नहीं होती है। मंत्री जब दौरे पर जायें, या लोग उनको उद्घाटन-चाटन के लिए इन्वाइट करें, तो उनको चाहिए कि पहले पूछें–मैं तब आऊंगा जब आप सौ आदमियों का वेस्टकाटोमा का ऑपरेशन करायें या दो सौ के लूप लगाने की योजना करें तो मैं आपकी समिति में जाऊंगा और यदि दो-तीन लूप लगाने की बात है तो मैं इतनी छोटी सी बात के लिए नहीं जाऊंगा। मंत्रीलोग इस प्रकार का कॉम्पीटिशन करें तो बात चल सकती है लेकिन आपके लिए तो सब चीजें एक भाव है। आपको तो बुलाने वाला चाहिए––हुजूर पधारिये। आपके बिना तो हमारा काम नहीं चलेगा और हुजूर छतरी हो जाते हैं। तो यह तो पुरानी बात है। आप तो जनतंत्र के आदमी है। आपको तो इस जनतन्त्र के युग में इस 'हुजूरबाजी' को छोड़ना चाहिए। आपने 'हुजूरबाजी' का कड़ा विरोध करके इस चीज का विरोध किया। आप भी 'हुजूरबाजी' का शिकार बनते हैं तो मैं समझता हूं कि यह दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, अध्यक्ष महोदय, हमारे लिए तो यह हुजूरबाजी भी दुःखदायक है। मैं आपसे यह निवेदन कर दूं, मंत्री लोग जहां भी जाते हैं, उस इलाके के जो कांग्रेसी पिट्ठू होते हैं, उनको साथ ले जाते हैं। यह देखिए कि मंत्री महोदय जिस जिस एम. एल. ए. के इलाके का दौरा करते हैं उसको सूचना करते हैं ?

श्री हरीप्रसाद शर्मा (पाटन) : करते नहीं है।

श्री मानसिंह महार : इन चार वर्ष के कार्यकाल में मुझे दुःख है मुख्य मंत्रीजी दर्शन देकर पधार गए, मैं उनको कहता हूं, आप लम्बी चौड़ी बात कहते हैं–मैं जिस एम. एल. ए. के क्षेत्र में दौरा करता हूं उसको सूचना दी जाती है। यह सूचना दी जाती है कि फलां मन्त्री फलां दिन दौरे पर आयेगा। हम विरोधी पक्ष के····

श्री गिरधारीलाल व्यास : मतलब की बात पर आ गये।

श्री मानसिंह महार : बिलकुल मतलब की है। मेरे मतलब की है !

श्री अध्यक्ष : आपको लेकर गये थे एक दफा !

श्री मानसिंह महार : मैं जबरदस्ती बस कर चला गया था, अध्यक्ष महोदय, मुझे बुलाया नहीं गया था। मैंने जबरदस्ती नकटाई धारण कर ली थी। मैं उनके घर पहुंच गया था। और साहब उनके साथ चला गया तो भिच भिचा कर ले गये। तो वह कोई अहसान नहीं है मेरे ऊपर। सरकारी मोटर में बैठा उनका अहसान मानता हूं, लेकिन सरकारी मोटर थी, टेक्स पेअर की मोटर थी। इसलिए एहसान नहीं मानता हूं........

श्री गोकुलचन्द शर्मा (कठूमर) : यह पिट्टू शब्द क्या है ?

श्री मानसिंह महार : वह तो आप जानें कि पिट्टू क्या होता है । मैं क्या जानूं ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह भी तो हैं ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : सामने दिखता नहीं है, क्या होता है ।

श्री मानसिंह महार : मैं निवेदन कर रहा था कि मन्त्री लोग जब हमारी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में जायें, तो चाहे हम विरोधी-पक्ष के हों, तब भी कम से कम सूचना जरूर भेज देनी चाहिए । वह कहेंगे कि हम भेजते हैं । मैं बताऊं, अभी सुखाड़िया साहब गये थे, लम्बे चौड़े दौरे में हमारी झोटवाड़ा समिति में । हम भी हमारी मोटर में बैठ कर जाते हैं । हम नहीं कहते कि सरकारी मोटर में ही जायें । लेकिन हमको सूचना नहीं दी, उनके सेक्रेटेरिएट से सूचना नहीं आई––मैं यही नहीं कहता, फिर भी कहता हूं कि जनतन्त्र का युग है, सब कुछ है लेकिन जनतन्त्र को सफल बनाने के लिए ज्यादा नीचे मत उतरिये । मैं निवेदन करूं, मेरी पंचायत समिति गोविन्दगढ़ में मुख्यमन्त्री का दौरा होने वाला था । उसके लिए, अध्यक्ष महोदय, डिफेन्स फण्ड का रुपया इकट्ठा हुआ । वह किस तरीके से किया गया । उसमें मैं नहीं जाऊंगा लेकिन रुपया इकट्ठा हो गया और मुख्यमंत्री जो पहले तो अस्वस्थ हो गये, फिर उन्होंने राजस्थान का मुख्य मन्त्री पद छोड़ने की घोषणा कर दी, फिर कांग्रेस अधिवेशन हो गया । इसलिए नहीं जा सके । तो वह रुपया अब भी सरपंच के पास पड़ा हुआ है और वह मजे से ब्याज कमा रहा है । मैं आपसे निवेदन करूं कि डिफेन्स फण्ड के लिए आप कोई भी तरीका अपनाइये । आप यह तरीका अपनाइये कि within one month or two months वे रुपये कलेक्टर के पास जमा हो जावें । यह नहीं होना चाहिए कि सरपंच के पास हजारों रुपये रहें और सरपंच हजारों रुपयों का ब्याज जमा कर खाता रहे । यह गलत तरीका है ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आप कहते हैं, या गलत तरीका है.....

श्री मानसिंह महार : आप सुखाड़ियाजी से पूछ लें ।

दो पंचायतों में मन्त्री जी दौरे पर आये, तो उनको वह रुपया दे दिया गया और बहां पर कोई मन्त्री दौरे पर नहीं पधारे इसलिए वह रकम पड़ी रही ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : पंचायत समिति में जमा हो ।

श्री मानसिंह महार : पंचायत समिति में जमा करा दें तो कोई मन्त्री गांव में आवेंगे तो रुपया कैसे ले जावेंगे । इसलिए वह वहां भी जमा नहीं हो सकता । इसलिए डिफेन्स फन्ड की रकम का कोई न कोई प्रबन्ध होना चाहिए ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : पंचायत समितियों के पास कैसे रहेगा ? आप एक दो के नाम बतावें कि किन-किन के पास पैसा है ।

श्री मानसिंह महार : सरपंच सामोद, फतेपुरा के पास पैसा पड़ा है । उन्होंने मुझसे कहा कि यह डिफेन्स फन्ड का रुपया हमारे

(श्री मानसिंह महार)
यहां पड़ा हुआ है इसका क्या करें। मैंने कहा कि आप अपने आकाओं से पूछें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपसे पूछा तो आपको बताना था .....

(कुछ माननीय सदस्य एक साथ बोलने से शोर-गुल)

(व्यवधान)

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, जब मैं अपनी स्पीच को डेवलप करता हूं तो बीच-बीच में बोल कर यह कहते है और यह चाहते हैं कि मैं अपने भाषण से विचलित हो जाऊं। मगर आज मैं अपने विचारों से विचलित नहीं होने वाला हूं। आप कितना ही डिस्टर्ब करें। मैं पक्का विचार कर आया हूं। मैं कतई विचलित नहीं होने वाला हूं। मैं अपने पाइन्ट पर रहूंगा। तो मैं यह कहूंगा कि डिफेन्स फन्ड का पैसा मन्त्रियों के नाम पर दुरुपयोग होता है उसको रोका जाना चाहिए।

अब मैं आता हूं कि इस बजट में यह कहा गया कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में करीब ३ करोड़ का घाटा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, नई योजना में घाटा तो था ही, ऊपरी तौर से वित्त-मन्त्री यह कह रहे थे. दिखता था। लेकिन यह तो घाटा हुआ तो लगाओ टैक्स, या झोली फैला कर भीख सेन्ट्रल गवर्नमेंट से मांग लो या भारत सरकार से रुपया लोन के रूप में ले लो। ये तीन तरीके आपके पास हैं। यदि इसको आप किसी बिजनेस मैन को देते तो, वह बेचारा ३ करोड़ का घाटा उसके आ जाता, तो उसका दिवाला निकल जाता। इसलिये मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप योजनाबद्ध तरीकों से पैसा लगाइये। मैं सही तरीके से कहता हूं एक गांव एक्स को ले लीजिये। बिजली की लाइन जावेगी उधर से होकर और बीच में "वाई" और "जैड" गांव भी पड़ते हैं, मगर "वाई" और "जैड" को छोड़ देंगे और फिर "ए" को बिजली दे देते है। फिर 'ए' से चले जाते और "बी" और "सी" को छोड़ देंगे और "डी" को बिजली दे देते हैं। समझ में नहीं आता कि आपकी क्या मंशा है ऐसा करने से? मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की बातें करने से बिजली का खर्चा बढ़ेगा। आप कम्पेक्ट एरिया में बिजली बढ़ाते जाइये आपको नुकसान नहीं होगा। विद्युत् मंत्री यहां पर नहीं है, अगर वे यहां पर होते, तो मैं झालारामजी (विराम) झालारामजी नहीं यह गलती से मेरे मुंह से निकल गया है, झालावाड़ हिज हाईनेस से अर्ज करता कि इस तरह से बिजली देनी चाहिये।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : झालारामजी कौन हैं?

श्री मानसिंह महार : यह तो गलती से अध्यक्ष महोदय, मेरे मुंह से निकल गया। मैं नहीं चाहता था।

इसलिये मैं निवेदन कर रहा था कि बिजली की योजना है वह बहुत अच्छी है या नहीं है, इस पर सरकार ध्यान दे।

अभी हमारे कृषि मंत्रीजी ने मोटी-मोटी बातें बताईं। मैं तो उनकी तुलना बड़ी-बड़ी बातों से नहीं कर सकता लेकिन बहस से कर सकता हूं।

तो बिजली कम से कम ऐसे गावों में तो दी जाये, जो कि इस दुनियां में एग्जिस्ट तो

Page No. 75

(श्री मानसिंह महार)

करते हों, ऐसे गांवों में न दी जावे जो गांव इस दुनियां में एग्जिस्ट ही नहीं करते हों और सैंक्शन होने के बाद दौड़ धूप की जाये कि, अरे, यह गांव तो कहीं है ही नहीं, कहां है बताया जाये। बांसा पंचायत समिति का एक गांव है उसके लिये बिजली दी गई जबकि उस नाम का कोई गांव वहां है ही नहीं। बिचारे गांव वाले कलक्टर के पास पहुंचे कि वहां पर जो गांव वालों की लिस्ट मेन्टेन होती है कहीं उसमें इस गांव का नाम हो, तो उस लिस्ट को देख कर कलक्टर साहब ने लिख दिया कि इस गांव का नाम गलती से लिख दिया गया है।

इतना ही नहीं, हमारी पंचायत समिति बांसा के दो गांव हैं, फतहपुर और कुशलपुर! तो जिस गांव में ट्रांसफार्मर लगाया गया है, उस गांव वालों को तो बिजली दी नहीं गई और पास वाले गांव में कुओं को बिजली दी गई। वैसे वह एक ही गांव है लेकिन पंचायत राज में उसको स्पलिट करके, दो गांव बना दिये गये, एक फतहपुर दूसरा कुशलपुर। तो ट्रांसफार्मर तो लगाया है फतहपुर में लेकिन जितनी भी बिजली दी जा रही है वह फतहपुर में दी जा रही है। यह सही हाल बता रहा हूं, आपके बिजली विभाग का। यह बिलकुल फैक्ट है। अगर माननीय झालारामजी 'हिज हाइनेस झालावाड़, चाहें, तो मैं इसको साबित कर सकता हूं। यह सही है कि कुशलपुर में बिजली का ट्रांसफार्मर लगा है, वहां के किसान कहते हैं कि बिजली दीजिये लेकिन दी जाती है फतेहपुर वालों को। तो यह देखने की बात है, अध्यक्ष महोदय। अगर दोनों गांवों को दी जाती तो अच्छा रहता इसलिये मैं कहता हूं कि पंचायत समिति गोविन्दगढ़ की बात है वह नोट करलें। अगर वे बिजली बोर्ड या और किसी पर बोलें तो बतादें। अगर मैं गलत हूंगा तो क्षमा मांगूंगा।

पी. डब्लू. डी. के लिये तो कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि वह तो plunder without danger है। उसमें तो ठेकेदार की वाहवाही है। ठेकेदार जिस तरह चाहे इन्जीनियर्स और मंत्रियों को नचाते हैं, और नचायेंगे; जिनके जेब से पैसा जाता है, जो २५ प्रतिशत इन्जीनियर्स को देते हैं तो क्यों नहीं नचायेंगे। कांग्रेस अधिवेशन में भी मोटी-मोटी रकमें दी जाती हैं तो नाचना ही पड़ेगा। इसमें किसी का दोष नहीं, न मंत्रियों का दोष है न इन्जीनियर्स का दोष है। मैं किसी का दोष नहीं बताता।

इस लूट में भारत सेवक समाज भी आ गया। हमारा जो जयपुर से सीकर जाने वाला नेशनल हाइवे है उसमें भारत सेवक समाज का भी शेयर आ गया। वहां पुल बनना था और सड़क चौड़ी होनी थी, तो न तो पुल ही बना न सड़क ही चौड़ी हुई। मैं मंत्रीजी से चेलेंज करके कहता हूं कि आपने भारत सेवक समाज को जो हरमाड़ा घाटी को ठीक करवाने का और सड़क चौड़ी करने का काम दिया उसमें लाखों रुपयों का घाटा हुआ है। अब भारत सेवक समाज ने कुछ नहीं किया, तो माननीय मंत्रीजी मौन बैठे रहे। क्या करें, नन्दाजी बैठे हैं अगर भारत सेवक समाज को कुछ कहते हैं तो नन्दाजी निकाल दें तो, आज जो हजार या दो हजार की तनख्वाह मिलती है उससे भी जायें।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर): भारत सेवक समाज में तो कांग्रेस के तपे-तपाये नेता रहते हैं।

श्री मानसिंह महार : यह मुझे नहीं मालूम था कि कांग्रेस में तपे-तपाये नेता रहते हैं, मैं तो सीधा-साधा आदमी हूं। मुझे तो जो लोग बताते हैं वही मान लेता हूं, अब ये तपे-तपाये नेता हैं या कच्चे लोहे हैं या कौनसे लोहे हैं, मुझे पता नहीं।

इस घाटी को सीधा करने में ३ वर्ष का टाइम नष्ट होने के बाद झक मार कर डिपार्टमेंटली वह काम कराना पड़ा ! डिपार्टमेंटली वह काम हुआ तो वह घाटी भी चौड़ी हो गई और सड़क भी बन गई। अब मैं आपसे यह पूछता हूं कि आपके द्वारा बनाये गये हमारे इस दिवालिया राजस्थान को भारत सेवक समाज के इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट से कितना नुकसान हुआ, यह जरा बता दीजिये।

शिक्षा के बारे में, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, अभी कृषि मंत्रीजी ने कहा कि इतने हजार स्कूल खुल गये। मैं कहता हूं यह सरकार स्टेन्डर्ड में विश्वास नहीं करती : हम कहते हैं, स्कूलें खोलो, पर उनमें अच्छे मास्टर रखो, लड़कों को अच्छी शिक्षा दो। पर यह तो कहते हैं कि इतने स्कूल खोल दिये, २४।। हजार खोल दिये पर जरा यह बताने की कृपा करें कि ऐसे स्कूल कितने हैं, जिनमें लड़के नहीं ? ऐसे कितने स्कूल हैं जिनमें मास्टर नहीं पहुंचते ? ऐसे कितने स्कूल हैं ? जिनके अन्दर १० बजे का टाइम होता है, तो मास्टर १ बजे पहुंचते हैं ? ऐसे कितने स्कूल हैं, क्या कभी आपने जांच करवाई है ? या जांच कराने को तैयार हैं ? ऐसे कितने स्कूल हैं, जिनमें लड़के पर्चों में ज्यादा फेल हो गये, तो उनकी कापियों में दुरुस्ती करा कर उन लड़कों को पास कर दिया गया ? क्या इसकी जांच कराई है या नहीं ? मैं आपको यह नहीं कहता कि स्कूल मत खोलो, स्कूल खूब खोलो पर शिक्षा पर रहम खाइये, शिक्षा शब्द पर रहम खाइए और बच्चों के उन अभिभावकों पर रहम खाइये जो अपने लड़कों को आपके स्कूलों में भेजते हैं। शिक्षा का स्टेन्डर्ड ऊंचा कीजिये बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिये कि वे माता-पिता को माता-पिता समझें, नालायक नहीं समझें। आज उसका नतीजा आप ही भोग रहे हैं। आज स्टूडेन्ट्स में कितना अनरेष्ट है, स्टूडेन्ट्स में जो अनरेष्ट है, उसका मूल कारण यह है कि छोटे स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में, इन्डिसिप्लिन है वह आगे जाकर कॉलेजों को अनडिसिप्लिन्ड बनाता है और उसका जो नजारा होता है वह आज बंगाल में मौजूद है। वही हालात हमारे यहां नहीं हो जायें, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप जो यह बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि २४।। हजार स्कूल हमारे यहां हो गये....

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, आबकारी) : संख्या तो बड़ी है, यह तो आप मानते हैं।

श्री मानसिंह महार : संख्या तो बड़ी है, वह तो आपके आंकड़े हैं, मैं क्या मूर्ख हूं, आप आंकड़े झूठे देते होंगे तो झूठे होंगे।

तो मैं शिक्षा के बारे में अधिक नहीं कहूंगा, लेकिन एक छोटी सी बात कहूंगा, कि समितियों में जो शिक्षा का स्टेन्डर्ड गिरता जा रहा है उसको ऊंचा उठाइये, स्कूल खूब खोलिये, उसमें ऐतराज नहीं है एक यह होता है कि ऊपर से स्कीम आजाती है कि फलां पंचायत समिति में १० स्कूल और खोले जाने चाहियें, तो दौड़ धूप होती है कि कहां कहां खोलें, अगर स्कूल खोलने की जरूरत नहीं है तो मत खोलो, पर कोटा पूरा करने के नाम पर स्कूल खोल देते हैं। मेरी

(श्री मानसिंह महार)
इस बात की उधर बैठने वाले माननीय सदस्य जो पंचायत समितियों में इस तरह की बातें देखते हैं, वे भी ताईद करेंगे। आप एज्यूकेशन दीजिये, पर गलत तरीके से काम कर रहे हैं, उसको ठीक करिये।

पुलिस के मामले में, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता था पर डिमाण्ड्स में पुलिस नहीं आ रही है, इसलिये ज्यादा बोलना पड़ेगा। पुलिस विभाग बहुत ऊंचा विभाग है। राजस्थान के इस विभाग की तो महिमा का वर्णन करना ही शायद भगवान् राम की महिमा का वर्णन करना है। हमारे मुख्य मंत्री इस विभाग के मिनिस्टर हैं, पर वे तो मुख्य मंत्री हैं, उनको और बहुत काम रहते हैं तो उन्होंने अपने सबसे नजदीकी मित्र को डिप्टी होम मिनिस्टर बना दिया। वे डिप्टी होम मिनिस्टर साहब कितने योग्य हैं, इसको मैं मिसाल पेश करूं इंग्लैंड में प्रोफ्यूमो ने मिस कीलर के साथ कुछ सोशियल कान्टेक्ट किया और वहां एक रूसी आदमी भी पहुँच गया और यह कहा गया, यह कहा ही गया, साबित करूं साबित भी पूरा नहीं हुआ कि वे कुछ सीक्रेट ले जा रहे थे। तो प्रोफ्यूमो को इंग्लैंड की केबिनेट से स्तीफा देना पड़ा। सिद्धान्त की बातें करते हैं, तो सिद्धान्त की ही बात समझता हूं कि किसी मंत्री को समझ में आ जाय। प्रोफ्यूमो को स्तीफा देना पड़ा मिस कीलर के कारण। यह हुआ कि इंग्लैंड में एक सनसनी फैली और इस मामले को बड़ा तूल दिया गया। राजस्थान के डिप्टी होम मिनिस्टर बहुत योग्य आदमी हैं उनका पी. ए. एक पाकिस्तान का एजेंट साबित हो गया....

(व्यवधान)

उसको जेल में डाल दिया गया....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): मैं महार साहब को इतना ही इन्टरप्ट करता हूं कि वे बेजानकारी में कहते हैं। मैं इस मामले में जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि इसका डिप्टी होम मिनिस्टर को क्रेडिट जाना चाहिये कि उसके पीछे सेडो लगा कर उस जगह पहुँचाया।

श्री मानसिंह महार: मैं नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य का आभारी हूं। उनकी जोइन्ट स्टाक कम्पनी की उन्होंने पैरवी की, उसके लिये भी आभारी हूं, पर मैं कहता हूं कि लालबहादुर शास्त्री ने रेलवे के एक्सीडेन्ट पर इस्तीफा दे दिया था....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: मैं महार साहब को, भूल गया था, इन महारजी को मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बात के बारे में मुझे पूरी जानकारी है। मेरी जोइन्ट स्टाक कम्पनी न आपसे है, न उनसे है और न भैरोंसिंहजी से है।

श्री मानसिंह महार: इस कम्पनी के कौन-कौन मेम्बर है, यह मुझे पता नहीं, इसलिये मैंने जो बात कही, मैं क्षमा चाहता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: जाओ माफ किया।

श्री मानसिंह महार: चाहे उन्होंने उस चीज को परस्यू किया हो, यह तो पहले उनके खुद के सोचने की बात थी, उनको खुद को सोचना चाहिये कि जिस राज्य के डिप्टी होम मिनिस्टर का पी. ए. ऐसा आदमी हो जो मुल्क इससे लड़ाई लड़ रहा

Page No. 78

(श्री मानसिंह महार)

है, उसकी ओर से हमारे खिलाफ जासूसी करे, यह आदमी इन बैंचेज पर बैठा रहे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : गिरफ्तार आपने नहीं किया, इसी सरकार ने किया है।

(विरोधी पक्ष के अनेक माननीय सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे, शोरगुल)

श्री हरीप्रसाद शर्मा: आखिर आप क्या करते गिरफ्तार नहीं करते तो ?

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : उसको माला पहनाते ? क्या आप यह चाहते थे कि पाकिस्तान के जासूसों के लिए जयपुर के बाजार में जुलूस निकाला जावे ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जोइन्ट स्टॉक कम्पनी चिल्ला रही है।

श्री मानसिंह महार : तो अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। यह तो उनके सोचने की बात है। भगवान् राम को जब सीता के बारे में, जब धोबी ने बात कह दी तो सीता को स्वतः छोड़ना स्वीकार किया।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हम आपको धोबी कहां मानते हैं ?

श्री मानसिंह महार : अजी साहब ! हम तो आपको कुत्ते की मानते हैं, कैसे चिल्लाते हैं, कुत्ते की हड्डी है क्या, क्यों डिस्टर्ब करते है ? वे इसलिये डिस्टर्ब करते हैं कि इनको किसी ने आकर कहा कि डिप्टी होम मिनिस्टर का पी. ए. ऐसी बातें करता है, तो उन्होंने कहा कि अब तो मर गये, क्या करना चाहिये, तो इन्होंने कहा कि इसको तो भेजो जेल और हम करेंगे आपकी पैरवी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं रिजेन्ट करता हूं। मैं इसके लिये एन्क्वायरी चाहता हूं, यह लाइटली भाषण से कुछ भी कह दें.......

श्री मानसिंह महार : मैं नहीं चाहता उनकी तरह भांड बनना।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो इस तरह की बातें करें उनको अलाउ नहीं करना चाहिये, एन्क्वायरी बैठा दें, या आप फैसला करें। हम आपकी तरफ इज्जत से बात करते हैं, गालियां खाने नहीं आये हैं। तुम्हें जुबान की आजादी है तो कानून की आजादी हमें भी है। हम इस तरह की बातें नहीं सुनना चाहते····

श्री मानसिंह महार : कान फोड़ लो, नहीं सुनना चाहते तो।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जुबान काट देंगे।

श्री मानसिंह महार : पहले अपने बाप दादाओं की काटो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस तरह की बातें न करें। कृपया जल्दी ही समाप्त करें।

श्री मानसिंह महार : मैं समाप्त कर रहा हूं पर, अध्यक्ष महोदय, इन्होंने खामोखाह मेरे १० मिनिट बिगाड़ दिये। मैं कोई गलत बात कह रहा होऊं, तो आप रूलिंग दे दें।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : बड़ी महत्वपूर्ण बात है, पूरी बात कहने दीजिये।

Page No. 79

श्री मानसिंह महार : मैं बड़ी गम्भीरता से बड़ी महत्वपूर्ण बात कहूंगा । यह नहीं हो सकता कि माननीय सदस्य अपने मित्र को बचाने के लिये, इस तरह की बातें करें । मैं निवेदन करूंगा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण और सीरियस मामला है ।

मैं चाहता हूं कि सदन इसको बहुत सीरियसली ले । मैं दुबारा रिपीट करता हूं कि हमारा राज्य एक बॉर्डर स्टेट है. उस बॉर्डर स्टेट का एक डिप्टी होम मिनिस्टर और डिप्टी होम मिनिस्टर का पी. ए. हमारे दुश्मन से मिला हो, डिप्टी होम मिनिस्टर को जो भी

(विराम)

इत्तलायें मिलती हों, सीरियस मेटर उठा रहा हूं अध्यक्ष महोदय, उस डिप्टी होम मिनिस्टर के पी. ए. के द्वारा सारे हमारे दुश्मन राज्य में आयें और जब तक लड़ाई चले वह बात आउट न हो इससे बढ़ कर अयोग्यता डिप्टी होम मिनिस्टर की और क्या हो सकती है ? मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से प्रार्थना करता हूं कि इनका दामन साफ है तो डिप्टी होम मिनिस्टर का स्तीफा लें और इतनी उनमें हिम्मत नहीं है तो कम से कम उनको डिप्टी होम मिनिस्टर से हटा कर दूसरा पोर्टफोलियो उनको दे दिया जाये । क्योंकि

(विरोधी पक्ष द्वारा हियर-हियर)

He has lost the confidence of the House कि वह डिप्टी मिनिस्टर रहे ।

मैं और बातें छोड़ देता हूं । अध्यक्ष महोदय, कट मोशन्स के समय कहूंगा । एक बात जरूर कहूंगा, एक बार नहीं सो बार कहूंगा, यह बहुत ही सीरियस बात है, यदि आप डेमोक्रेसी को जिन्दा रखना चाहते हैं, स्वस्थ परम्परायें कायम करना चाहते हैं तो यह निहायत जरूरी है कि राजस्थान के डिप्टी होम मिनिस्टर, मैं उनका दाद देता हूं कि पी. ए. को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनका दामन गलती पर चला गया हमारे देश का बड़ा भारी खड्डा है, इसमें राजस्थान की चार हजार वर्ग मील जमीन पर हमारे दुश्मन का कब्जा हो गया उसकी रेस्पोन्सिबिलिटी सारी राजस्थान के डिप्टी होम मिनिस्टर की है । मैं बजट भाषण समाप्त करने से पहले यह चाहूंगा कि वे स्तीफा दे दें यह उनसे प्रार्थना करूंगा, यदि वे स्तीफा नहीं दे, तो मुख्य मंत्री जी उनसे स्तीफा ले लें वह भी न हो तो सिद्धान्तों की तो हत्या होगी ही, कम से कम उनसे प्रार्थना करूंगा कि होम का पोर्टफोलियो जल्दी से जल्दी उनसे ले लें ।

आखिरी बात कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय । तथ्य रूपी बात कहूंगा । अपने ध्येय से विचलित नहीं होऊंगा ।

मैं निवेदन करूं, हमारे वित्त मंत्रीजी ने, अभी खुश हो जावेंगे, एक नक्शा रखा, करीब ९६ करोड़ की आमदनी बताई और दस लाख का इधर उधर करके उतने ही खर्च के आंकड़ों को जमावट बहुत अच्छी है इसमें कोई शक नहीं है । मैं उनको मुबारकबाद देता हूं, पर ३३३ करोड़ का कर्ज बताया तो, अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक हार्ट पेशेन्ट हूं, सिक होने लगा यह सुनकर ३३३ करोड़ का कर्जा, हमारे ऊपर । लेकिन मैं उनको हिम्मत की दाद देता हूं कि उन्होंने ३३३ करोड़ का कर्ज चढ़ाकर ऐसा रफा दफा किया है कि गत हुआ हुआ नहुआ ।

(श्री मानसिंह महार)

यह बता दूं, क्या आप उन बांधों को नीलाम करोगे, सड़कों को नीलाम करोगे, भारत सरकार के या और सरकार के गिरवी रखोगे ? जिसकी सौ करोड़ की आमदनी है और उतना ही खर्चा है उस बापड़े गरीब पर ३३३ करोड़ का कर्जा ! कितने बर्षों में चुकायेगा ? छोटीसी बात पूछता हूं, मन्त्रीजी । आप कहते हैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं ! डेफिसिट फाइनेन्सिंग को छोड़ दीजिये । भारत सरकार से कह दीजिये कि हमारा दिवाला निकल गया है । कर्जा वह चुका सकेंगे तो कुछ हो सकता है । अभी तो मौका है, वित्त मन्त्री जी, अभी तो आप स्ट्रांग है सेन्टर में । आप दिवालिया घोषित करके कुछ कर सको तो कर दीजिये, वरना बाद में दूसरा वित्त मन्त्री आवेगा तो बेचारे को मुसीबत हो जावेगी ।

एक बात बड़ी जोर-शोर से कृषि मन्त्री जी ने कही, एग्रोकल्चर की बात तो मैं बाद में कहूंगा लेकिन उन्होंने कहा कि १८ करोड़ से ९६ करोड़ का बजट पहुंच गया । तो क्या बड़ी बात हो गई, अध्यक्ष महोदय । यह तो इन्फलेशन है । आपका रुपया जो पहले १६ आने का था वह आज १२.१४ पैसे का रह गया है । वह तो अपने आप होना था । नेचुरल चीज थी । उसमें आप मन्डूक की तरह फूलिए मत । ये ही शब्द कह कर वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि राजस्थान को कर्जे में, कृपा निधान, मत डुबोइये और आप से इन्तजाम न हो तो आप सर्वगुण सम्पन्न हैं, कोई दूसरा महकमा ले लीजिये और किसी फाइनेन्सर को यह महकमा दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : श्री जयलाल ।

श्री जयलाल (डग) : अध्यक्ष महोदय, आज करीबन पांच रोज से बजट पर वाद-विवाद हो रहा है । मैंने भी इस बजट को पढ़ा । लेकिन यह बजट जो सरकार ने बनाया है इस बजट से पहले देहात की जनता, देहात का किसान और मजदूरी करने वाले लोग इस बात को महसूस करते थे कि जो अगला बजट बनेगा उसमें राजस्थान के किसानों को और मजदूरी करने वालों को, कुछ पिछड़े वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी । लेकिन ऐसा कहीं भी इस बजट में देखने नहीं आया । इस बजट को सरकार ने एक ऐसा बजट बनाया है जिसके द्वारा सरकार ने गरीब लोगों के खून को खींचने के लिए बजट रूपी इंजेक्शन बनाया है, क्योंकि इसमें आपने घाटा बतला कर और जो आपने टेक्स लगाये हैं, उन टेक्स का असर बिल्कुल गरीब लोगों पर पड़ा है ।

अध्यक्ष महोदय, तेल पर टेक्स लगाया है । तेल कौन लोग पैदा करते हैं ? हाथ से तेल निकालने वाले लोग जो दिन भर मजदूरी करते हैं, हाथ से तेल निकालते हैं और जिसका सारा परिवार इस धन्धे पर ही निर्भर है, फिर उस पर भी सरकार ने टेक्स लगाया यह बड़ी सोचने की बात है ।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा टेक्स लगाया पशुओं पर । अधिकतर पशु देहात में पैदा होते हैं और देहाती किसान इसको पैदा करते हैं । वे बेचते भी हैं और आवश्यकतानुसार खरीदते भी हैं । इसका असर विशेषकर किसानों पर पड़ा है । अध्यक्ष महोदय, वैसे सोचा जाये तो कांग्रेस के द्वारा पशुओं पर टेक्स लगाना उचित नहीं

(श्री जयलाल)

होगा, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है बैलों की जोड़ी, सरकार ने अपना हित तो नहीं सोचा सो नहीं सोचा, लेकिन देश की जनता का हित भी नहीं सोचा।

तीसरा टैक्स जो घी पर लगाया है, घी पर जो टैक्स लगा है उसका असर बिल्कुल आम लोगों पर पड़ा है। वह कैसे असर पड़ा है आम लोगों पर? जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, छोटे लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, वे अब भी मंहगा, घी नहीं खा सकते। अध्यक्ष महोदय, घी पर और टैक्स लगाने पर अधिक मंहगा होगा। गरीब लोग घी को खा नहीं सकते।

घी न खाने की जगह तेल का यूज करते हैं, इससे आप देखते हैं, आज टी० बी० की बीमारी बहुत फैल रही है।

(३ म. प.)

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आज की सरकार पिछड़े वर्ग के लिये और समाज कल्याण विभाग पर करोड़ों रुपया खर्च करती है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह रुपया जाता कहां है? आज गरीबों की परिस्थिति, आदिवासियों की परिस्थिति, हरिजनों की परिस्थिति वैसी की वैसी ही है जैसी कि बीस साल पहले थी, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। आज हरिजन के पास रहने के लिये मकान नहीं, उसको खेती के लिए जमीन नहीं, पेट पालने के लिए धन्धा नहीं। सरकार ने जो जमीन अलॉट करने के नियम बनाये हैं उसमें सरकारी कर्मचारी बहुत पक्षपात करते हैं, जिससे उनको जमीन मिल नहीं पाती। वे जमीन देने में पक्षपात करते हैं इसलिए सुचारु रूप से उनको दे नहीं पाते। कर्मचारियों में और पटवारियों में यह आम रिवाज बन गया है, जो जमीन का नम्बर लेने के लिये जाते हैं उन बिना पैसे वे बात तक नहीं करते, लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, मुझ से जब यह कहा तो मैंने कहा जमीन के लिये नम्बर लेने के लिये पैसे की क्या आवश्यकता है? लेकिन उन्होंने कहा कि बिना पैसे लिये पटवारी नम्बर तक नहीं देता है और जिन लोगों को पैसा लेकर नम्बर दे दिया लेकिन अलॉटमेंट कमेटी ने उनको जमीन नहीं दी। इस तरह से पैसा भी दिया और लोगों को जमीन भी नहीं दी गई।

इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, जो जमीन का सेटलमेन्ट हुआ वह भी गलत हुआ है।

श्री प्रभुलाल सेन्टर (खानपुर) : आप कहां की बात करते हैं?

श्री जयलाल : मैं सब राजस्थान की बात करता हूं, अम्ता में और इग में भी यही हुआ है। सेटलमेन्ट हुआ है, उसमें इतनी धांधली हुई है कि जो जमीन उपजाऊ है वह बिल्कुल गोचर में निकाल दी गई है और ऐसी जमीन जो बंजड़ है वह गरीबों को देना चाहते हैं और उससे आप यह चाहते है कि उत्पादन बढ़े........

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : तो क्या आप के ख्याल से गोचर भूमि हो वह बंजड़ होनी चाहिये?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि सेटलमेन्ट दुरुस्त होना चाहिये।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : माननीय सदस्य ने कहा कि गोचर के लिये भूमि दी गई, वह

Page No. 82

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)
उपजाऊ दी गई, तो क्या बंजड़ देनी चाहिए थी ?

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य का तो यही कहना है कि जो सैटलमेन्ट हुआ है, वह गलत हुआ है, वह दुरुस्त होना चाहिए।

श्री जयलाल : मेरा यह कहना है कि जो जमीन का सेटलमेन्ट किया गया वह जमीन को देख कर नहीं किया गया है। गांव में बैठ कर सारी जमीन की कल्पना करली है कि कौनसी जमीन किस प्रकार की है। मेरा यह कहना है कि इस प्रकार का जो सेटलमेन्ट हुआ है वह दुबारा होना चाहिये।

दूसरा सवाल यह है कि कृषि उत्पादन की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये। कृषि उत्पादन पर ही देश का सारा ढांचा निर्भर करता है। अनाज के उत्पादन के लिये अधिक से अधिक साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिये।

सिंचाई का जो विभाग है, वह बराबर पानी नहीं देता। इस कारण हजारों बीघा भूमि जहां पर गन्ना पैदा हुआ, वह सूख गया। समय पर पानी न मिलने के कारण चना सूख गया। कृषि मंत्रीजी ने कहा है कि हमारे यहां उत्पादन बढ़ा है, मैं कहना चाहता हूं कि केवल कागजों पर उत्पादन बढ़ा है, फाइलों में उत्पादन बढ़ा है, लेकिन खेती में उत्पादन नहीं बढ़ा है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसान को समय पर पानी मिलना चाहिये, इसके अलावा इसी साल गन्ने में बीमारी लगी, चने में बीमारी लगी, धनिये में लगी, अलसी में लगी, लेकिन उसके निवारण के लिये कोई उपाय नहीं किये गये। कौनसी फसल में किस प्रकार कीड़ा लगता है, इसकी जानकारी कतई नहीं दी गई कृषि उत्पादन के लिये इन सारी बातों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तभी जाकर अमेरिका से अनाज मंगाना बन्द हो हो सकेगा, उसके बिना हम कृषि में आत्मनिर्भर नहीं हो पायेंगे।

किसानों ने पशुओं की नस्ल सुधारने का प्रयत्न किया है, लेकिन मैंने कई जगह देखा है कि सांड नहीं हैं, इसलिये कई गांवों में पशुओं की नस्ल बिगड़ रही है। किसानों के छोटे-छोटे जानवर होते हैं उनको बेचकर उन्हे अच्छी नस्ल के जानवर खरीदने पड़ते हैं। इसलिये जिन गांवों में सांड नहीं हैं, उन गांवों को सांड दिये जायें। बहुत से लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है।

पाकिस्तान का जब आक्रमण हुआ, सब लोगों ने अपना अपना फर्ज अदा किया। इसमें सरकारी कर्मचारियों ने भी काम किया और सबने किया। लेकिन जब जनता का सवाल आता है, उनके लिए जब कुछ कार्य करने की आवश्यकता होती है तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। जहां तक देश-रक्षा का सवाल है वह तो हम सब का सवाल है। हमारे पूर्वजों ने पहले भी देश की रक्षा की, देश की रक्षा के लिये बड़े-बड़े वीर योद्धाओं ने अपने प्राण दिये। राणा प्रताप, राणा सांगा, बप्पा रावल, राठौड़ दुर्गादास, गोरा बादल, जयमल, फत्ता, राणा राजसिंह आदि वीरों ने अपने देश की रक्षा के लिए प्राण दिये....

श्री गंगासिंह परिहार (हिन्डोली) : आप बातें तो बहुत करते हैं लेकिन अलाटमेंट कमेटी में आप कितनी बार गये ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : गंगासिंहजी पहले अपना मुंह आइने में देख लें आपने कितनी कमेटियों में भाग लिया है।

श्री जयलाल : हमारी सरकार को सोचना चाहिये कि जब देश पर संकट था देश के जवानों के लिये खून दिया, धन दिया, अन्न दिया, अपनी नसों का खून दिया। आज जहां देश की रक्षा का सवाल है वह सारे देश की जनता का सवाल है। लेकिन सरकार की जो शासन व्यवस्था है, उसमें दुरुस्ती होनी चाहिये, उनको देश के हर वर्ग का ध्यान रखना चाहिये देश का ढांचा सुचारु रूप से चलाने के लिये।

आज हम देखते हैं कि डाकू लोग गांवों में आते हैं आदमियों को उठाकर ले जाते हैं, लेकिन किसी प्रकार भी उनकी हिफाजत का इन्तजाम नहीं। एक जगह कलेक्टर साहब पहुंच गये, डाकू उनके सामने खड़ा है, पुलिस कर्मचारी उनके साथ हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं कि वे डाकू का मुकाबला कर सके।

बारां तहसील में कोयला चौकी है। यहां आम लोगों की मारपीट की जाती है एक दिन कोयला के पास गांव है यहां गई आये....

श्री प्रभुलाल सेन्टर : यह कोयला कौन से जिले में है ?

श्री जयलाल : यह तहसील बारां में है। बनवारीलाल जी हैं उनके मकान के अन्दर घेरा लगा दिया गया, वहां शिड्यूल्ड कास्ट के चमार जाति के लोग रहते हैं, वे लोग बाहर निकले उन लोगों को बिना वजह डण्डे मारे गये। उनसे कहा गया कि बोतल लाओ, एक बकरा लाओ। इस तरह से २३२ रुपये जो उनके पास थे वह भी ले लिये इस बारे में हमने मुख्य मन्त्री को सूचना दी, कलेक्टर साहब को सूचना दी, एस.पी. साहब को दी, लेकिन किसी ने भी सुनवाई नहीं की....

जिसका चाहे तबादला करें। प्रतिदिन ऐसी घटनाएं होती हैं। पर कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। यह आपकी शासन-व्यवस्था है। अगर यह राज आपका यों ही चलता रहा तो, राजस्थान की जनता भी आपसे ऊब जावेगी और जिस तरह पंजाब, केरल और बंगाल में हो रहा है वही यहां होगा। यही दशा धीरे २ सारे देश की होने वाली है। और फिर भी यही हालत चली तो वह दिन दूर नहीं जब अंग्रेजों की तरह आपके भी जाने के दिन आने वाले हैं।

रहा सवाल शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को सहूलियतें देने का। आप पढ़ाने के लिये जितनी और जैसी छात्रवृत्तियां देनी चाहिये नहीं देते। गरीब लोग हैं, उनकी आप तक पहुंच नहीं है, फिर उनको कैसे दिया जावेगा ? लेकिन मन्त्रीजी के परिवार वालों को जरूर मिलेगी। अमृतलाल जी के लड़के, लड़कियों को कितनी छात्रवृत्तियां दी गईं, बताएं जरा। हजारों रुपयों की दी गई। इस प्रकार के मन्त्री बैठे हुए हैं, वे क्या देश का निर्माण करेंगे ? इनके परिवार का निर्माण होना चाहिये। इनके स्वार्थों का निर्माण होना चाहिये, ये तो यह जानते हैं। पर जिस दिन सबको समान लाभ आप देंगे, तब हम जानेंगे कि जनतन्त्र आया है।

(श्री जयलाल)

आज तो हाल यह है कि एक छोटे-छोटे कमरे में बीस बीस और पच्चीस-पच्चीस और पचास-पचास तक छात्र भेड़ बकरियों की तरह भरे रहते हैं उनके लिये आप मकान की व्यवस्था नहीं कर सकते। उनको तेल, साबुन और समय पर बाल काटने के साधन नहीं मिलते। यहां तक कि खाने को ज्वार के आटे की रोटियां नसीब होती हैं। क्या इस प्रकार का बर्ताव करके हमारे माइंड को आप खत्म करना चाहते हैं? हमें कैद कर रखा है आपने। कहते हैं लाखों खर्च करते रहते हैं लेकिन आपने खर्च करके किया क्या? यह तो व्यवस्था आपके छात्रावासों की है। यह हालत ठीक होनी चाहिये।

छात्रवृत्तियां समान रूप से मिलनी चाहियें। इसमें भेदभाव और पक्षपात नहीं होना चाहिये। तब भावी पीढ़ी की प्रजातन्त्र में आस्था बनेगी। पर आज तो लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया है कि अंग्रेजों के जाने के और आजादी के आने के १६ सालों के बाद भी आपने कोई प्रगति नहीं की। टैक्स पर टैक्स लगाते जा रहे हैं। हर चीज पर टैक्स लगा दिया है। पहले जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो कहते थे, कि हम छोटी जातियों के साथ यह बर्ताव करेंगे, उनको ऊपर उठायेंगे, देश को ऊपर उठायेंगे, गरीबी मिटेगी, अंग्रेज जैसे टैक्स लगाते हैं वैसे नहीं लगावेंगे और इन भावनाओं से उत्साहित होकर लोगों ने कांग्रेस को वोट दिये। पर आज अगर कांग्रेस अपने उन वायदों को अपने उन आदेशों को भूल कर अंग्रेजों के कदमों पर चलने लगी तो, जो गति अंग्रेजों की हुई वही आपकी होगी।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इन सारी बातों पर गहराई से विचार करे। तब तो देश का विकास होगा। आप लोग तभी सफल होंगे, जब आम लोगों का खयाल करेंगे।

आपके न्यायालयों में न्याय नहीं मिलता। देरी होती है। १०७ के मुकद्दमे चलते हैं। चार-चार, पांच-पांच साल तक फैसला नहीं करते। तारीखें पड़ती रहती हैं, बिचारे गवाह आते हैं और जाते हैं, खर्चे से जेर बार होते हैं लोग। इसलिए जनता को सस्ता न्याय मिलना चाहिए। जल्दी से मिलना चाहिये, तब तो लोग जानेंगे कि प्रजातन्त्र आया है और अगर इसकी ढोल की पोल में आप बैठे रहे और इसी तरह लोगों को बेवकूफ बनाते रहे तो आपका यह वक्त भी नहीं रहने वाला है।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के वित्त मंत्रीजी ने जो बजट प्रस्तुत किया, उसे मैंने पढ़ा और उनकी बातें भी सुनीं। आंकड़ों के विषय में तो विशेष क्या कहूं, पर वित्त मंत्री ने जो टैक्स लगाये हैं वे ज्यादातर गरीबों पर, गरीब जनता पर व किसानों पर हैं। उन्हीं पर लागू होते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि तेल, घी और पशु बिक्री पर जो टैक्स लगाये हैं उनको कम करें या छोड़ दें।

इसके साथ-साथ सहकारिता पर बोलना चाहता हूं। कोरा गांव है जहां एक सहकारिता समिति है उसमें करीबन ६-७ हजार का घोटाला है। लोगों के बीस-बीस रुपयों के उसमें शेयर है। इसके बारे में सरकार को पत्र भी लिख चुके हैं। पर सरकार का इधर ध्यान नहीं है। बद्रीनारायण शर्मा है, वहां

(श्री भानुप्रसाद कराड़िया)
का रहने वाला। वे कांग्रेसी भी नहीं हैं। किन्हीं कांग्रेसी के साले वाले होंगे। वे गड़बड़ करते हैं।

तीस हजार लगाकर खादी एसोसियेशन का मकान बनाया है। पर उस में मास्टर लोग किराये से रहते हैं। वहां पर न तेल की घाणी चली है न साबुन बना है। मकान यों ही पड़ा है।

इसी के साथ-साथ एक वहां पर कृषि सहकारी समिति भी है जो तीन भाइयों ने मिलकर खोली है १५-१६ हजार सरकार ने दिया है। पर न खेती होती है, न कुछ होता है और भाई-भाई सरपंच से मिलकर १५, १६ हजार लेकर बैठे हैं।

मेरा तीसरा सुझाव है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको महंगाई को देखते हुए भत्ता मिलना चाहिए, उनकी तनख्वाहें बढ़नी चाहिये।

मेरा चौथा सुझाव है कि कृषि उत्पादन के लिए अधिक से अधिक लोन, सहायता अनुदान किसानों को दिया जाये, ताकि उत्पादन बढ़े और देश की खाद्य समस्या का हल निकल सके। पर आज जो नाम मात्र का ऋण और सहायता देते हैं तो इससे किसान न पूरा सामान ला सकता है न कुछ कर सकता है। तो उनको जरूरत हो जितना ऋण और अनुदान देना चाहिये।

पांचवां सुझाव मेरा है कि सिड्यूल्ड कास्ट को १२।। पर्सेन्ट जो नौकरियां मिलनी चाहिये, वे नहीं दी जाती हैं। इस बारे में कई बार यहां भी मैंने प्रश्न रक्खे, पर उत्तर ठीक नहीं मिले। उनको १२।। पर्सेन्ट नहीं लिया जाता और अगर थोड़ा बहुत लिया भी जाता है तो उनको बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ गढ़, डूंगरपुर जैसे गांवों में, इलाकों में भेज देते हैं।

अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के लिये बस्तियों की व्यवस्था नहीं की जाती। जैसे यहां चांदपोल में है, भांखरोटा में हैं, गंगा टाकिज के पास हैं। उनकी पुरानी बस्तियां हैं, उधर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

उनको काश्त के लिये योग्य भूमि नहीं दी जाती। उनको सहायता और भूमि दोनों मिलनी चाहिये। कम से कम एक एक हजार रुपया कुओं के लिये भी मिलना चाहिये, जो नहीं मिलता।

पंचायतों में, पंचायत समितियों में और जिला परिषदों में भी हमारी शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को, वहाँ जैसे एसेम्बली में रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन दिया गया है, वह दिया जाना चाहिये। इससे आपको लाभ होगा। आज हम लोगों के वोटों के पीछे आप यहां सत्ता बनाकर बैठे हैं। किसान और पिछड़ा वर्ग ये दो ही वर्ग हैं, जो आपको ज्यादा से ज्यादा बहुमत देता है।

मैं आपको हमारे गोविन्दगढ़ पंचायत समिति में सरपंच के खिलाफ शिकायत के बारे में निवेदन करूं कि उसकी शिकायत की गई, पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। न उसकी जांच होती है न और कुछ होता है।

गोविन्दगढ़ पंचायत समिति में अग्नि काण्ड होते हैं, तो सहायता नहीं दी जाती। जैसे चौमू है, मजाड है और एक दो जगह जो अनुदान और सहायता मिलनी चाहिये वो नहीं मिली है।

(श्री भानुप्रसाद कराड़िया)

वहां पर जो बिजली दी गई है उसके लिये भी अभी जो ट्रान्सफॉर्मर लगाये जाते हैं, उसमें क्या होता हैं कि जो पहला ट्रान्स-फार्मर होता है, उसमें तो बिजली ठीक आती है लेकिन दूसरे में कम आती है और तीसरे में उसमे भी कम आती है, तो जो बिजली दी गई है उससे भी नुकसान पहुंचता है। मैं मानता हूं कि आपका विधान बहुत ही अच्छा है मैं उसका समर्थन करता हूं और राज्य सरकार का समर्थन करता हूं लेकिन उसको कानूनन कार्य रूप में परिणत करना चाहिए और मैं समझता हूं कि कानून को कार्य रूप में परिणत करेंगे तो जनता को सुविधा मिलेगी और जो आप योजनायें करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन खास तौर से मेरा मकसद यह है कि कानून को कार्य रूप में परिणत किया जाये। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्रावासों वगैरह की सुविधाओं के लिए मैं समझता हूं कि सरकार उनकी ओर ध्यान दे और सहकारी समितियों के बारे में जो बताया है उसकी तरफ भी ध्यान दें।

मैं इतना ही कहते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल सुखाड़िया।

श्री श्रवणलाल: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप (मुख्य मंत्री की ओर मुखापेक्ष)

(३.२३ म. प.)

जनलेखा एवं प्राक्कलन समितियों १९६६-६७ के हेतु सदस्यों के लिए निर्वाचन संबंधी प्रस्ताव

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम २३०(१) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जन लेखा समिति १९६६-६७ के लिए १० सदस्यों का निर्वाचन किया जावे।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की अनुमति है कि प्रस्ताव स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम २३२ (१) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति सन् १९६६-६७ के लिए १५ सदस्यों का निर्वाचन किया जावे।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की अनुमति है कि प्रस्ताव स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(३.२५ म. प.)

आय-व्ययक १९६६-६७ पर अग्रेतर सामान्य विचार विमर्श

(पूर्व क्रम से)

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**: अध्यक्ष महोदय, इस सदन में इस वर्ष के बजट पर यह सामान्य वाद-विवाद जब से चल रहा है उस दौरान में माननीय सदस्यों ने बहुतसी बातें यहां पर उठाई। सबसे पहले मैं यह

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी बजट प्रस्तुत किया जाता है उसके पीछे सरकार अपने प्रदेश या देश के भविष्य के बारे में किस प्रकार की कल्पना करके चलती है, उसका एक अन्दाज उससे मालूम होता है। जहां तक राजस्थान के इस बजट का प्रश्न है या देश की नीतियों का प्रश्न है, हम लोग इस बात में विश्वास करके चलते हैं कि देश के लिये यह आवश्यक है कि वह विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा देश के उत्पादन को बढ़ायें, देश की गरीबी को दूर करें, अज्ञानता को दूर करें और देश को समृद्धिशाली बनाने की तरफ आगे बढ़ें। प्रश्न यह उठता है कि इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिससे कि मैं समझता हूं आम तौर से किसी भी पक्ष के माननीय सदस्यों के बीच में मतभेद नहीं है कि किस प्रकार से पहुँचा जावे। जब इस पर विचार करने लगते हैं तो स्वभाविक तौर से यह प्रश्न खड़ा होता है कि हमारे जैसे देश में कि जहां सदियों से व्यापक रूप से गरीबी फैली हुई है, आबादी बहुत ज्यादा है इस देस के अन्दर, अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम अलग अलग क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करें और दूसरे साधनों को ढूंढें कि जिससे देश का, देश के लोगों के जीवन का माप-दन्ड ऊंचा हो सके।

इन तीन पंचवर्षीय योजनाओं के अन्दर, माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रयत्न किये गये उन प्रयत्नों के फलस्वरूप जो कुछ उपलब्धियां हुई उनको सदन में अलग अलग तरह से समय समय पर रखा गया है। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम उस बात की कल्पना को भी सामने रख कर चलें कि आज अगर यह पंचवर्षीय योजनायें नहीं होती, अगर प्लानिंग के जरिये देश को आगे बढाने के लिए प्रयत्न नहीं किए जाते तो इस देश के अन्दर जितनी आबादी बढ़ी, जितनी इसकी गरीबी थी उस परस्थित में और उस भूमिका को सामने रखते हुए देश की स्थिति क्या होती? क्योंकि इन्वेस्टमेंट करके जो परिणाम सामने आये उन परिणामों से यह कहा जा सकता है कि जितना हम आगे बढ़ना चाहते हैं उसके मुकाबले में हम कम आगे बढ़े। लेकिन आखिर आगे बढने लिए कौन सा मार्ग अपनाना चाहते हैं? जब यह प्रश्न सामने खड़ा होता है हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो बांधों का निर्माण करना होगा, कुओं को बनवाना होगा, सॉइल कन्जर्वेशन में काम करना होगा, सीड के बारे में काम करना होगा, फर्टीलाइजर के बारे में काम करना होगा चाहे जिस क्षेत्र को लें यह, माननीय अध्यक्ष जी निर्विवाद बात है कि आज चाहे अमेरिका या दूसरे देश के लोग हमारी एग्रीकल्चर के साथ मुकाबिला करें हमारी सबसे पहली कमी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कुछ चीजों की आती है। पानी की कमी सबसे पहले आती है। अगर पानी की उपलब्धि हो तो हम खेती की पैदावार बढ़ा सकते हैं। दूसरे शिक्षा का सवाल सामने आता है जिससे नये टैकनिक से काम कर सकें और उसके साथ ही साथ, अध्यक्ष महोदय, यह निर्विवाद बात है कि एग्रीकल्चर को भी इन्डस्ट्री मानकर उसमें इन्वेस्टमेंट का सवाल आयेगा। बिना उसके अन्दर इन्वेस्टमेंट किये हुए केवल यह समझ कर चला जाये कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अपने आप हो जायेगा तो उसके परिणाम भी सामने नहीं आ सकते। तो घुमा फिराकर सवाल यह होता है कि शिक्षा आम गांवों में फैले जिससे नये टैकनिक की

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

वह खेती के मामलों में अपना सकें। इरिगेशन, पॉवर और कुए आदि दूसरी चीजें भी ज्यादा से ज्यादा हों जिससे उसके उत्पादन में मदद मिल सके और इन सब चीजों का मतलब यह होता है कि इन्वेस्टमेंट। उसी प्रकार से, अध्यक्ष महोदय, यह भी मानी हुई बात है कि देश केवल मात्र कृषि के के ऊपर ही अपना विकास आगे करके नहीं चल सकता। क्योंकि कृषि का और उद्योग का मामला भी जुड़ा हुआ है। आज जितना हमारी धरती के ऊपर पहले से ही वजन है, हमारी धरती के ऊपर जितनी खेती करने वाले हैं, जितने हमारे छोटे होल्डिंग्स है उनको देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि इस देश के अन्दर औद्योगीकरण भी हो। जिससे जो सरप्लस लेबर फोर्स हमारे देश के अन्दर आती है और जो पहले से अनएम्प्लायेड है उसको हम एम्पलॉयमेन्ट दे सकें और धीरे धीरे इसकी कोशिश कर सकें कि सम्भव हो तो जमीन के ऊपर आज जितना प्रेशर है उसको कम करें। क्योंकि जमीन के ऊपर सरप्लस जब तक किसान के पास नहीं है या उसको और तरह से कर्जा नहीं मिले, उत्पादन बढ़ाने की क्षमता उसकी सीमित हो जाती है। जितना भी इनवेस्टमेन्ट कर सकेंगे उतना ही प्रोडक्शन के अन्दर आगे बढ़ सकते हैं। तो यह योजनाओं का क्रम बन जाता है जिसके अन्दर जो इनवेस्टमेन्ट के लिए अरबों रुपयों की जरूरत पड़ती है हमारे देश के अन्दर भी इस के बारे में इन तीन पंचवर्षीय योजनाओं के अन्दर प्रयत्न किये गये और माननीय अध्यक्ष जी इस बात को भी लक्ष्य में रख कर चलना होगा कि जहां हम आगे बढ़ने के बारे में चर्चा करते हैं हमारे जैसे देश के सामने एक निश्चित सुनियोजित योजना के जरिये अपने विकास को करने का कान एक तरह से भारत वर्ष के अन्दर पहली बार स्वतंत्रता के बाद शुरू हुआ है और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है और हमारे देश का पिछला ट्रेडीशन है, इन सब के अलावा नये तौर से देश के विकास के सम्बन्ध में कांग्रेस ने पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं, इस पर चिंतन करना शुरू किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में ही हमने इसके बारे में सोचा कि हम योजनायें बनाकर ही आगे बढ़ सकेंगे और उन के समय में ही इसके बारे में विचार किया गया था। और उनके सामने से ही योजनाओं को रखकर देश को आगे बढ़ाने के बारे में प्रयत्न करते हुए चल रहे हैं।

इस बीच में कई बाधायें आईं, चीन का हमला हुआ, पाकिस्तान का हमला हुआ और सेना पर खर्चा बढ़ता हुआ चला गया जो कि नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेन्डीचर है, जो नॉन प्लॉन एक्सपेंडीचर है। इन सब खर्चों के बढ़ने के बावजूद देश के अन्दर हम आज यह कह सकते हैं कि जो हमारे लक्ष्य थे उन तक हम नहीं पहुँच पाये हैं, लेकिन यह सब प्लॉन नहीं होते तो निश्चित बात मान कर चलना चाहिए कि जो बेरोजगारी और गरीबी है वह आज काफी मात्रा के अन्दर यहां होती। अब जो प्रयत्न किये गये उन प्रयत्नों में हमारी परकेपिटा इनकम कितनी बढ़ी, नहीं बढ़ी यह प्रश्न विवाद का हो सकता है, मतभेद का प्रश्न हो सकता है लेकिन यह निश्चित बात है कि हमें योजनाओं को आगे बढ़ाने केलिये प्रयत्न करना होगा और उनको बढ़ाने के लिए, अध्यक्ष महोदय, यहां तक धन को उपलब्ध करने का प्रश्न है

Page No. 89

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
तो उसके जरिए आपके टैक्स हो सकते हैं या लोन्स हो सकते हैं। इसके सिवाय चाहे वह नोन टैक्स रेवेन्यू हो, चाहे टैक्स रेवेन्यू हो, चाहे लोन्स के जरिए हो, चाहे केपिटल असेट्स को सेल करके इन्कम की जाय, इन सब साधनों से इन्वेस्टमेंट के पोटेंशियल को आगे बढ़ाकर देश को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जनता के अन्दर आज, मैं समझता हूं कि बहुत से माननीय सदस्य भी जानते हैं, मैं भी राजस्थान के कई कोनों में घूमता हूं, मैं आज निश्चित तौर से इस बात को कह सकता हूं कि चाहे इसके अन्दर कितनी ही मत भेद की बातें कही जायं, जो राजस्थान आज से पन्द्रह साल पहले था, जो आदिवासी और दूसरे तबके के लोग थे, उन लोगों को जितना पहिनने को और खाने को मिलना था, आज उन गरीबों की हालत में निश्चित तौर से इन पन्द्रह वर्षों में फर्क आया है। आप इन्कार करना चाहें तो करें लेकिन यह निश्चित है कि उनके जीवन-स्तर में फर्क आया है।

मैं अध्यक्ष महोदय, जानता हूं उदयपुर डिविजन के इन आदिवासी लोगों को जो पहले महुवे के फूल और टीमूरी और दूसरी दूसरी चीजों पर गुजर करते थे, आज के दिन वे खेती के अन्दर विश्वास ही नहीं करते हैं बल्कि आज वहां कपास की पैदावार होने लगी है। आज उन इलाकों में लोगों के मानसिक धरातल में अन्तर होने लगा है। आखिर यह शिक्षा का, इरिगेशन के साधनों का, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन के भावों का और उनके रहन सहन में परिवर्तन होने का कारण ही है जिसकी वजह से उनकी हालत में अन्तर हुआ है।

माननीय अध्यक्षजी, राजस्थान के अन्दर जो हम पर केपिटा और दूसरी इन्कम के बारे में बहस करते हैं और उन फिगर्स के बारे में वादविवाद भी होता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्टैटिस्टिक्स के फिगर जाते हैं उनका एक निश्चित फॉर्मूला है उसके आधार पर ही वे फिगर्स निकाले जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो हम राजस्थान के अन्दर जमीनों का अलॉटमेंट करते हैं हजारों लाखों व्यक्तियों को, उसका रिफ्लेक्शन पूरी तौर से इसमें नहीं आता है क्योंकि उनके कुछ सेट फॉर्मूला हैं जिनको लेकर ही फिगर्स निकाले जाते हैं। एनोमल हस्बेंड्री के द्वारा जो विकास होता है उससे भी अन्तर आता है।

आज राजस्थान के अन्दर जो कुछ पहले स्थिति थी उस स्थिति को समझने के लिए और उस पर विचार करने के लिए यह आवश्यक होगा कि हम राजस्थान के उस जमाने को देख कर चलें कि राजस्थान पहले क्या था और अब क्या है ?

माननीय अध्यक्षजी, यहां पर टैक्स के बारे में बातें कही गई तो बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि किसानों के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, सरकार किसानों के हित की दृष्टि से सोचना नहीं चाहती। मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यही राजस्थान सरकार है कि जिसने सारे हिन्दुस्थान के अन्दर सबसे पहले जागीरदारी प्रथा समाप्त की और जो जागीरदारों के टीनेंट्स थे उनको बिना उनसे मुआवजा लिए हुए कानून के एक ही झटके में मालिक बना दिया। यू० पी० के अन्दर जमींदारी समाप्त हुई तो भूमिदारी का हक प्राप्त करने के लिए उनको मुआवजा देना

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

पड़ा करोड़ों रुपयों का। मुझे मालूम है कि सौराष्ट्र के अन्दर जागीरदारी समाप्त हुई तो उनको करोड़ों रुपया मुआवजे का देना पड़ा और तब जाकर वे खातेदार बने, इसके विपरीत राजस्थान के अन्दर मुआवजा राजस्थान सरकार चुका रही है और किसान खातेदार बन रहा है, बिना एक पैसा मुआवजे का चुकाए और आज लाखों व्यक्ति खातेदार बन गए हैं राजस्थान में।

मैं यह निवेदन करता हूं कि किसानों के हित का, किसानों की दृष्टि से सोचने का हम लोगों ने शुरू से ध्यान रखा है हम जानते हैं कि यहां ८०,८५ प्रतिशत किसान रहते हैं। और जिस स्टेट के अन्दर इतने लोग रहते हों तो उनकी शक्ति बढ़नी चाहिये और राजस्थान के अन्दर किसानों की शक्ति जागीरदारी समाप्त होने के बाद किस प्रकार से बढ़ी है, आज इसको इन्कार करके नहीं चल सकते। न केवल उनको खातेदारी हक ही मिले हैं बल्कि उन पर जो एक शोषण था, जो अनिश्चितता थी, जो लाटा, बांटा, कूंता के रूप में उनसे वसूल किया जाता था, आज उस व्यवस्था के हटने से निश्चित तौर से राजस्थान के किसानों के अन्दर खुशहाली आई है, फर्क पड़ा है।

मैं इस बात को मानता हूं कि आज उन लोगों की हैसियत जिस मात्रा के अन्दर बढ़नी चाहिए थी वह नहीं बढ़ी है लेकिन उसके लिए माननीय अध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें उसके लिए ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेन्ट और मजदूरी के लिए रास्ता ढूंढना चाहिए। आज कृषि के अलावा दूसरे कामकाज के अवसर उनको कम मिलते हैं, मामूली अवसर प्राप्त होते हैं, उनको व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे वे आगे बढ़ सकें।

माननीय अध्यक्षजी, कल जब योजना मंत्रीजी कुछ स्टेटिस्टिकल फीगर्स दे रहे थे तो उसके बारे में यह सवाल उठ रहा था कि यह अन्तर बहुत बढ़ता जा रहा है। दरअसल जो अन्तर बढ़ता जा रहा है उसकी वजह यह है कि जो कॉन्स्टेंट प्राइस केलकुलेट करने का प्रोसेस है वह अलग है। हम अपने यहां राजस्थान की जो कॉन्स्टेंट प्राइस केलकुलेट करके चलते है वह सन १९५४-५५ की प्राइसेज के आधार पर करते हैं जब कि हिन्दुस्तान के फिगर्स ४८-४९ की प्राइसेज पर आधारित होते हैं। मैं इसके विवाद में नहीं पड़ना चाहता लेकिन इतना निवेदन अवश्य कर देना चाहता हूं कि तीसरी योजना के चौथे वर्ष के जो फिगर्स निकाले गए हैं वह परसेंटेज नियरेस्ट टू दी ऑल इण्डिया फिगर रहा है। उसको अगर समझने की कोशिश की जाय माननीय अध्यक्ष, तो उससे एक बात जाहिर होती है कि राजस्थान के अन्दर जहां दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर हमारी कुल इन्कम के अन्दर, प्लान पीरियड में १४.६१ की इन्क्रीज़ हुई थी और पर-कैपिटा इन्कम २.११ या कुछ थी वहां पर भारतवर्ष के अन्दर उसकी कम्पेरेटिव इन्कम जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुई, उनकी जो इन्क्रीज हुई वह २१.४७ थी हमारे १४.६१ के कम्पेरेटिव में और पर-कैपिटा इन्कम उनकी हुई ९.४८, हमारी २.११ के कम्परेटिव में। और अब तीसरी पंचवर्षीय योजना के जो चार साल के आंकड़े उपलब्ध हुए है तो उन चार सालों के अन्दर अध्यक्ष महोदय, हमारी टोटल इन्कम के अन्दर १७.२९ की इन्क्रीज़ हुई है और हिन्दुस्तान

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

के अन्दर भी १७.२९ की इन्क्रीज हुई है। सैकिंड प्लान का गैप ज्यादा था। थर्ड प्लान के एचीवमेंट्स में दो दो अकाल पड़े तथा और और भी परिस्थितियां पैदा हुई। इन सारी परिस्थितियों के बावजूद जो हमारी इन्क्रीज हुई है कम्पेरेटिवली उसके फिगर मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूं। पर-कैपिटा इन्कम हमारी ६.६४ बढ़ी है वहां आल इण्डिया की ७.२३ है। इसके अन्दर कारण यह भी हैं कि जो परसैन्टेज पोपुलेशन के इन्क्रीज का है वह ऑल इण्डिया परसैन्टेज के मुकाबले राजस्थान का परसैन्टेजकम्पेरे-टिवली ज्यादा है। इस वजह से पर-कैपिटा में अन्तर आया है। मेरा निवेदन करना यह है कि थर्ड प्लान में जहां हमारे सामने बहुत सी मुश्किलातें थीं, यह पंचवर्षीय योजना इस प्रकार की हुई कि इसमें हमारे यहां दो-दो अकाल पड़े और जैसा हमारे वित्त मंत्रीजी ने बताया कि ११ करोड़ का हमारा डेफिसिट रहा है और हमारी तीसरी योजना जो २३६ करोड़ की थी उसमें से २०६ करोड़ कुछ माल का खर्चा हो जाएगा। उसके अन्दर कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि टैक्स तो हमने पूरा वसूल कर लिया लेकिन टैक्स पूरा वसूल करने के बाद भी हम अपनी पंचवर्षीय योजना के टार्जेट पर नहीं पहुंच पाए। स्पष्ट है अध्यक्ष महोदय कि हमारे सामने यहां सदन के अन्दर पहले भी कई बार बताया जा चुका है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के ओवर ड्राफ्ट के पेमेंट का सवाल था, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में सेल आफ लैंड और बैटरमेंट लेवी से इन्कम होनी थी उसका शोर्टफाल रहा है। इसके अलावा इस चीज को भी हमें सामने रख कर चलना होगा कि इस तीसरी योजना के अन्दर नौ करोड़ का एक्सपेंडीचर तो फेमिन पर ही करना पड़ा और छः करोड़ का एक्सपेंडीचर डियरनेस अलाउंस पर करना पड़ा। इस प्रकार पन्द्रह करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेंडीचर हमें नॉन-प्लान साइड में करना पड़ा, इस वजह से भी वह बढ़ गया।

उन खर्चों के बढ़ने के प्रभाव से आखिर हमारी शक्ति आगे जो कुछ काम करने की थी उसके अन्दर अन्तर हुआ, और जब फेमीन पड़ता है, अध्यक्ष महोदय, तो एक्सपेन्डीचर ही सिर्फ नहीं बढ़ता है, लेकिन हमारी इनकम साइड पर भी उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है।

श्री भैरोंसिंह : आपने बताया फेमीन के लिए भी नौ करोड़ रुपयों का कि नॉन-प्लान एक्सपेन्डीचर हुआ, तो फेमीन के लिए दो करोड़ रुपयों का प्लान एक्सपेन्डीचर भी शामिल हैं? हमने ५ वर्ष में ६ करोड़ रुपया फेमीन के ऊपर खर्च किया है तो वह केवल नॉन-प्लान का एक्सपन्डीचर है, लेकिन पिछली बार आपने हाउस में यह भी कहा था कि फेमीन के सम्बन्ध में जो खर्च हो रहा है उसका ५० परसेन्ट, हमारी कोशिश यह है कि प्लान-एक्सपन्डीचर हो जाय और प्लान के खर्चे को मीट कर लिया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह मैंने प्लान पीरियड का बताया है। उसके अन्दर प्लान में केवल खर्च हुआ। अगर बजट आता है तो प्लान की जो रोड़ थी, उनके लिए अलग पैसा था। उन रोड्स पर काम हुआ तो वह एडीशनल एक्सपेन्डीचर का पैसा नहीं है। यह एडीशनल एक्सपेन्डीचर किया गया जिसके लिए हम चाहते थे कि प्लान से कुछ

Page No. 92

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

एडीशनल एक्सपेन्डीचर मिल सके। बहुत सी रोड्स पर, नाड़ियों पर कई काम लगाए गये, वह उसमें नहीं आता है।

माननीय अध्यक्षजी, मैंने निवेदन किया कि तीसरी पंचवर्षीय योजना पर स्वभाविक तोर पर इस वर्ष जब हम बजट के ऊपर विचार कर रहे हैं तो हमारा ध्यान जाना आवश्यक हो जाता है, और मैं यह समझता हूं कि वह ध्यान सदन ने इस ओर आकर्शित किया, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता था कि यह फेक्टर्स एक तरफ हैं।

दूसरे, माननीय अध्यक्षजी, इसके साथ इन्फलेशन भी इस प्लान पीरियड के अन्दर जो कि देशव्यापी हुआ उसकी वजह से फिसकल टार्गेट्स पर असर हुआ। यह ठीक बात है कि इन्फलेशन नहीं होना चाहिए और प्राइसेज कॉन्स्टेन्ट रह पायें तो बहुत अच्छी बात है जिससे कि हम अपने एचीवमेंट्स को पूरा कर सकें, लेकिन उस इन्फलेशन को रोकने के जो गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की तरफ से फिजीकल मेजर्स लिए गये, जो रेग्यूलर मेथड्स इसके बारे में काम में लाये गये, जैसे जोनल सिस्टम कर मूवमेंट्स वगैरह फूडग्रेन्स को रोका तो उसका असर हुआ, लेकिन उसके बावजूद प्रोडक्शन उसके मामले में मूल चीज है। आज देश के अन्दर वह बढ़ना चाहिए जिससे कि इन्फलेशन को रोक सकें। आज प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमारे सामने आगे की योजनाओं का प्रश्न आकर खड़ा होता है। अभी जिन योजनाओं को हाथ में लेकर चल रहे हैं उनमें, माननीय अध्यक्षजी इस तीसरी पंचवर्षीय योजना काल के अन्दर उद्योग-धन्धों के अन्दर काफी तरक्की होनी चाहिए और हुई है। बहुत से नये उद्योग चालू हुए हैं, और नये नये उद्योगों के जरिये हमें चाहे इन्डाइरैक्ट टैक्स के रूप में हो, चाहे नोन-टैक्स रेवेन्यू के रूप में हो. राजस्थान को उसकी वजह से मदद मिली है, आज राजस्थान, बम्बई-मतलब महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात या दूसरे प्रदेशों के मुकाबले आया तो आज उन स्टेट्स के पास जिनके यहां इन्डस्ट्रियल पोटेन्शियल पहले से ज्यादा है, उन स्टेट्स को आसानी होती है अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने के अन्दर व मुकाबले उसके जो केवल एक कृषि-प्रधान देश हो, कृषि-प्रधान प्रदेश हो। आज हमारे सामने भी यह समस्या है, इसी लिए हम यह समझते हैं कि हम अपने औद्योगीकरण को दिशा में आगे कदम उठायें।

माननीय अध्यक्षजी, यहां कई बार यह सवाल उठाया जाता है उद्योगों के बारे में कि अमुक कन्सेशन्स दिये गये, अमुक बातें हुई। मैंने बार बार माननीय सदस्यों से निवेदन किया, आज भी मैं यह निवेदन करना चाहते हूं कि हमें इस मामले को बहुत स्पष्ट करा कर चलना होगा कि हम राजस्थान के डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहते हैं? राजस्थान में आज का ही सवाल नहीं है, राजस्थान के अन्दर ही जो पुरानी स्टेट्स थीं उन स्टेट्स में, जिनके फीगर्स को यहां पर कोट करके बैड इन्वेस्टमेंट और गुड इन्वेस्टमेंट के उदाहरण दिये गये उनसे यह बात स्पष्ट तौर से जाहिर हुई है कि जयपुर स्टेट के अन्दर वी० टी० कृष्णमाचारी जैसे योग्य शासक, सर मिर्जा इस्माइल जैसे योग्य शासक, जयपुर जैसी जगह में जो कि कम्यूनेकेशन्स के लिहाज से ज्यादा नजदीक था दिल्ली के और दूसरे यहां पर साधन थे, उनके जमाने में भी

Page No. 93

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जयपुर उद्योग को जहां ७५ लाख का प्रिफरेन्शयल शेयर ३ पर्सेन्ट पर दिया गया और शर्तें भी थीं टैक्सों के बारे में उस जमाने में कि जो भी उद्योग लगेगा उस पर इन्कम टैक्स नहीं होगा, कस्टम नहीं होगा, और कोई टैक्स नहीं लगेगा, रेल की लाइन बना देंगे, और कन्सेशन्स दिये जायेंगे। क्यों यह सब करना पड़ा? आखिर वे जानते थे कि अगर उद्योग स्थापित होते हैं, उद्योग स्थापित होकर आगे तरक्की होती है तो हमको लाभ होगा। जयपुर स्पिनिंग मिल के अन्दर जो इन्वेस्टमेंट किया गया वह इन्वेस्टमेंट मिर्जा इस्माइल और वी० टी० कृष्णमाचारी के जमाने में किया गया। इसलिए किया गया कि यहां की इन्डस्ट्री की तरक्की की जाय कि जिसकी वजह से एक उद्योग यहां पर लग सके और उससे आगे काम बढ़ सके।

माननीय अध्यक्षजी, हिन्दुस्तान के अन्दर कुछ जगह तो ऐसी हो गई हैं, जैसे बम्बई, कलकत्ता और कुछ और जगह कि जहां पर आज समस्या यह है कि वहां पर उद्योग नहीं लगने चाहिए और उद्योगों को दूसरी जगह जाना चाहिए वहां पर कन्जेशन हो रहा है एक तरह का, लेकिन उद्योग लगाने वाले वहां पर ही लगाना पसन्द करते हैं, क्योंकि वहां पर रॉ मेटेरियल एवेलेबल हो जाता है, स्पेयर पार्ट्स एवलेबल हो जाते हैं, मार्केट एवेलेबल हो जाता है, पावर एवेलेबल हो जाती है। आज राजस्थान के अन्दर कुछ उद्योगों को छोड़कर अगर माननीय सदस्य इस पर विचार करें कि रॉ मेटेरियल भी बहुत सा हमें बाहर से लाना होता है, उनको प्रोसेसिंग करके एक्स-पोर्ट भी बाहर करना पड़ता है। और चीजों को छोड़ दें। आज तो कई स्पिनिंग युनिट्स की यह हालत है कि काटन भी बाहर से लाते हैं, सूत यहां तैयार करते हैं और एक्सपोर्ट दूसरी स्टेट को करते हैं। सिर्फ प्रोसेसिंग का काम यहां पर होता है। तो इन चीजों के लिए एक तरह से राजस्थान में बेस बनता है, उसमें वक्त लगेगा। मैं समझता हूं कि आज से १० साल के बाद, आज से ७ साल के बाद, कह नहीं सकता कब, लेकिन १० साल बाद ऐसी स्थिति पैदा हो तब कन्सेशन देने के बजाय उस वक्त की गवर्नमेंट टर्म्स डिक्टेट कर सके। लेकिन बैकवर्ड एरियाज के अन्दर उद्योगों को ले जाने के लिए कन्सेशन्स देने होंगे और मैं यहां तक इस बात को मानने वाला हूं कि भारत सरकार और प्लानिंग कमीशन को इस बात को सोचना चाहिए कि जो बैकवर्ड रीजन्स है उन बैकवर्ड रीजन्स के अन्दर जो इन्डस्ट्रीज लगायें उस इन्डस्ट्री लगाने वाले को लोन्स के मामले में, दूसरे इन्वेस्टमेंट के मामले में, लाइसेन्स के मामले में विशेष तौर से कन्सेशन्स दिए जाने चाहिए कि जिससे दूसरों के एट पार वह आ सके; नहीं तो इसके अन्दर हमारे सामने और कई बहुत सी पेचीदगियां खड़ी होने वाली है। आप राजस्थान की बात छोड़ दें। इंगलेण्ड जैसे इन्डस्ट्रियेलाइज्ड देश के अन्दर स्कॉटलेण्ड और आयरलेण्ड जैसे दूसरे बैकवर्ड एरियाज हैं, वहां मैंने देखा है कि स्पेशल कन्सेशन्स देते हैं। वहां पर लैण्ड एक्वायर करके, बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्ट करके, स्पेशल लोन देकर के स्कॉटलैण्ड में इन्डस्ट्रीज लगाते हैं, आयरलैण्ड में इन्डस्ट्री लगाते हैं। इंगलैण्ड जैसे इन्डस्ट्रियेलाइज्ड देश में ऐसे कन्सेशन्स दिए जाते हैं तो आज राजस्थान के अन्दर अगर हम यह समझते हैं कि इसको हमें इन्डस्ट्रियेलाइज करना है तो इन्डस्ट्रियेलाइज करने के लाभ पर, मैं कोई आंकड़े नहीं देना चाहता हूं; आज हर

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

व्यक्ति इस बात को जानता है कि इन्डस्ट्री लगाने से इन्कम टैक्स में हमको शेयर मिलता है, एक्साज ड्यूटी में शेयर मिलता है, इन्टर स्टेट सेल्स टैक्स में शेयर मिलता है, और यदि शेयर्स के अलावा एम्प्लायमेंट होकर जो लेबर उसके अन्दर काम करता है और जो रुपया दूसरी स्टेट या फोरिन में माल एक्सपोर्ट करने की वजह से कमाता है और उसका सर्क्युलेशन होने की वजह से और मार्केट की इन्कम होती है वह एडिशनल इन्कम होती है, तो आज हमें एग्रो-इन्डस्ट्रियल सोसायटी के तौर पर सोचना चाहिए और सोचना होगा।

एग्रीकल्चर को इग्नोर करके हम चल नहीं सकते, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारा बेसिस है। चौथी पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चर को मुख्य मानकर चलना होगा। इस बात को लक्ष्य में रखकर चलना चाहिए कि हमारी सोसायटी एग्रो-इन्डस्ट्रियल सोसायटी है। अब प्रश्न यह खड़ा होता है, माननीय अध्यक्षजी, कि कुछ टैक्स लगाकर और उसके रुपये से गरीब चाहे किसान हों, चाहे मजदूर हों, को पढ़ा कर योग्य बना सकें, तो उसका प्रयत्न करना चाहिए। अगर थोड़ा सा टैक्स का वजन आता है तो उस टैक्स के वजन को न उठा कर निरक्षरता फैलाना चाहें और उत्पादन को आगे नहीं बढ़ायें तो इन दोनों विचार धाराओं के बीच में संघर्ष है। स्पष्ट रूप से हम इस बात को मान कर चलते हैं कि हमें उसकी शक्ति को बढ़ाना होगा और इस शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें ही नहीं दुनिया भर में, चाहे जिस देश में जाकर देखें सिवाय उन देशों के जहां १०० साल पहले साइन्स और टैक्नोलॉजी के विकास की वजह से एडवान्स कर गये हैं, उनको बड़ा फायदा मिला है, लेकिन जो साम्यवादी देश हैं जो अभी साम्यवादी व्यवस्था कायम कर रहे हैं किस प्रकार की मेहनत करके, मुश्किल में से निकल कर उन्होंने एक बेस बनाया है। यह प्रश्न देश के सामने है, हमारे सामने है; राजस्थान जैसी जगह के लिए जो कि पिछड़ गया है, बैकवर्ड रहा है कई सैकड़ों सालों से, उसको आगे बढ़ाने के लिए और ज्यादा प्रयत्न करने की आवश्यकता होगी। हमें इस क्षेत्र को बढ़ाना है।

प्रकृति ने हमें साधन दिए हैं, हमारी जमीन उर्वरा है पानी का सवाल हमारे सामने बराबर खड़ा होता है, और हर एक माननीय सदस्य चाहे वह किसी दल के हों, इस सदन के अन्दर बोलते हैं तो हरएक इस बात को कहता है कि ट्यूब वैल्स ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, सड़कें ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, बिजली ज्यादा से ज्यादा फैलनी चाहिए, स्कूल ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, अस्पताल ज्यादा से ज्यादा होने चाहिये; लेकिन टैक्स नहीं होना चाहिये, और दूसरी तरह से, टैक्स का ही सवाल नहीं, कर्जे के ऊपर भी विरोध किया जाता है।

अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि वित्त मंत्री को, अपने आप लिक्वीडेट हो गये, इस प्रकार की घोषणा कर देनी चाहिये। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो आप केपिटल एक्सपेन्डिचर करते हैं; जैसे भाखरा बांध हम जानते हैं कि करोड़ों रुपयों का अन्न पैदा करता है और साथ ही साथ इरिगेशन और दूसरे तरीकों से धन बढ़ाता है, शक्ति बढ़ाता है, यह मुख्य चीज है। यदि इसको इन्वेस्टमेंट समझ कर नहीं चलें तो मैं नहीं समझता,

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
किसको इन्वेस्टमेंट समझ कर चलेंगे। एक मामूली किसान भी यह समझता है कि वह एक कूआं खोदता है तो उसका असर उसकी उपज पर पड़ने वाला है; तो भाखरा का असर कैसे नहीं होगा........

श्री मानसिंह महार (आमेर) : कूआं खोद कर हजार की इनकम हो तो १ लाख का कर्जा करना पड़े, ऐसा बेवकूफ कोई किसान नहीं होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं, एक कूआं खोदने के लिये जितना कर्जा दे रहे हैं उससे दस गुना कर्जा भी देना चाहे तो किसान लेंगे, लेकिन आज फंड्स की कमी है। जिसके पास जमीन है और कूआ खोदने से उसको पानी मिल जाय तो आज २० मन पैदा होता है तो उसके बजाय २ फसलें करके अधिक उपजाने की कोशिश करेगा और उससे कूए की कीमत चुका देगा, इसको किसान समझता है और चारों तरफ मांग करता है कि कूओं के लिये उनको कर्जा ज्यादा मिले।

श्री मानसिंह महार : यह कोई रीजनिंग नहीं है। मैंने कहा, उसका जवाब आप दे दीजिये। कोई किसान ऐसा नहीं होगा कि यदि हजार रुपया महीना उसकी आमदनी होगी तो १ लाख रुपया वह खर्च करे। मैंने कहा था कि आपका इन्वेस्टमेंट गैर वाजिब तरीके से हो रहा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके लिये विचार करने की बात हो सकती है। माननीय सदस्यों से मैंने कई बार कहा है, मैं समझता हूं माननीय सदस्यों ने बजट देखा होगा, जो तनख्वाह चुकाने के लिये या रेवेन्यू एक्सपेन्डिचर जिसको कहे, प्योरली रेवेन्यू एक्सपेन्डिचर है उसके लिये यदि कर्जा लेकर चुकाना पड़े तो चिन्ता की बात हो सकती है। लेकिन आज यदि डेवलपमेंट के लिये, केपिटल एसेट्स बढ़ाने के लिये या अचानक इस तरह की परिस्थिति पैदा हो जाती है जिनको मीट करने के लिये हमें कुछ न कुछ करना पड़ता है; जैसे अकाल हो गया या और कोई चीज हो गई हो तो सोशियल जस्टिस डिमान्ड करती है इस तरह की परिस्थिति को मीट करने के लिये कुछ न करें तो उचित नहीं रहता। जो आंकड़े दिये गये हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कर्जा है........

श्री संपतलाल बोहरा (मावली) : आपने कहा कि हम राजस्व खर्च पूंजी से करें तो चिन्ता की बात है। आप पिछले १० साल के आंकड़े देखिये, हर वर्ष टैक्स लगाने के बाद भी राजस्व में घाटा हुआ है और यह १७ करोड़ का सन् ५७ से ६४ तक हुआ। रुपये उधार लेकर राजस्व पर खर्च किये हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस साल के बजट पर माननीय सदस्य ने निगाह डाली होगी तो देखा होगा कि १ करोड़ और कुछ लाख का रेवेन्यू साइड में घाटा है और उसको मीट किस तरह किया जायगा वह भी वित्त मंत्रीजी ने रखा है। कर्जा लेकर मीट करेंगे, यह बजट में नहीं कहा गया है। पिछले बजट में भी किसी साल में ऐसा नहीं हुआ है।

दूसरे एक माननीय सदस्य ने कहा कि फाइनेन्स कमीशन के जरिये घन-राशि मिली है। इस विवाद में पड़ने के बजाय मैं अपनी बात रख देना चाहता हूं। फाइनेन्स कमीशन की वजह से हमारे प्लान पर असर होना

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

चाहिये था। मैं अर्ज करूं कि फाइनेन्स कमीशन सारी बातों पर विचार करने के बाद जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है उसको फाइनेन्स करने के लिये अपनी रिकमन्डेशन्स भेजता है। अगली योजना में हमारे रिसोर्सेज को देख कर प्लान में रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। जिस प्रकार की बात आप कहते हैं उस प्रकार की बात करके फाइनेन्स कमीशन नहीं बजता और इसके अलावा ड्यूरिंग प्लान पीरियड यदि रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर डी. ए. या एमर्जेन्सी की वजह से बढ़ता है तो फाइनेन्स कमीशन को रिकमन्डेशन में नहीं होता है। अनफोरसीन परिस्थिति खड़ी होती है तो कोई न कोई ऐसी एजेन्सी बनानी चाहिये जिसके जरिये इस प्रकार के प्रश्न को उसके सामने रखा जा सके और प्लान पीरियड के दौरान में भी फाइनेन्स कमीशन रिकमन्डेशन कर चुका है उसके अलावा स्टेट्स को मदद मिल सके फाइनेन्स कमीशन ने इस बात को अपनी रिकमन्डेशन में कहा है।

अभी जब गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के फाइनेन्स मिनिस्टर ने स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया था तब हमने उनसे कहा कि जो डीयरनेस अलाउन्स के और दूसरे सवाल खड़े होते हैं, उसके लिये गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को चाहिये कि वह स्टेट्स को फाइनेन्स करे, एडीशनल असिस्टेन्स के रूप में हमको और दूसरी स्टेट्स को भी दें। आगे के लिये कमीशन के रिकमन्ड करने के अलावा जो हमारे रिसोर्सेज और दूसरी चीजों के लिये एडीशनल फंड का सवाल है, वे सिद्धान्त रूप से मान कर चलते हैं। यह आशा की जा सकती है कि फाइनेन्स कमीशन यह बात मान कर चलेगा, अलग अलग स्टेट्स के लिये निर्धारित करेगा, तो उसके साथ रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए निश्चय करेगा कि कितने स्टेट के रिसोर्सेज हैं और कितनी पूर्ति करनी है। तीसरी योजना में हमने देखा कि राजस्थान को जो सेन्ट्रल असिस्टेन्स मिली है और जिस वक्त प्लान बना था उस वक्त २३६ करोड़ में से १५६ करोड़ प्लान असिस्टेन्स की बात रखी थी लेकिन चाइनीज एग्रेशन के बाद ओवर ऑल फिगर्स कम किये तब भी तीसरी योजना में १५६ करोड़ के बजाय १९४ करोड़ रुपये सेन्ट्रल असिस्टेन्स के तौर पर मिले क्योंकि जो रिसोर्सेज हम सोचते थे उतने रिसोर्सेज रेज नहीं हो सके, इसलिए इतनी असिस्टेन्स मिली।

यह जो चौथी योजना का साल शुरू हो रहा है, अब तक प्लानिंग कमीशन के जरिये चौथी व पांचवीं योजना का प्रारूप देश भर के लिए तैयार नहीं हुआ है। वे तैयार कर रहे हैं। एक साल का प्लान चल सके इस तरह की तजवीज चल रही है; एमर्जेन्सी प्लान जैसा होगा, जो विशेष हालत में इस वर्ष में बनाया गया, उसको देखने से ज्ञात होगा और यह सही है कि पिछले वर्ष के मुकाबले में यह प्लान छोटा होगा। पिछले वर्ष ४६.६ करोड़ का हमारा ओरिजिनल प्लान था जो सदन के सामने रखा गया था, उससे यह कम होगा। एडवान्स एक्शन और एक्सेस सेन्ट्रल असिस्टेन्स के फिगर्स के अलावा डेवलपमेंट के पैसे के हिसाब से देखा जाय तो यह ३६.६६ करोड़ का प्लान है। इसके अलावा साढ़े पांच करोड़ रुपये राजस्थान केनाल के लिए सेन्ट्रल बजट में प्रोवाइड किये हैं। इसके अलावा कमिटेड एक्सपेन्डिचर पार्ट ऑफ दी नोन

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
प्लान एक्सपेन्डिचर बन गया है जो ८ करोड़ से ऊपर है। टैक्सों के साथ बढ़ा जाय तो हमारी एक्टिविटीज फाल नहीं होगी। यह बात सही है कि प्लान डेवलपमेंट के हिसाब से लिया जाय तो उसका पैसा जो सेन्ट्रल असिस्टेन्स से बनता है, पहले के मुकाबले काफी कम है। एमर्जेन्सी की वजह से जो हालत पैदा हुई है उसके कारण फर्क पड़ा है।

(४ म. प.)

माननीय अध्यक्षजी, जो इस १३ करोड़ के घाटे के बारे में माननीय सदस्यों में से कुछ ने कहा कि पहले से इन फिगर्स के ऊपर सरकार ने पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया है और उसकी वजह से यह इतना बड़ा गैप पड़ गया और वह उनकी जानकारी में नहीं था। मैं समझता हूं, माननीय वित्त मंत्री के भाषण से यह स्पष्ट है और माननीय सदस्यों ने इसके ऊपर निगाह डाली होगी तो इस बात को देखा होगा कि बजट एस्टीमेट की वजह से यह सारा अन्तर पड़ गया है, यह बात नहीं है। इन फिगर्स में खास तौर से वह हैं जो फेमिन की वजह से जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडीचर होगा और इसलिए ही शोर्ट फाल होगा। दूसरे इसके अन्दर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वजह से जो·······

महारावल श्री लक्षमणसिंह (आसपुर): मैं सहमत नहीं हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी से········

(विद्युत् प्रकाश अदृश्य)

लो बिजली गई। अपनी योग्यता देख लीजिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): यह आपकी वजह से हुई है।

(पुनः विद्युत प्रकाश)

महारावल श्री लक्षमणसिंह: मेरा निवेदन है कि आप प्राइस इन्डेक्स देखिये, प्राइस इन्डेक्स किस स्थिति पर जा रहा है। अगर आप प्राइस इन्डेक्स पर ध्यान नहीं देते हैं और प्राइस इन्डेक्स को को-रिलेटेड डेवलपमेंटल एक्टीविटीज से नहीं करते हैं तो आपका बजटिंग ठीक नहीं रह सकता है। आपका बजटिंग ठीक नहीं रहा है। आप चौथी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में विचार करते हैं तो प्राइस के सम्बन्ध में भी विचार करें, नहीं तो वही की वही डी. ए. अलाउन्स की करोड़ों रुपयों की समस्या आयेगी और आपकी डेवलपमेंटल एक्टीविटीज जो होनी चाहिये·······

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: उस पर अभी आऊंगा।

महारावल श्री लक्षमणसिंह: वह नहीं होगी। अब आप अपने अचीवमेंट्स का सुन्दर चित्रण करें, आपका अधिकार है और आपके अचीवमेंट्स हैं। मैं नहीं कहता कि अचीवमेंट्स नहीं हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आपके अचीवमेंट्स हैं, लेकिन उनमें भी मेरे खयाल में कमी है और वे अचीवमेंट्स आप एफीशियेन्सी के साथ में कर सकते हैं।

दूसरे बार बार कहा जाता है (अध्यक्ष महोदय से) मैं आधा सैकण्ड लूंगा। बीस वर्ष, पच्चीस वर्ष पहले यह था, वह था, पिछड़े हुये थे, सब कुछ था—लेकिन वर्ल्ड फोर्सेज इन प्लान—आप वर्ल्ड फोर्सेज को

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
रोप नहीं कर सकते। आज वर्ल्ड फोर्सेज अफ्रीका में क्या है ? लोग कच्चा मांस खाते हैं और चमड़े के वस्त्र पहिनते हैं।

वह स्थिति कभी इंग्लैंड की भी थी। आप बीस-पच्चीस वर्ष पीछे से कम्पेयर करके यह कहें कि आपके एचीवमेंट्स हैं—वह मैं नहीं कहता कि अचीवमेंट्स नहीं हैं। आपके एचीवमेंट्स हैं लेकिन आज वे पर्फेक्ट नहीं हैं और उनमें पर्फेक्शन लाने की गुंजाइश है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं इतना निवेदन कर दूं कि केवल यह समझ कर चलना बहुत बड़ी भ्रान्ति होगी कि वर्ल्ड फोर्सेज की वजह से यह सारा परिवर्तन हो गया। वर्ल्ड में साइन्सेज और टेकनोलोजी का अच्छा काम कई वर्ष पहले हो गया है। लेकिन उस वक्त की जो सरकारें थी वे इस दृष्टिकोण को नहीं रखती थी इसलिए पिछड़े रहे। लेकिन देश की आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार ने आकर सारे दृष्टिकोण को बदला और बदलने की वजह से वह परिवर्तन आया है। यह भी देखना होगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कुछ हद तक आपका कहना ठीक है, लेकिन अक्षरशः ठीक नहीं है। आप कहें कि वर्ल्ड फोर्सेज कुछ नहीं और सब क्रेडिट आप अपने ऊपर ले लें-यह वर्ल्ड फोर्सेज को डिनाई करके वास्तविकता से दूर जाना है। उससे मैं सहमत आज भी नहीं हूं और कभी नहीं हो सकता (हिअर-हिअर) आप अपने एचीवमेंट्स का सुन्दर चित्रण करें। आपका अधिकार है। मैं ना नहीं कहता, लेकिन मैं सहमत नहीं हो सकता (हिअर-हिअर) वर्ल्ड फोर्सेज एक ऐसी चीज है कि जिसका कन्ट्रोलिंग इफेक्ट आपके ऊपर ही नहीं, आपके सक्सेसर और प्रिडिसेसर के ऊपर भी रहेगा और रहेगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : महारावल साहब, आप तो यह कहोगे ही।

कई माननीय सदस्य : बैठ जाओ ! बैठ जाओ !!

(शोर-व्यवधान)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय अध्यक्ष जी........

(शोर-व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : बैठ जाओ ! नेता को बोलने दो।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं विरोधी दल के माननीय नेता का बहुत आदर करता हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं भी आदर करता हूं, लेकिन यह मतमतान्तर की बात है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : और मैं उनकी राय की कद्र करते हुए इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने कहा-शत प्रतिशत यह कारण नहीं है, वर्ल्ड फोर्सेज भी कारण है। तो कितने प्रतिशत कहा जाय—यह मतभेद का विषय है....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : पचास प्रतिशत। आप समझते हैं कि महात्मा गांधी के कारण भारतवर्ष स्वतंत्र हो गया ! उसमें पचास प्रतिशत वर्ल्ड फोर्सेज का कारण था।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अमरीका की ओर ध्यान दीजिये, सुखाड़िया [illegible]

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं निवेदन करूं कि पर्सेन्टेज की बहस में मैं नहीं पड़ना चाहता हूं। साथ साथ में माननीय सदस्य ने कहा कि मेरी राय से इत्तिफाक नहीं करते हैं। वह मानी हुई बात है और इसीलिए आमने-सामने बैठे हुए हैं। नहीं तो आमने-सामने बैठने की जरूरत नहीं पड़ती यदि दोनों का दृष्टि कोण एक होता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : कम्युनिस्टों की तरह नजदीक आ जाते।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैंने निवेदन किया कि १३ करोड़ का डेफिसिट हुआ–उसके फिगर्स जो आज दिये गये हैं उन फिगर्स से बहुत स्पष्ट है–फेमिन, लैण्ड की बेटरमेंट लेवी और उसकी सेल गांधी सागर डेम, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और राजस्थान कैनाल का एक्स्ट्रा इन्ट्रेस्ट देना पड़ा, वह पुलिस की एक्स्ट्रा बटालियन और पेफिकेशन टीचर्स का इस साल अच्छा काम किया गया–इनकी वजह से यह फर्क पड़ा....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : हर वर्ष, जब भी बजट आया, या पंचवर्षीय योजना निकाली गई उसमें एक बात निश्चित रूप से एड करते हैं और वह है बेटरमेंट लेवी की, लेकिन वह किसी साल, किसी प्लान में वसूल नहीं होती है। उसका आधार मान कर बजट बनाते है लेकिन वह वसूल नहीं होता है तो प्लान एक्सपेन्डीचर को नॉनप्लान एक्सपेन्डीचर में खर्च करने के बाद उसको आप जस्टीफाई करते हैं। तो दोनों जस्टीफिकेशन्स साथ साथ नहीं चल सकते। मैं यह मान कर चलता हूं कि बेटरमेंट लेवी का प्रावधान रखा वह जानते हुए रखा, लेकिन वह वसूल नहीं हो सका।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : इस साल हुई है।

श्री भैरोंसिंह : नहीं हुई।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आठ लाख का हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : आपको पता नहीं है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : पता है वसूली हुई है और वित्त मंत्री ने अपने भाषण में आठ लाख की वसूली बताई।

श्री भैरोंसिंह : प्लान में लिखा हो तो, प्लान में लिखा है–नहीं हुई। वित्त मंत्री के भाषण में लिखा हुआ तो उसमे भी लिखा हुआ है–नहीं हुई। जिसके कारण रिसोसेज बढ़े हों........

श्री मोहनलाल सुखाडिया : Short fall

श्री भैरोंसिंह : चौथी पंचवर्षीय योजना की जो चार वर्ष की रूप रेखा पेश की गई है उसमें भी लिखा है कि नहीं हुई है। फिर कहां वसूल हो गई है–यह पता नहीं है। इसलिए बेटरमेंट लेवी के वसूल नहीं होने के कारण प्लान एक्सपेंडीचर को नॉन-प्लान एक्सपेंडीचर में मीट करने की व्यवस्था की जाती है–यह अनुचित है।

श्री मोहन लाल सुखाडिया : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की इस बात से मालूम होता है कि बेटरमेंट लेवी कम वसूल हुई है, इसलिए उसमें तेजी लानी चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : यह नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसका वित्त मंत्री जी ध्यान रखें।

श्री भैरोंसिंह : बैटरमेंट लेवी वसूल नहीं होगी १९६७ तक।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : १९६७ के बाद वसूल करने की कोशिश करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन कर रहा हूं..

श्री महारावल लक्ष्मणसिंह : यह अर्थ का अनर्थ है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन कर रहा हूं कि बैटरमेंट लेवी और लैण्ड को बैटरमेंट लेवी तो और कम हुई है।

श्री भैरोंसिंह : वह होगी भी नहीं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जैसा पहले कहा था कंपोजल रिसीट का पोस्टपोनमेंट हुआ है, हमेशा के लिए वसूल नहीं होने की बात नहीं हुई है। पिछले साल वसूल नहीं हुई हो–ऐसी बात नहीं है। वसूल हुई है काफी। इस साल उसपे रखा गया है, उसको समझ कर रखा गया है और मैं आशा करता हूं इसकी पूर्ति करने के अन्दर जनसंघ के माननीय सदस्य सरकार से सहयोग करेंगे....

कुछ माननीय सदस्य (जनसंघ) : नहीं, नहीं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी से आवाज आने लगी।

श्री भैरोंसिंह : आपने बताया है कि बिना मुआवजा को जमीन दी गई है, तो हम चाहते हैं कि किसानों को बिना मुआवजे के पानी भी दे दीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान के अन्दर विरोधी पक्ष के माननीय नेता ने इस बात का भी सवाल उठाया कि प्राइसेज बढ़ती जाती हैं–इसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। मैं आप से निवेदन करूं और शायद माननीय सदस्य भी इस बात को मानेंगे कि राजस्थान के अन्दर इस साल इतना अकाल होते हुए भी, इतनी मुश्किल हालत होते हुए भी जो फूड ग्रेन की प्राइसेज हैं, जिसके कम्पोरेटिव फीगर्स में दूसरी स्टेट्स के साथ नहीं देना चाहता, लेकिन पंजाब को छोड़ कर आम तौर से हिन्दुस्तान में राजस्थान के अन्दर फूड ग्रेन्स की प्राइसेज कम रही है और राजस्थान के अन्दर अवेलेबिलिटी के लिहाज से जो लोगों के अन्दर इस सम्बन्ध में आम तौर से संतोष है उससे, मैं समझता हूं, सदन के माननीय सदस्यों को भी संतोष होगा....

महारावल श्री लक्ष्मसिंह : पूर्ण संतोष नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कि इस प्रकार की परिस्थिति रही।

माननीय अध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने हमारे शियूड्ल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के भाइयों का आह्वान किया था बहुत जोर के साथ और पंजाब का उदाहरण देकर उनको प्रेरित करना चाहा था जैसे वे उनके लिए बहुत हमदर्दी रखते हैं। मुझे यह तो खुशी है कि जब से हमारा विधान आया और

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
उस विधान ने हरिजनों को और आदिवासियों को वोट-अधिकार दिया-तब से सबके दिल के अन्दर हमदर्दी पैदा हुई

श्री भैरों सिंह : यह आपका मुगालता होगा, आपका विधान तब आया

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता।

श्री भैरों सिंह : उससे पहले से मैं जिस संस्था में सदस्य रहा उस संस्था ने इस परम्परागत छूआछूत और मतभेद को व्यवहार से समाप्त कर दिया था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : क्या कहा ?

श्री भैरों सिंह : आपने कहा कि विधान के द्वारा समाप्त किया। लेकिन मैं जिस संस्था का सदस्य रह कर आया हूँ उसने अपने निर्माण-काल से, जो आपका विधान बना उसके पहले की यह संस्था बनी हुई है उसने अपने निर्माण-काल से ही छूआछूत को व्यवहार से समाप्त कर दिया था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप जिस संस्था के सदस्य हैं; ठीक है, आप कहते हैं लेकिन उसका निर्माण किसने किया है यह तो वे लोग अच्छी तरह से जानते हैं और हरिजनों का बच्चा बच्चा जानता है कि अगर किसी ने अपने जीवन पर खेल कर काम किया है तो महात्मा गांधी ने किया।

श्री भैरोंसिंह: यही तो लड़ाई है कि आप महात्मा गांधी के सिद्धान्तों पर चलिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह तो आपकी राजनैतिक बात है। लेकिन मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज राजस्थान में जहां तक हम लोगों का प्रश्न है। आजादी से पहले और आजादी के बाद उसी नीति को मान कर चलते हैं कि हम अपने साधनों के अनुसार इन हरिजनों के लिये जितना ज्यादा हो सकता है करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भूमि वितरण के नियमों में हमने विशेष तौर से यह किया है कि भूमि वितरण के मौके पर हरिजन या आदिवासियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

(विराम)

मैं यह भी निवेदन करूं कि इकोनोमी के स्टेप्स हम उठा रहे हैं और उन स्टेप्स में हमें कुछ-सरप्लस स्टाफ करना पड़ेगा। हमने इस संबंध में भी, जो सरप्लस स्टाफ इकोनोमिक मेजर के लिये करना पड़ेगा उसके लिये मेरे पास कुछ माननीय सदस्य इस तरफ के बैठने वाले आये और कहा कि इसमें आपको कुछ शिड्यूल्डट्राईब्स के लोगों के लिये करना चाहिये और जो टेम्परेरी स्टाफ है आपके इस मेजर से सरप्लस हो जावेगा। हमने एक हिदायत जारी की है जो कोटा हरिजनों का परसेन्टेज के द्वारा बनता है, वहां तक हरिजनों आदि को रखाजावे और उनको सरप्लस नहीं किया जावे, जब तक उनका कोटा पूरा नहीं होता हो। यह कार्यवाही की गई है हम उनके संबंध मे कदम नहीं उठाते हैं, ऐसी बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। आप उसको अवोइड कर रहे है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं उसी पर आ रहा हूं।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य हैं, उन्होंने यह कहा कि हमने प्लान में रिडक्शन

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

किया और इससे शोर्ट फाल होगा । ठीक है कुछ शोर्ट फाल होगा; यह सही है कि शोर्ट-फाल होगा । २०८ करोड़ का प्लान है उसमें से आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर पर और उसके बाद इरिगेशन और पॉवर पर जिसके एक्स-पेन्डीचर को हम कम नहीं कर सकते, जिसको हम रोक नहीं सकते, उसको तो हमे पूरा दूसरों में कमी करके भी करना पड़ेगा और उसके बाद में एजुकेशन वगैरह में किया है । इसलिये यह कहना कि उसका बेनिफिट नोन हरिजनों को मिलता है और हरिजनों को न मिलता है, यह बात नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : आप ने अलग अलग क्यों बनाये है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो हमारे सामने मुश्किल थी, मजबूरी से हमें कम करना पड़ा है । उनके एक्सपेंडीचर को कम करने के लिये यह सोचा गया हो, ऐसी बात नहीं है । हम यह चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो कर सकें करने की बात करें ।

माननीय अध्यक्ष, इस सदन में टैक्स के संबंध में कई बातें कही और कई भाईयों ने इस बात को बहुत जोर से उठाया, इस पक्ष ने अपील की कि किसानों पर टैक्स लगा रहे हैं । और उनसे उन पर बड़ा असर पड़ रहा है । जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया कि टैक्स का सवाल क्यों खड़ा होता है और क्यों लगाने चाहिये । मैं आपको निवेदन करूं कि पांच रुपयों का मामूली टैक्स एक एकड़ भूमि पर लगाया गया है और वह भी उस पर नहीं अगर वह उस भूमि में चावल, बाजरा या गेहूं आदि की खेती करना चाहता हो तो उसको इस बात की, गुंजायश है कि अगर रबी में वहां गेहूं और जो बोता है तो उसके लिये कोई टैक्स नहीं है ,ये तो एक प्रकार से जो सीरियल्स हैं, यदि वह उनको बोता है तो उसको कोई ना नहीं है । लेकिन अगर वह अपनी इनकम ज्यादा करने के लिये कोई दूसरी चीज वहां पर लगाता है तो वह टैक्स पांच रुपयों का लगाया गया है वह ज्यादा नहीं होता । फिर भी अध्यक्ष महोदय, यह इसलिये करना पड़ा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि कुछ बड़ी योजनाएं हमने पूरी कीं, उस पर मेन्टीनेन्स चार्ज भी चाहिए, वह भी पूरा नहीं होता है । इसके लिए प्लानिंग कमीशन ने और कमेटी की यह सिफारिश थी कि जो डाइरेक्ट एडवान्टेज लोगों को होता है उनको इसके लिए पे करना चाहिए और जनरल पब्लि इससे टैक्स होती हो, उसमें इसको रोकना चाहिए । इस लिए यह कदम उठाया गया है कि जो लोग दूसरे तरीके की क्रोप में जाते हैं तो मैं समझता हूं कि उनको यह पांच रुपये का टैक्स भी देना चाहिए ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जहां के लोग पहले ही बहुत ज्यादा टैक्सेज देते हैं वहां तो यह नहीं लगना चाहिए । वहां पर २२) रु० देते हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं भेद-भाव में इस समय पड़ना नहीं चाहता ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यह भेद-भाव की बात नहीं है, बराबर करने की बात है ।

श्री मानसिंह महार : यह कोई मेवाड़ का मामला दिखता है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वहां पर पहले ही ज्यादा टैक्सेज हैं ।

Page No. 103

श्री मानसिंह महार : जयपुर में लगान की दरें बहुत ऊंची हैं, उनको भी कम कर दिया जाय ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं तो इरिगेशन की बात करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि मैं इसको कोई प्रश्न. प्रखर नहीं बनाना चाहता । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कुओं पर नहीं है और केवल नहरों पर है और सीरियल पर नहीं है नॉन सीरियल पर है । इसलिये यह कहना कि यह केश क्रोप पर नहीं जा कर सीरियल पर जावेगा उचित नहीं है ।

इसके बाद में घी के बारे में कहा गया । सब जानते है कि असली घी कह कर वेजीटेबल दे दिया जाता है और भी बहुत सी बातें हैं । इसलिये एक तरह से इस लीकेज को रोकने के लिये कहा गया । इसके बारे में हमारे वित्त मंत्री कहेंगे । इस बारे में मैं और ज्यादा न कह कर मैं यह कहूंगा की जो कुछ भी असलियत है माननीय सदस्यों को उसकी जानकारी वे अपनी तरफ से देंगे ।

माननीय अध्यक्ष, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने भाषण में यह रखा कि राजस्थान में एक तरफ पाकिस्तान का आक्रमण हो रहा था और दूसरी तरफ मालखाने के आर्म्स हैं उनको सस्ती कीमतों पर कुछ लोगों को बेचा गया है और उनको बोर्डर पर नहीं दिया गया । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो मालखाने के आर्म्स बेचे गये उनकी तादाद ६८२ है । उसमें से चाइनीज एग्रेशन हुआ उससे पहले ६४६ आर्म्स पहले बिक गये थे । मैं पाकिस्तान और कच्छ के एग्रेशन की बात नहीं कहता । उसके बाद चीन और कच्छ के एग्रेशन के बीच में २० आर्म्स बिक गये । इस तरह से २६ आर्म्स रहे । उनमें से भी कुछ आर्म्स पाकिस्तान की लड़ाई हुई उसके बीच में २५ आर्म्स बिक गये . पाकिस्तान के एग्रेशन के बाद में एक हथियार बिका । उसके बाद हजारों हथियार दूसरों को बेच दिये गये । यह परिस्थिति उनके सामने थी ।

श्री भैरोंसिंह : आप उनकी कीमतों के बारे में बता दीजिये ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : माननीय अध्यक्ष, जो कीमतों का प्रश्न है उसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का सर्कुलर था, उसके मुताबिक हर डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी बनाई गई इसके लिये । कलेक्टर और एस. पी. मिल कर इन हथियारों को दिया करते हैं । उन कमेटीज के जरिये दिये गये और यह सन् १९५८ में सर्क्यूलर निकला उसके मुताबिक दिये गये । इसलिये यह कहा जाता है कि पाकिस्तान के एग्रेशन के समय बेच दिये गये, यह सही नहीं है; यह तो बहुत पहले बिक चुके ।

श्री भैरोंसिंह : मैं अर्ज करूं अध्यक्ष महोदय, कि मैं खुद पाकिस्तान और राजस्थान के बोर्डर पर, करणपुर से लेकर वहां पर जितने गांव हैं, उनमें गया हूं, वहां कोई गांव ऐसा नहीं है जहां से गंगानगर के अधिकारियों ने हथियार नहीं छीने हों । प्रश्न यह है कि हथियार किस समय छीने, यह आपके लिये विवाद का विषय है, मेरे लिये नहीं । मेरा कहना यह है कि सदन में आज से नहीं चाईनीज एग्रेशन के पहले से मांग की जा रही है कि बोर्डर पर हथियार बांटे जांय

(श्री भैंरोंसिंह)

५९ में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के समय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि हमारे पास हथियार नहीं हैं, इसलिये हम हथियार नहीं बांट रहे हैं। इसके बाद सरहद के लोगों से उनके हथियार जब्त करके, बड़े-बड़े अधिकारी उन हथियारों की लूट मचा लें और मुख्य मंत्री यह कह कर इसको टाल जायं कि कमेटी ने हथियार बेचे; मुख्य मंत्री जी यह आपको शोभा नहीं देता। कमेटी के मेम्बर्स ने ही तो लूट मचाई है। दुगुनी कीमतों पर, तिगुनी कीमतों पर उन हथियारों को लोग लेने के लिये तैयार है। ३२, ३२ बोर ६२ बोर की गन्स और पिस्टल्स जिस कीमत में बेचे है उनसे पांच गुनी कीमत में देने को तैयार हूं। आज के दिन मेरा यह कहना नहीं है कि इसमें आपका पर्सनल इन्ट्रेस्ट है। सरकारी अधिकारियों ने इस कमेटी के नाम पर लूट मचाई है। उनको आप प्रोटेक्ट मत करिये। यह हथियारों का मामला है। सब अधिकारियों ने मिल कर लूट की है। आई. जी. ने, डी. आई. जी. ने, एस. पीज. ने नाम की कीमत पर उन हथियारों को खरीदा है। मिनिस्टर कुंभारामजी ने, ३७ नहीं ९ एम. एम. बन्दूक जब कि ६५ में उसकी कीमत १५००) रु० से कम नहीं थी, १५०) रु० में खरीदी है, उनके पी. ए. ने खरीदी है, उनके ड्राइवर ने खरीदी है। इस तरह के आदमियों को मुख्य मंत्री प्रोटेक्ट करें, यह मुख्य मंत्री के लिये शोभा की बात नहीं है।

श्री मानसिंह महार : ऐसे डाकुओं को कैसे बन्दूकें दे दी यह भी कहें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : तो माननीय अध्यक्षजी, आपके सामने सवाल उठाये, उसमें दो बातें आती हैं; एक तो कम कीमत पर देने की और दूसरी पाकिस्तान के एग्रेशन के वक्त में, जिनके हथियार थे उनके सिवाय दूसरों को दे देने की।

यह बात तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान के एग्रेशन के समय दूसरों को नहीं सैल किये जा रहे थे। दूसरी बात है उन हथियारों को कम कीमत पर दिया गया और घोटाले की बात कही, उसके लिये मैंने कहा कि अलग अलग जगह कमेटियां गवर्नमेंट आफ इन्डिया की इन्स्ट्रक्शन्स के माफिक बनाई गई, उन कमेटियों ने इन बातों को ध्यान में रख कर बेचा है या नहीं, आज इस परिणाम पर पहुंचना उचित बात नहीं होगी।........

श्री कृष्णकुमार गोयल : तो फिर जांच करा लीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : जांच क्या ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : इन अधिकारियों ने कैसे खरीद लिये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एक आदमी के बजाय कमेटी बनाकर ही ऐसे मामलों को सौंपा जाता है।

श्री भैरोंसिंह : यह क्रिमिनल ब्रीच आफ ट्रस्ट किया है कमेटी ने। ऐसे हथियारों को १५-१५ रुपयों में बेच दिया जाय और उसके लिये भी सरकार जांच कराने को तैयार नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय बोर्डर के मामले में........

Page No. 105

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हथियार ...ने गये या नहीं छीने गये; छीने गये तो ...ों छीने गये, स्पष्टीकरण तो होना चाहिये ?

श्री भैरोंसिंह : यह बहुत ही महत्वपूर्ण ...द्दा है, माननीय अध्यक्ष ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : तो माननीय ...ध्यक्षजी, दूसरा सवाल यह उठाया गया कि ...थियार छीन लिये गये और उनको न देकर ...सरों को दे दिये गये । मेरे पास इस समय ...टेल्स नहीं है कि पाकिस्तान के एग्रेशन के ...मय हथियार छीन लिये गये या क्या हुआ, ...ानकारी करके बतायें कि किस के लिये....

श्री कृष्णकुमार गोयल : बीस-बीस ...पयों में हथियार मिनिस्टरों और अधिकारियों ...े लिये इतने सीरियस चार्ज को मुख्य मंत्री जी केवल इस बात पर टाल दें कि इन हथियारों को बेचने के लिये कमेटियां बनाई ...ई । हम कह रहे हैं कि वे कमेटियां बोगस ...ं । कोटा में जब हमारे सामने इस प्रकार का ...क सवाल आया तो आर्म को सरेंडर करवाया । ...आम लोगों को अगर मालूम हो जाय कि ...आर्म्स बेचने की योजना है तो आम लोग वहां खरीदने के लिये पहुंच जायं, पर किसी को मालूम तक नहीं होने दिया । आपके गवर्नमेण्ट के अधिकारी आकर कहते हैं, मुझे यह आर्म खरीदना है; तो इस बोगस कमेटी ने फर्जी कीमत तय करके इन अधिकारियों ने लूट कर ली । यह लाखों का मामला है । कुछ हजार में ही आर्म्स को बेच दिया गया है इसको आप छिपाना चाहते हैं यह आपके लिये शोभनीय नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : एक चीज और मुख्य मंत्री जी के नोटिस में ले आऊं । वे सदन को इस बारे में बताने की चेष्टा करें ।

६० और ६२ में सरकार ने टेन्डर्स इन्वाइट किये थे । एक फर्म ने जो टेन्डर दिये हैं उनमें जिन आर्म्स की कीमत छः-छः सौ, सात-सात सौ, आठ-आठ सौ और नौ-नौ सौ रुपयों तक के टेन्डर दिये हैं उन्हीं आर्म्स को तीस-तीस रुपयों में बेचा गया है । किस कमेटी ने किस प्रकार का बोगस काम किया है, यह तो आप इन टेन्डर्स को मंगा कर देख लेते । डेढ़-डेढ़ हजार के लोगों के हथियार आपने छीन लिए और तीस-तीस रुपये में बेच दिए । जागीरदारों के लिए आदेश निकाल दिया आपने कि दो से अधिक हथियार न रखें, उनसे हथियार आपने छीन लिए; उनको किसी प्रकार का मुआवजा उन शस्त्रों का नहीं दिया और राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने १५-१५ रुपयों में उन पर कब्जा कर लिया, इस चीज को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसका हम विरोध करेंगे ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : टेन्डर में कितना दिया, इसकी मैं जानकारी करा लूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, जानकारी का सवाल नहीं है, दो महीने पूर्व मैंने गवर्नर साहब, मुख्य सचिव और मुख्य मंत्री जी को इस सबकी डिटेल्स देते हुए चिट्ठियां दी हैं, चिट्ठियों का जवाब देना तो दूर रहा पर आज उन तथ्यों के बारे में मुख्य मन्त्री जो इस तरह की बात कहें कि जानकारी नहीं है तो यह मुख्य मन्त्री पद के लिए शोभा की बात नहीं है । ऐसा लगता है कि मुख्य मन्त्री जी कुछ अधिकारियों को शील्ड करना चाहते हैं जिन्होंने जनता के कीमती हथियारों को छीन कर मनमानी लूट की है.....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं कह दूं कि मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता....

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि जो जानकारी माननीय सदस्य ने चाही है वह इनके पास नहीं है, इसलिए यह प्रश्न अभी नहीं उठा कर फिर किसी समय उठा सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : जानकारी नहीं होने का प्रश्न नहीं, अध्यक्ष महोदय मैं, दो महीनों से चिट्ठियां लिख रहा हूं, प्रेस में ये सब फैक्ट्स दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : इस पर इसी समय चर्चा न कर सारी जानकारी करके आ जायं।

श्री भैरोंसिंह : फिर स्टेटमेंट देंगे ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय जनसंघ के नेता ने सरकार पर बड़ा गम्भीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इस सम्बन्ध में उन्होंने चिट्ठियां भी लिखी हैं, चीफ सेक्रेट्री तक को चिटिठ्यां लिखी हैं, चिट्ठियां लिखने के बावजूद उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, चिट्ठियां लिखने के बावजूद मुख्य मन्त्रीजी ने प्रकाश नहीं डाला। यदि कोई सिक्योरिटी का मामला हो तो मै जोर नहीं दूंगा, पर यदि कोई अन्य चीज है, राजनैतिक कारण हैं या सरकारी कर्मचारियों को शील्ड करने के लिए यदि मुख्य मन्त्री ऐसा करते हैं तो हम इसका विरोध करेंगे, अवश्य करेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया कि न कोई राजनैतिक कारण है और न कोई और कारण है। गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया की कन्स्ट्रक्शन्स के माफिक कमेटीज के जरिये देने की व्यवस्था की। गवर्नमेंट का कहना था कि फेअर प्राइस पर दिये जायं........

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ६ एम. एम. और उसकी कीमत १५० रुपया, यह फेअर प्राइज है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : फेअर प्राइज पर न देकर........

श्री भैरोंसिंह : गंगानगर के कलेक्टर श्री कोचर है, उन्होंने ३२ बोर का रिवाल्वर ४० रुपये में खरीदा। मैं एक हजार रुपया उसी रिवाल्वर का देने को तैयार हूं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : वही देने वाले और वही लेने वाले !!

(शोर-गुल)

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कर लें।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्यों नहीं सोचना पड़ेगा, यह जनता का मामला है।

(घन्टी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! आर्डर प्लीज।

श्री जोधसिंह चौहान : डाका मत डालो।

श्री कृष्णकुमार गोयल: मुख्य मन्त्री इसको दबाना चाहें यह बर्दाश्त करने लायक नहीं है। मुख्य मन्त्री से आशा की जाती है कि इन्डिपेंडेंटली गम्भीरता से इस प्रश्न पर विचार करें और देखें कि कम कीमत में किनको आर्म्स दिए गए हैं। आप स्वयं देखेंगे कि एक वेपन का २० रुपये कोई वाजिब दाम है ? जो कमेटी बनी हुई है उसमें एस० पी०, कलेक्टर और डीलर भी होता है उन्होंने कीमत तय करके बेच दिये। आप इसको उचित समझते हैं ? अगर उचित

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
नहीं समझते हैं प्राइमा फेसी तो आप को क्या आपत्ति है घोषणा करने में कि आप इस सम्बन्ध में जांच कराने को तैयार हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया कि कुछ बातें जो माननीय सदस्य ने कही हैं उनके बारे में मैंने कहा कि किसी कमेटी के मेम्बर या दूसरे पर उन्होंने जो घोटाला किया, इस बात को मान कर चलने के लिए आज कोई ऐसी बात नजर नहीं आती। अब सवाल आता है कि फेयर प्राइज़ पर न देकर कम प्राइज़ पर ये वेपन्स दिए गये। मैं अवश्य जानकारी कर लूंगा, उसके बारे में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अगर इसके अन्दर एक्सट्राऑर्डिनरी बात हुई है तो इस बारे में पता लगा लिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : सदन में जवाब देंगे जानकारी करने के बाद में ?

श्री अध्यक्ष : सदन में उत्तर वे देंगे, नहीं तो और किसी तरह चर्चा उठाई जायगी।

श्री भैरोंसिंह : फिर चर्चा का मौका नहीं आयेगा।

श्री मानसिंह महार : तथ्यों के आधार पर है, इसमें दो राय नहीं। अब भी कैसे कहते हैं कि जानकारी दूंगा ?

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : इसमें राजा मानसिंह, भरतपुर का भी नाम है।

श्री मानसिंह महार : होगा, तो क्या हुआ ?

श्री भैरोंसिंह : आप यह कहें कि राजा मानसिंह को सस्ता दिया।

श्री मानसिंह महार : अगर उन्होंने लिया है तो उनसे भी वापिस लिया जाय, यह कोई आर्ग्युमेंट नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : राजा मानसिंह या और किसी ने लिया हो। पब्लिक के आदमी ६–७ हैं, बाकी सब अधिकारी हैं; कलेक्टर, एस० पी०, उनकी बीबियां, उनके बच्चे, उनके पोते उनके रिश्तेदार, एडीशनल कलेक्टर, डी० वाइ० एस० पी०—सबने मिलकर जितनी लूट हो सकती थी वह की और मुख्य मंत्री कहें कि वह जांच कराने को तैयार न हों तो इससे बड़ा प्रमाण अधिकारियों को शील्ड करने का और क्या हो सकता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने कहा है कि इस संबंध में जानकारी करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : दो महीने क्यों नहीं की ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो फैक्ट्स आप डिटेल में दे रहे हैं.......

श्री भैरोंसिंह : वे तो मैंने अपनी चिट्ठी में सब आपको लिखे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो जानकारी मैंने की उस आधार पर मैंने आपको यह जानकारी दे दी और उस जानकारी के बाद भी जब आपने इस संबंध में इन्सिस्ट किया तब मैंने कहा कि आवश्यक जानकारी . .

श्री हरिप्रसाद शर्मा ; आप इसको गंभीर मानते हैं या नहीं ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : तो मुख्य मंत्री कहें कि मुझे जानकारी नहीं है, जानकारी करके सदन के सामने तथ्य रखूंगा।

श्री भैरोंसिंह : कम से कम आप इतना तो कह दीजिए कि अगर मार्केट प्राइस से लोवर प्राइस में 'वेपन्स' को बेचा है तो आप उनके विरुद्ध एक्शन लेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सारी हालत की मैं जांच करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : मैं प्रमाण सहित जब कह रहा हूं.........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सारी जानकारी किए बिना इस समय कमिट नहीं करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन में डिस्कशन के लिए यह बात आएगी या नहीं, आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष : वही तो मैं निवेदन कर रहा था कि सदन में इस तरह की चर्चा उठाने के क तरीके हैं। मुख्य मंत्री ने स्वयं ने कहा है कि जितना पेचीदा मामला आपने बताया है, कई तथ्य मुख्य मंत्री के पास भेजे, चिट्ठी लिखी, उन सब मामलों की जांच करके सदन के सम्मुख वक्तव्य देंगे, यह उनके सोचने की बात है; फिर भी इस पर बहस का सदन में अवसर अवश्य दिया जायगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एक बार जब मैं सदन में उपस्थित नहीं था तो जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अजमेर के एक सम्पादक के बारे में एक प्रश्न यहां पर उठाया था कि श्री केसरीचंद ने वित्त मंत्री के खिलाफ एक किताब निकाली उसकी वजह से उसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। इस बात का सदन में उल्लेख किया गया। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में पुलिस के पास २७ दिसम्बर, १९६५ को एक शिकायत आई थी, श्री पूरन कोठारी की तरफ से, उसमें यह लिखी हुई थी, कि इन्होंने एक प्रदर्शनी लगाई थी और उस मौके पर कई टाईज लेकर आए कि प्रदर्शनी के बाद म्यूज़ियम के अंदर अरेंज किए जायेंगे, लेकिन उन्होंने उन टाईज़ को उठाकर बेच दिया और बेच कर अपने पास रुपया रख लिया। यह शिकायत पुलिस के पास आई। उसके बाद पुलिस ने इन्क्वायरी की और उसके बाद इस संबंध में कार्यवाही की गई और यह शिकायत जैसे मैंने आपसे कहा २७ दिसम्बर को आई जब उस किताब का सवाल नहीं था उसके बाद प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी जनवरी १९६६ में शुरू हुई, एवीडेंस वगैरह ली गई उस पर कार्यवाही हो रही है।

श्री भैरोंसिंह : प्रदर्शनी कब लगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उससे पहले २७ दिसम्बर की शिकायत है यह दुबारा शिकायत की गई। इससे पहले इन्वेस्टीगेशन हो चुका हैं। किताब फरवरी में लिखी शिकायत दिसम्बर में हुई।

श्री भैरोंसिंह : आपने आपके एस. पी का लेटर जो पढ़ कर सुनाया सदन में, वह ११ या १२ फरवरी का है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : केसरीचंद के लेटर का आप रेफरेंस दे रहे हैं, वह जो लेटर भेजा गया वह २१ दिसम्बर का है।

श्री भैरोंसिंह : एस० पी० अजमेर ने जो लेटर लिखा है वह।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : किस दिन लिखा यह सवाल नहीं है। जो लेटर आई. जी. पी. को लिखा गया, वह २६ दिसम्बर का है। उसके बाद यहां से अजमेर को लिखा गया, पर उसके बाद की डेट है। तो जहां तक चिट्ठी का सवाल है उसके साथ का कोई संबंध नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : वित्त मंत्री महोदय के पक्ष में, ऐसी वालकृष्ण के जन्म दिवस पर विशेषांक १८ जून, १६६४ को लिखा था और इसमें मंत्री महोदय ने जो कल बिल पेश किया था कि शराब की एडवर्टाइजमेंट नहीं होनी चाहिए, वे भी हैं। विशेषांक निकला उस समय उसकी मदद की, उसके खिलाफ केस हुआ उस समय उसकी मदद की गई, केस झूठा था, विशेषांक निकलवा दिया। उसके बाद किताब निकली। उसके लिए जब उसने मैटीरियल इकट्ठा करना शुरू किया तब उन्होंने तजवीज़ की कि ज्योंही किताब निकलेगी तो इसको पकड़ लेंगे। वह मामला जो पहले इन्वेस्टीगेट करके दबा दिया गया था उसके लिए जिम्मेदार कौन है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जब यह सवाल उठाया गया और इससे जोड़ा गया क्योंकि किताब ११ फरवरी को निकली और १२ फरवरी को शिकायत की गई, इसका कोई मेल नहीं है. बल्कि केसरीचंद की तरफ से खत आया, उस पर एस० पी० अजमेर को यहां से सी० आई० डी० की तरफ से लेटर लिखकर भेजा गया वह भी १६ जनवरी का है। उसको लेटर रेफर किया गया, जिसके रेफरेन्स से यह बात जाहिर होती है कि फरवरी के बाद के एक्शन का संबंध नहीं जुड़ता है। हो सकता है कि इस जानकारी के अंदर कोई अन्तर हो।

इस सदन में माननीय सदस्यों ने इस बात को भी उठाया कि जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया उस मौके पर राजस्थान की सीमा पर जो कुछ हुआ उस संबंध में एक माननीय सदस्य ने कहा कि राजस्थान के बारे में मैंने शुरू में यह कहा था कि राजस्थान की एक इंच जमीन पर भी पाकिस्तान का कब्जा नहीं है। मैं समझता हूं, मैंने जानने की कोशिश की, पिछली प्रोसिडिंग सारी दिखलायी, उसमें "एक इंच भी राजस्थान की भूमि पर कब्जा नहीं है," यह नहीं कहा है।

श्री भैरोंसिंह : आपने यह कहा है कि पाकिस्तान का राजस्थान के किसी भी भू-भाग पर कब्जा नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : असेम्बली की प्रोसिडिंग्ज हैं उस पर से कह रहा हूं। अब सवाल यह खड़ा होता है, अभी भी माननीय सदस्यों ने कहा, पहले भी माननीय सदस्यों ने कहा, और कुछ माननीय सदस्य सदन के बाहर भी इस बात को कह कर चलते हैं कि पाकिस्तान ने हमारी जमीन पर इतना कब्जा कर लिया, मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, यह बात बिलकुल ही गलत है। वह इसलिये गलत है कि भारत सरकार की ओर से वक्त वक्त पर जवाब दिया गया है वह भी उनकी जानकारी में है, पाकिस्तान ने सीज़ फायर के बाद कुछ आईसोलेटेड जगहों पर जाकर घुसपैठ की। पाकिस्तान के एरिया के बारे में एक प्रोपेगेन्डा चलता है। मैं माननीय सदस्य से

Page No. 110

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
निवेदन करूंगा कि उस प्रोपेगेन्डा में, हम उनके किसी ट्रेप में न आ जायं........

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इसका ओब्जेक्शन लेता हूं। मुख्य मंत्री का मतलब यह है कि हम पाकिस्तान के प्रोपेगेन्डा में आ गये। मैं निवेदन करूंगा। कि या तो इस पर पूरा वाद-विवाद करें, अन्यथा मुख्य मंत्रीजी अपने इन शब्दों को वापिस लें। किसी भी समय इन शब्दों का हमारे खिलाफ प्रचार हो सकता है। जिस पार्टी की एक घोषित नीति हो, जिसकी राष्ट्रीय नीति हो और जो दल उस घोषित नीति को लेकर चलता हो और जिसके द्वारा आज तक कहता रहा हो, उस दल के लिये और सदस्यों के लिये मुख्य मंत्री जी यह कहें कि पाकिस्तान के ट्रेप में आ गये, पाकिस्तान के साथ मिल गये, वह केवल उस चीज को छिपाने के लिये है जो असली रूप में प्रकट नहीं करना चाहते हैं। इसलिये मुख्य मंत्रीजी अपने शब्दों को वापिस लें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने यह नहीं कहा कि पाकिस्तान के साथ मिल गये।

श्री भैरोंसिंह : आपके कहने का अर्थ यही निकलता है। आप अपने शब्दों को वापिस लीजिये। हम पाकिस्तान के ट्रेप में आ गये, हम इसको कतई स्वीकार नहीं करेंगे। कमजोरी आपकी थी। आपने राजस्थान की नाक को कटवा लिया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस का अर्थ यह निकलता है कि राजस्थान सरकार ने, भारत सरकार ने मुतवातिर इसको कहा है कि पाकिस्तान का ४ हजार वर्ग मील पर कब्जा करने का जो क्लेम है वह गलत क्लेम है; हमने हमारी तरफ से यह कहा है कि कुछ आइसोलेटेड प्लेस पर वे आकर बैठे हैं उस वक्त भी हमारे लोग-बाग, पेट्रोलिंग के लिये भी और दूसरे कामों के लिये भी आते जाते थे। तो यह भारत सरकार का और राजस्थान सरकार का बराबर क्लेम स्टेन्ड रहा है और पाकिस्तान का यह कहना कि हमने चार हजार वर्ग मील पर कब्जा किया है वह गलत है, हमने बराबर उसको गलत बताया है। पाकिस्तान का एक प्रोपेगेन्डा रहा है और उसके लिये हमारा यह कहना है। माननीय सदस्यों को मालूम है पाकिस्तान के एरिया में भारत सरकार की फोर्सेज ने आकर सौ, डेढ़ सौ वर्ग मील पर कब्जा किया, माननीय सदस्य खुद देखने के लिये गये, वे देखकर आये हैं कि टेरिटरी पर कैसे कब्जा किया जाता है और जो आइसोलेटेड प्लेस हैं, सूने पड़े हुए ट्रेक हैं, जहां हमारे आदमी भी आते-जाते हैं उन जगहों के लिये पाकिस्तान द्वारा कहना कि चार हजार मील पर हमने कब्जा कर लिया है, उस घुस पैठ को कब्जा माना जाना, मैं समझता हूं वह ठीक नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, ताज्जुब की बात तो यह है कि किसी भावना के कारण वे बात कह गये, शोभा की बात तो यह होती कि वे उन शब्दों को वापिस ले लें और हमारे ऊपर जो यह चार्ज लगाया जाता है कि हम पाकिस्तान के प्रोपेगेन्डा में आ गये, हम उसके ट्रेप में आ गये, तो इसका प्रचार हम ताशकन्द पेक्ट के पहले करते। उसके पहले हमारी

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

सीमाओं में क्या हुआ है, उसके सम्बन्ध में हमने एक शब्द भी नहीं कहा है। जो कुछ तथ्य रखे हैं वे हमने ताशकन्द पेक्ट के बाद रखे हैं। ताशकन्द पेक्ट के बाद हमने, हमारे दल ने जोर-शोर से उन तथ्यों को रखा है और तथ्य रहते हैं तो आप उन तथ्यों से मुकरते क्यों हैं? साथ में सुखाड़िया जी से यह पूछा गया था कि विधान सभा को यह बतायें कि हमारी कितनी चौकियां पाकिस्तान ने ली हैं और हमने कितनी चौकियां पाकिस्तान से वापिस ली हैं, आज तक आपने उसका जवाब नहीं दिया. आप उसको टालना चाहते हैं। आप स्वयं उसके लिये जिम्मेदार हैं, आप ही बता दें। आप इन्कार कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमारा क्षेत्र लिया.......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय......

श्री भैरोंसिंह : ओन ए पोइन्ट ऑफ आॅर्डर....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं उसमें नहीं पड़ना चाहता, न किसी माननीय सदस्य के लिये यह कह कर चलना चाहता हूं डाइरेक्टली और इनडाइरेक्टली कि वे पाकिस्तान का प्रोपेगेन्डा करना चाहते है। मैं यह भी क्लीयर करदूं कि यह कहना कि कोई माननीय सदस्य पाकिस्तान का प्रोपेगेन्डा करना चाहते है. मैंने जो कहा वह सिर्फ इस लिये कहा कि वे इस बात को कह कर चले जाते हैं कि जिसको हमने डिनाई किया है, तो पाकिस्तान के प्रोपेगेन्डे को सपोर्ट मिलता है।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनसे मेरी राष्ट्रीयता पर सीधा आरोप है और जो स्पष्टीकरण उन्होंने किया है उससे हमें ट्रेप में लेने की कोशिश की है कि हमने पाकिस्तान का क्लेम है उसका समर्थन किया है। पाकिस्तान के क्लेम का समर्थन करने का मतलब यह होता है कि हम अराष्ट्रीय हैं, इस लिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी अपने शब्दों को वापिस लें जो उन्होंने अभी सदन के अन्दर कहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने यह नहीं कहा है कि उस क्लेम को हम सपोर्ट करते हैं। उनके प्रोपेगेन्डा के ट्रेप में हम न आजायें, उसके लिये निवेदन किया है।

श्री भैरोंसिंह : आपने जो कहना था वह कह दिया, प्रोसिडिंग्ज आपके सामने है। मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसमें जिद्द और प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। आपने एक दल और एक सदस्य के ऊपर जो इस प्रकार संदेह किया है उसको आप वापिस लें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि न आप पर, न आपके दल पर किसी प्रकार का शक है और न कर रहे हैं। इसका सवाल इससे जुड़ता नहीं है। जो मैंने कहा और जिस रूप में आपने उसको लिया, मेरी कहने की यह भावना नहीं है। इसलिये इस बात को अलग तरह से समझना उपयुक्त नहीं होगा।

माननीय अध्यक्षजी, पाकिस्तान के एग्रेशन के वक्त में, माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय सदस्यों ने इस बात को बताया है कि जो आर. ए. सी. और दूसरे ऑफिसर्स थे उन्होंने अपना कर्त्तव्य-पालन उन

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

मुश्किल हालात में किया था, मैं समझता हूं कि इस सदन के सब माननीय सदस्य मानेंगे कि उन्होंने अपना कर्त्तव्य बहुत बहादुरी और हिम्मत के साथ निभाया।

(करतल-ध्वनि)

दूसरा आर. ए. सी. का स्टाफ टेम्परेरी है और परमानेन्ट नहीं हुआ है उसके लिए सवाल उठाया। मैंने यह कह दिया है कि जल्दी से जल्दी जो कार्यवाही करनी है वह की जाय जिससे उनको क्षति नहीं पहुँचे। बोर्डर होम गार्ड के लोग वहां से आये और यह बताया गया कि उनको किराया नहीं दिया गया, दूसरी मुश्किलें सामने आयीं; मैंने इसका पता लगाया तो मालूम हुआ कि उनको किराया दे दिया गया है, दूर के रहने वाले थे उनको बस किराया भी दिया गया। होम गार्ड ने बहादुरी से काम किया उसकी पूरी कद्र करते हैं और इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इन लोगों को हम किस तरह से रख सकते हैं। गवर्नमेंट उस पर विचार कर रही है।

माननीय अध्यक्षजी, इस संघर्ष में कितने आर्म्स वहां डिस्ट्रिब्यूट किये गये और क्या नीति रही, उसके विषय में इस सदन में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। जो वहां की परिस्थितियां हैं, राज्य सरकार के लिये जो कार्यवाही करना सम्भव हो सकता था, वह राज्य सरकार करती रही। पाकिस्तान के साथ संघर्ष हुआ, वह एक लड़ाई का रूप था जिस पर ओवरआल स्ट्रेटेजी के नाते कितनी फोर्सेज कहां लगे और ओवर ऑल पोजिशन क्या हो उस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने स्ट्रेटेजी कायम की।

मैं ऐसा समझता हूं और आप सब भी यह जानते हैं कि असली युद्ध तो पंजाब के मैदान में हो रहा था, उधर हम ज्यादा से ज्यादा शक्ति लगा रहे थे। देश इस बात को चाहता था कि सारे देश के अन्दर इस सम्बन्ध में कार्यवाही हो। राजस्थान में सीज फायर के बाद धोखे से कुछ कार्यवाही हुई है उस कार्यवाही में यह कहा गया है कि कुछ बोर्डर पर रहने वाले लोग हैं उन्होंने इस मामले में गड़बड़ियां पैदा की हैं। जहां जहां भी राज्य सरकार को इस बारे में जानकारी दी गई वहां कार्यवाही की गई और सभी बोर्डर पर बसने वाले ऐसे लोग हों जिनके लिए यह मानकर चला जाय कि सभी देश के साथ नहीं थे और इस प्रकार की कार्यवाही में लगे हुए थे, यह गलत है। उनमें हजारों व्यक्ति ऐसे भी थे जिन्होंने हर परिस्थिति में देश का साथ दिया है। कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं, चाहे वे कांग्रेस के मेम्बर क्यों न बन गये हों, उनके खिलाफ कार्यवाही की है और आइन्दा भी कार्यवाही करेगी, राज्य सरकार ऐसे लोगों के बारे में आंखें बन्द करके नहीं चलना चाहती है। इस दौरान जो कार्यवाही करना उनके लिए आवश्यक था वह की गई और आगे भी कार्यवाही की जायगी।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं इतना और निवेदन करूंगा यहां पर, जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ उसके बारे में जो सवाल किये गये उनके विस्तार में न जाकर एक ही प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। यह कहा गया कि इस अधिवेशन में ५० लाख रुपये खर्च कर दिये गये। इस बारे में मैंने पता लगाया जो स्टेडियम बनने

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
वाला था उस स्टेडियम का काम पूरी गति से आगे भी चल सके, इस लिहाज से कार्य किया गया। कुल खर्चा ६५-६६ के बजट में इस पर ६ लाख के आसपास हुआ जो खर्चा हमें करना था।

श्री भैरोंसिंह : मैंने केवल स्टेडियम-निर्माण के खर्चे को लेकर नहीं कहा, चित्तौड़ में कितना खर्चा हुआ, पुलिस पर, प्रदर्शनियों पर, एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा जो हुआ वह सब मिला कर कहा था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दूसरा सवाल पुलिस के इन्तजाम के बारे में कहा जाता है। पुलिस का इन्तजाम तो कोई भी जल्सा हो, इस प्रकार की स्थिति हो, तो उसमें इन्तजाम करना होता है। आज कहीं भी मेला लगता है, वहां भी पुलिस का इन्तजाम करना होता है। सिक्योरिटी के लिए पुलिस का इन्तजाम करना होता है, यह है कि जितना बड़ा जल्सा होता है उसके हिसाब से पुलिस का भी इन्तजाम होता है, यह केवल कांग्रेस के जलसे के लिये किया गया हो, यह बात नहीं। जहां कहीं भी जल्सा होता है, किसी भी पार्टी का होता है, वहां करना पड़ता है।

इसके साथ ही बिजली पानी और दूसरे एक्सपेंडीचर इस जलसे के समय हुए, उन सब का खर्चा कांग्रेस की ओर से दिया गया। कोई सरकार की तरफ से इस सारे खर्चे को किया गया हो, यह बात नहीं है।

एक माननीय सदस्य : चित्तौड़ में कितना हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जहां तक एडवर्टाइजमेन्ट देने और पुस्तकें आदि छपवाने की बात है उसके लिये निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की पब्लिसिटी हो, हिन्दुस्तान भर के लोग उसमें आये, उनको राजस्थान के बारे में जानकारी मिल सके, यहां क्या पोटेन्शियल है, क्या काम हो रहा है, इसके लिये जानकारी हो, वहां इस प्रकार की पुस्तकें छपवाना आवश्यक है। ऐसे जलसों में प्रदर्शनियां लगती हैं, पत्रों के विशेषांक निकलते हैं, उनके अन्दर जो भी नियमानुसार होता है, एडवर्टाइजमेन्ट मिलता है, जो कुछ भी विशेषांक आदि में एडवर्टाइजमेन्ट दिया गया है वह गलत नहीं कहा जा सकता।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अगर किसी पार्टी का आल इन्डिया जल्सा हो तो उसके लिये आप स्टेडियम दे देंगे। हम भी इसी पैमाने पर जल्सा करेंगे; उसमें राजगोपालाचारी और श्री रंगा को बुलायेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जिस प्रकार से किराया देकर स्टेडियम कांग्रेस ने लिया है उसी प्रकार किराया देकर दूसरी पार्टी वहां जल्सा करना चाहती है तो उनको सुविधा दी जायगी।

श्री मानसिंह महार : विज्ञापन आदि भी देंगे क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि एग्जीबिशन इस अधिवेशन में लगाई गई, उसमें डिफेन्स की एग्जीबिशन भी थी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस एग्जीबिशन में एन्ट्री फीस जो ली गई उसकी वजह से जो इनकम हुई है उस इनकम का एक पैसा भी कांग्रेस नहीं ले रही है,

Page No. 114

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
इसको इनकम को बिल्कुल अलग मान कर चल रहे हैं। उसमें जो खर्चा हुआ उसके बाद जो कुछ बचत होती है वह डिफेन्स फन्ड में भेज दी जायगी।

श्री मानसिंह महार : इस डिफेन्स फन्ड में तो कम से कम इस प्रकार का पैसा मत दीजिये, इसको तो अपवित्र मत करिये। मैं चोरी करके कह दूंगा कि जितना पैसा मुझे चोरी का मिला वह डिफेन्स फन्ड में देता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कांग्रेस अधिवेशन के समय जो एग्जीबिशन लगी उससे कांग्रेस को फायदा हुआ हो, यह बात नहीं। इससे सारे राजस्थान की जनता को लाभ पहुंचा। एग्जीबिशन में चीजें रखी गईं, हजारों आदमियों ने उससे लाभ उठाया। ऐसे जलसों पर जो एग्जीबिशन होती है, उसके लिये तो आपको खुशी होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मानसिंह महार : मेरा एक सवाल था डिप्टी मिनिस्टर, होम के बारे में, जो बात मैंने कही, उसके बारे में आप बिल्कुल मौन रहे, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य काफी प्रश्न पूछ चुके हैं।

श्री मानसिंह महार : वह पर्टीक्यूलर पोइन्ट रेफर किया था; डिप्टी मिनिस्टर, होम के लिये जो बात कही, कुरैशी के बारे में। जब उनके पी०ए० की गिरफ्तारी होती है तो वे डिप्टी मिनिस्टर होम नहीं रह सकते, उनको मिनिस्टरी से इस्तीफा देना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके बारे में मुझे व्यक्तिगत तौर से जानकारी है कि डिप्टी मिनिस्टर, होम ने स्वयं ने इनीशियेटिव लेकर इस आदमी को पकड़वाने के बारे में कार्यवाही की है, इसके लिये उनको धन्यवाद देना चाहिये।

श्री मानसिंह महार : मेरा पोइन्ट बिलकुल दूसरा है। एक आदमी एक गलती करता है, वह गलती करने के बाद पकड़े जाने के डर से खुद ही मुखबिर बन जाता है, इसी तरह से डिप्टी मिनिस्टर मुखबिर हो गये। आपको इस प्रकार उन्हें शील्ड नहीं करना चाहिये, यह बिल्कुल अनुचित बात है।

श्री सरोसिंह (किशनपोल, जयपुर) : एक प्रश्न का तो जवाब आ गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपने जो कुछ मुद्दे उठाये थे उसके बारे में कल जानकारी दे दूंगा।

श्री सरोसिंह : आपने डिप्टी होम मिनिस्टर के बारे में बात कही वह ठीक है। लेकिन सेक्रेटेरिएट का केयर टेकर जो पाकिस्तान की ओर से जासूसी करने के लिये पकड़ा गया उस केयर टेकर के बारे में जो सारी सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग का इन्चार्ज है, जिसके पास सारे तालों की चाबियां रहती हैं वह केयर टेकर हमारे देश की खबरें पाकिस्तान को भेजता था, उसके लिए कौन जिम्मेदार है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जिस तरह से डिप्टी होम मिनिस्टर का पी० ए० पकड़ा गया उसी तरह से वह भी पकड़ लिया गया।

एक माननीय सदस्य : वह आपने पकड़वाया है?

श्री भैरोंसिंह : यह कह कर आप टाल नहीं सकते ।

श्री अध्यक्ष : पांच बज चुके हैं क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय बढ़ा दिया जाय ।

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया। श्री कौल ।

(विराम)

(५.०० म० प०)

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से इन पांच दिनों से मेरे बजट भाषण पर बहस हो रही थी और जिसका जवाब एक तफसील में हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने अभी आपके सामने दिया ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : "जी" मत लगाओ ।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान्, जिस तरीके का बजट सामने था और जिस तरीके से उस पर बहस मुबाहसा हुआ उससे मालूम यह हो रहा था और लोग सुन रहे थे इधर के भी और इधर के भी जैसे कि बहस में कोई संजीदगी नहीं है । यह होली के बाद फाग उड़ाई जा रही है ।

मैं यह निवेदन करना चाहता था कि उसका जवाब........

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आपका बजट भी होली के अनुरूप था ।

श्री बालकृष्ण कौल : जिसका ताल्लुक नहीं था बजट से उन बातों को सदन में रखा गया । तो मैं यह निवेदन कर दूं........

श्री मानसिंह महार : बजट बनाना तो आप पहले सीख लें । फिर सर्मन देना ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । अभी जरा शुरू करने दीजिये ।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं यह निवेदन करूंगा कि आप जरा शान्ति से मुझे दो-चार मिनिट तो बोलने दें । क्योंकि मुख्य मंत्री इस पर बोल चुके हैं काफी देर तक, अगर उनको एक घंटा बोलने नहीं देते तो मुझे ज्यादा समय लेना होता । पर वाकयात और तथ्य जितने आपने सदन में रखे उससे इस बजट का सम्बन्ध नहीं था । वह तो एक तरह से जनरल डिबेट हो गई, सिवाय एक-दो बातों के जो आपने करों के बारे में कही है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, इस सदन के अन्दर जब जनरल डिसकशन होता है तो सभी को पता है कि हर चीज का छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी का उल्लेख किया जाता है । इसलिए इस तरह का राजस्थान सरकार के एक वित्त मन्त्री का कमेन्ट है तो यह उनकी इग्नोरेन्स ही जाहिर करती है । जवाब देने के बजाय वे यह कहते हैं कि इन छोटी-छोटी चीजों, छोटे-छोटे पोइन्ट्स का ताल्लुक नहीं था और इनका जवाब दिया है चीफ मिनिस्टर ने । यह बात सही है कि इन सबका ताल्लुक है । आप जवाब दें और हम यह जवाब नहीं पसन्द करेंगे कि चूंकि सही पोइन्ट्स आपसे नहीं कहे, इसलिए जवाब नहीं मिलेगा । कोई मेम्बर यह बादस्तूर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि जो उन्होंने माननीय सदस्यों ने बातें कहीं वे सम्बन्धित नहीं थीं ।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
इस तरह के व्यू को रख कर आप नहीं चल सकते।

श्री मानसिंह महार : कमाल कर दिया, साहब।

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्य जो नसीराबाद से तशरीफ लाये हैं उन्होंने अपने राजस्थान के वित्तमंत्री को इग्नोरेन्ट बताया।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इग्नोरेन्ट के माने क्या होते हैं, यह तो जरा समझावें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : वे क्या समझे हैं, वित्त मन्त्री जानते हैं, वे ही बता दें।

श्री बालकृष्ण कौल : कांग्रेस पार्टी का वित्त मंत्री इग्नोरेन्ट है, इससे ज्यादा इग्नोरेन्स समझने में और हो ही क्या सकती है।

(हियर हियर)

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : पार्टी का इस तरह से नाम जोड़ने और लेने की जरूरत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : पार्टी का, मन्त्री इग्नोरेन्ट नहीं है।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं यह निवेदन कर रहा था कि बहुत सी चीजें सदस्य सदन के सामने रखते हैं और जो चीजें इस वक्त बजट के सामने थीं उनको एक सेकण्डरी इम्पोर्टेन्स देकर दूसरी चीज सामने आई और ऐसी चीजों को लेकर बहुत से सदस्य सामने आये। यह मेरी अपनी राय है। बजट की डिमाण्ड्स के वक्त ये चीजें लाई जा सकती थीं। तब भी इन सबका एक बिफिटिंग रिप्लाई माननीय मुख्यमंत्री ने दे दिया है।

अब मैं इतना निवेदन करूं कि अधिकतर जो माननीय सदस्य यहां बोले, उन्होंने अपनी बात रखते हुए भी एक चीज से उनका विरोध था। वह यह था कि आज की परिस्थितियों में, जिसमें से राजस्थान गुजर रहा है, जैसा कि मैंने अपने बजट भाषण में कहा था कि अकाल है, पानी का अकाल है, वगैरा और इस तरह से लोगों की माली हालत गिर गई है और जिसके कारण से हमें जितना रेवेन्यू आना चाहिये था वह नहीं आया।

इन हालात की पृष्ठभूमि में जो माननीय सदस्यों ने बातें रक्खीं उनमें कुछ वजन था और उस वजन का लिहाज रखते हुए मुझे आखिर यह सोचना पड़ा कि मैं क्या और कहां तक इस बजट के करों में कुछ कमी कर सकता हूं।

(हियर हियर)

कुछ माननीय सदस्यों ने.........

श्री भैरोंसिंह : वापिस लेने हैं, और ताली बजवानी है।

श्री अध्यक्ष : आपको क्या ऐतराज है?

श्री भैरोंसिंह : वे तो वापिस लेंगे।

श्री बालकृष्ण कौल : बता दें तो फिर, क्या क्या लूंगा?

श्री भैरोंसिंह : पशुओं पर और तेल पर से वापिस लेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप कयास मत करिये।

श्री मानसिंह महार : यह तो इनकी ही पार्टी में तै हुआ था। फिरथ कॉलमनिस्टों ने बता दिया, लीकेज हो गया।

श्री बालकृष्ण कौल : मुझे कहने तो दें।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो कच्चे चमड़े पर सेल्स टेक्स था, उसको मैं विड्रा करता हूं, मैं मानता हूं, ऐसा करके मैंने गलत नहीं किया।

दूसरी बात, मैं यह निवेदन कर रहा था कि ज्वेलरी पर टेक्स था। यह सोचकर कि यहां की इन्डस्ट्री है ज्वेलर्स की, इस इन्डस्ट्री को भी नुकसान न हो, इन सब बात का लिहाज रखते हुए यह फैसला किया कि आखिरी पोइन्ट पर टेक्स लिया जावे। लास्ट पोइन्ट पर स्टेट के भीतर क्योंकि यह बहुत से प्रोसेस में से गुजरता है और इन्टर स्टेट में दो परसेंट लिया जावे।

श्री भैरोंसिह : सवाल इसमें परसेंटेज का नहीं है, टेक्स का है।

श्री बालकृष्ण कौल : मैंने कहा न कि लास्ट पोइन्ट पर लिया जावेगा, ५ परसेंट। और इन्टर स्टेट टेक्स दो परसेंट लिया जावेगा। हटाया नहीं है।

श्री भैरोंसिह : इस टेक्स में इन्डस्ट्री का लिहाज करें। यह टेक्स खुद में ही एक प्रोबलम है। इससे इन्डस्ट्री खत्म हो रही है।

श्री बालकृष्ण कौल : यह मैंने बता दिया।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि क्योंकि इन्डस्ट्री के खतरे में पड़ने का डर था, इसलिये तो यह कहा है और किया है। यह कई हाथों में से चीज निकलती है, तो हर बार टेक्सेबल न हो जावे, इसलिये लास्ट पोइन्ट पर टेक्स किया है ताकि बीच के पीरियड में यह न लगे।

तो अब मैं माननीय सदस्यों को बताऊं कि आगे घी पर आता हूं। घी पर टैक्स जो मैंने लगाया है वह वैसा ही रहेगा।

श्रीमन्, अब मैं घाणी तेल पर आता हूं। घाणी के तेल पर अब ५ परसेंट है।

श्री बलवन्तसिंह (आबू) : घी का कितना है यह तो बता दीजिये।

श्री बालकृष्ण कौल : घाणी तेल पर मुझे निवेदन करना है, क्योंकि यह जो टेक्स है यह हरेक व्यक्ति जो घाणी का काम करता है उसके ऊपर आकर पड़ता है। घाणी के तेल पर अभी भी टेक्स है, लेकिन जिस किस्म का टेक्स हम लगा रहे थे उससे घाणी के चलाने वालों पर यह सीधा पड़ता है। इसलिये यह मैंने सोचा कि कैसे इन लोगों पर, जो कसरत से गांवों में रहते हैं, और हिसाब-किताब अच्छी तरह जानते नहीं हैं, उनके ऊपर आज की परिस्थितियों में यह टेक्स का भार न पड़े। इसलिये यह टेक्स मैं विड्रा करता हूं।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय.......

श्री मानसिंह महार : यह प्रचार तो चीफ मिनिस्टर का सा लग रहा है।

श्री बालकृष्ण कौल : अध्यक्ष महोदय, एक टेक्स जिसके ऊपर बहुत विवाद था और हर तरफ से यह विचार रखे गए थे कि यह सीधा किसानों के ऊपर पड़ता है वह था

(श्री बालकृष्ण कौल)

फेटल टेक्स । श्रीमन्, यह टेक्स पहले से चला आ रहा है और उसमें ही कुछ संशोधन किया है, जिस संशोधन पर जब मैंने यहां सबकी डिबेट सुनी, तो मुझ पर भी यह असर हुआ कि इस टेक्स से जो मेलों में पशुओं की बिक्री होती है, वहां किसान आकर अपना पशुधन बेचता है। उसमें लोकल ट्रान्जेक्शन भी होते हैं, और बाहर के भी होते हैं जो बाहर जाते हैं। लेकिन आज के हालात को देखते हुए कि किस तरीके से किसानों के ऊपर आज की हालात में तकलीफ है और माली हालत उनकी इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, बारिश नहीं होने के कारण..........

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (बांसपुर) : यह आप मानते हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : यह तो मैंने बजट स्पीच में कहा है ।

सरकार ने यह मुनासिब समझा है कि जिस तरह से टेक्स चल रहा था एक्सपोर्ट पर, नाकों पर वह बदस्तूर रहेगा लेकिन जो मेलों पर लगाया गया था वहां होने वाले लोकल ट्रान्जेक्शन पर वह मैंने विदड्रा किया है।

श्री भैरोंसिंह : तेल पर से टेक्स हटा कर आपने शनिदेव को खुश कर दिया।

श्री बालकृष्ण कौल : इस हालत से इन टेक्सों को वापिस लेने से मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट में एक गैप रहेगा । कल को कोई माननीय सदस्य यह कह कर नहीं चले कि डेफिसिट फाइनेन्सिंग रहा है । तो मैं आज इस स्थिति में नहीं हूं कि इसके लिए अभी कोई योजना रख सकूं । मैं इंतजार कर रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के जो टेक्सेज अनाउन्स हुए हैं उनका क्या नतीजा निकलता है और उसमें कितना संशोधन होता है या उसमें क्या होता है। तो इन हालात को देखते हुए मैं इस समय मौजूदा गेप को भरने के लिए कोई नया टेक्सेशन बिल आपके सामने नहीं रख सकता हूं। लेकिन आपको यह मालूम हो कि इसमे असर कोई ३०-४० लाख से कम नहीं होगा । लेकिन कोशिश यह करूंगा आपकी मदद मे कि आप इस गैप को भरने के लिए हमारी मदद करें। मितव्ययता के लिए तो बहुत कहा जाता है लेकिन जब इकोनोमी का सवाल आता है, मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमने २ करोड़ ६४ या ६८ लाख की इकोनोमी की ओर १ करोड़ का आपके सामने प्रावधान है; लेकिन जब भी इकोनोमी होती है उस समय मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि जिस समय इकोनोमी की जा रही हो तो कहीं सुझाव हो तो हमारे पास आयें, बाकी हमारे पास न आयें । क्योंकि यह कोआपरेशन हमको मिलता रहा तो शायद सरकार को काफी बल मिलेगा और जो आंकड़े उन्होंने इकानामी के लिए रखे हैं वे शायद पूरे हो सकेंगे। और भी जो मैंने बताया कि जो गैप है उसके लिए आप कोई सुझाव दें। मैं मानता हूं कि जो अपोजीशन के मेम्बर्स हैं वे इसमें हिचकिचाते हैं और वह शायद इसलिए हिचकिचाते होंगे कि वह हुकूमत में आना चाहते हैं, लेकिन वह हुकूमत में आने वाले नहीं हैं। इसलिए वे हर किस्म का वाद-विवाद कर सकते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं

(श्री बालकृष्ण कौल)
कि जो मैंने टैक्स प्रपोज़ल्स को विड्रॉ किया है उसको हाउस एक्सेप्ट करेगा।

मैं एक बात और आपसे निवेदन कर दूं कि बहुत सी बहस कन्ज्यूमर्स स्टोर्स के ऊपर हुई। मुझे माफ करेंगे अगर मैं बड़ा नम्र निवेदन करूं कि इस कन्ज्यूमर्स स्टोर्स की स्कीम को माननीय सदस्यों को सराहना चाहिए क्योंकि यह ठीक है कि जैसा कुछ माननीय सदस्यों ने शंका प्रकट की है कि वह काम कर सकेंगे या नहीं, तो उसमें हमें सहयोग मिलना चाहिए, न कि यह कि वे स्टोर्स जिनमें हम फिक्स्ड चीजें देंगे जो कि जिन्दगी की जरूरियात की हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): वे कौन कौनसी चीजें होंगी?

श्री बालकृष्ण कौल: वह लिस्ट आपके सामने आयेगी।

एक माननीय सदस्य हैं नसीराबाद से आने वाले उन्होंने ५ चीजों के बारे में कहा। मैं बता दूं कि हम वर्क आउट कर रहे हैं। इसी सदन में मैं वह लिस्ट रखूंगा। तो वे चीजें जरूरियात के लिए काफी होंगी और ख्याल भी यह है कि जो भी चीजें दी जायेंगी वे सबसीडाइज्ड रेट पर दी जायेंगी........

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): कितनी सबसिडी देंगे?

श्री बालकृष्ण कौल: सबसीडाइज्ड रेट पर देंगे, सब्सीडी नहीं देंगे, यह कहा है मैंने। क्योंकि यह चीज कन्सीडरेशन में है और वर्क आउट हो रही है इसलिए मुझे उम्मीद है कि माननीय सदस्य यह ५ रुपये का भूत भुलाकर इस पर आयें कि हम कन्ज्यूमर्स स्टोर्स को अच्छी तरह से चला सकें और मुझे यकीन है कि अगर माननीय सदस्य खास करके जो अपोजीशन में बैठे हैं वे सरकार की मदद करें और सलाह दें तो वे स्टोर्स अच्छी तरह से चल सकते हैं और जो प्राइस लेवल बढ़ती है वह प्राइस लेवल घटे।

श्री भैरोंसिंह: एक बात बता दें कि आपने बजट भाषण के अन्दर जिसको इन्ट्रोड्यूस किया है उसकी कम्पलीट स्कीम बनाई है या नहीं? और जो सब्सीडाइज्ड रेट पर आप चीजें देंगे उससे एक साल में किस सीमा तक गवर्नमेन्ट को लोस होगा?

श्री बालकृष्ण कौल: मैंने उस समय भी कहा और अभी भी कह रहा हूं कि स्कीम के लिए जितना मैटीरियल आना चाहिए उसके लिए हमारे अफसरान बाहर गये हैं, दूसरे प्राविन्सेज के अन्दर, जहां ये स्टोर्स चल रहे हैं; वे हमारे सामने आ जावेंगे तब मैं इस हालत में होऊंगा कि मैं आपके सामने पूरी स्कीम रख सकूं।

श्री भैरोंसिंह: यानी सरकार को कोई जानकारी नहीं है इस स्कीम की?

श्री बालकृष्ण कौल: कच्ची जानकारी मैं सदन के सामने रख नहीं सकता।

श्री भैरोंसिंह: कच्ची भी है क्या?

श्री बालकृष्ण कौल: वह मैं सदन के सामने रखने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं बिलकुल नहीं रखिये।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म०प० ५ बजकर १८ मिनिट पर १७ मार्च, १९६६ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक १६ मार्च, १९६६)

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
२७७३-२७७४	उप-शोर्षक	कार्यवाहो	कार्यवाही
२७७३	११	उद्योग विभाग)	उद्योग-विभाग)
२७७५	१२	फरवरो	फरवरी
२७७६, २७७८ व २७८०	शोर्षक	तरांकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
२७७७	अन्तिम से ६	उप मंत्री,	उप-मंत्री,
२७७८	१७	सवारो	सवारी
२७८०	३	श्री अध्यक्षः	श्री अध्यक्ष :
,,	अन्तिम से ३	विभ ग	विभाग
२७८२	८	सक्यूलस	सक्यूंलर
२७८४	२०	प्रतिबर्ष	प्रतिवर्ष
२७८६	८	निधारित	निर्धारित
२७८७	१०	श्री भैरोसिह	श्री भैरोंसिह
२७८८	२३	सं घ	संबंध
२७९०	१५	क्रासिग	क्रोसिंग
,,	अन्तिम से ३	ऐक्शन	एक्शन
२७९४	अन्तिम से ४	विद्यूत्	विद्युत्
२७९७	१४	घिश्रान्ति	विश्रान्ति
२७९८	७	ext श्री	Next. श्री
,,	९	(अनुपस्थित !	(अनुपस्थित--
२७९९	११	टन्समोशन	ट्रान्समीशन
२८०१	१६	इरिगेशन	इर्रिगेशन
,,	अन्तिम से ५	क्या हुआ ?	क्यों हुआ ?
२८०२	अन्तिम से ८	आकड़े	आंकड़े
२८०३	शीर्ष	(श्री हरिशचन्द्र)	(श्री हरिश्चन्द्र)
,,	अन्तिम से ४	कभी	कमी
२८०४	अन्तिम से ८	हाइहल	हाइडल
२८०५	३	मारत	भारत
२८०६	७	डब्लयू. डी	डब्ल्यू० डी०
,,	१२	कन्जन्पशन	कन्जम्प्शन
२८०७	३	मे विलम्व ।	में विलम्ब
,,	अन्तिम	मं	में
२८०८	३	फलाग	फर्लांग
२८१०	४	अध्यक्षः	श्री अध्यक्ष :
,,	६	(लूनकरणसर)	(लूणकरणसर)

१	२	३	४
२८१०	अन्तिम से [illegible]	[illegible]	और
२८११	१३	जयपुर.) वहां	जयपुर) : वहां
,,	अन्तिम से ४	सेक्शन	सक्शन
२८११ व	अन्तिम से	एग्रीकल्चुरल	एग्रीकल्चरल
२८१२	६, ४ व अन्तिम से ७		
२८१५	२	जोयेंगे	जायेंगे
,,	अन्तिम से ४	घटेन	घटने
२८१६	[illegible]	मैंने	मैने
२८१७	[illegible]	रखा	था
,,	१८	प्रीसीडिंग्स	प्रोसीडिंग्स
,,	[illegible]	अवक	[illegible]
२८१८	६	मुअ।वजा	मुआवजा
,,	अन्तिम से ५	तरमीन	तरमीम
२८१९	१	की	को
२८२०	[illegible]	चतुथ	चतुर्थ
२८२७	अन्तिम [illegible]	स) :	[illegible]
२८३१	अन्तिम से ३	जुरहडा की	जुरहड़ा को
२८३७	अन्तिम से २	खिलाफ	खिलाफ
२८४०	[illegible]	श्री ज्वाल प्रसाद	श्री ज्वालाप्रसाद
,,	[illegible]	श्री सतश्चन्द्र	श्री सतीशचन्द्र
२८४१	६	कहेगे।	कहेंगे।
,,	२	वहुत	बहुत
,,	अन्तिम से ४	होया	होगा
२८४४	अन्तिम से ४	अव	अब
२८४६	[illegible]	बिषयक	विषयक
२८५०	[illegible]	दगे ?	देंगे ?
२८५१	[illegible]	रम	रूप
२८५४	[illegible]	ामान्य	सामान्य
,,	अन्तिम से [illegible]	दौरे पर रहे	दौरे पर रहें
२८५५	[illegible]	विला	[illegible]
२८५६	अन्तिम से ३	Og nization	Organization
२८५७	[illegible]	मार्स	मार्च
२८६१	अन्तिम से १४	नौक शाही	नौकरशाही
२८६५	अन्तिम से १२	व	[illegible]
२८६६	१५	lit le	little
,,	[illegible]	b ing	being
२८६८	[illegible]	So e	Some
,,	[illegible]	t e	the
२८७२	अन्तिम से १३	अपको	आपको
२८८१	१४	सरी	सारी
२८८७	[illegible]	८७]	२८८७]
२८८९	अन्तिम से १२	श्री नथूराम	श्री नाथूराम

१	२	३	४
२८६०	७	मे ा	मेरा
,,	१२	वातें	बातें
,,	अन्तिम से ५	शोशियल	सोशियल
२८६१	अन्तिम से १५	लए	लिए
२८६२	५	आका	आकार
२८६३	३	दिक तों	दिक्कतो
२८६४	१६	व्यव थित	व्यवस्थित
,,	२२	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिह
२८६५	अन्तिम	स	इस
२८६६	६	सेक र	सेक्टर
,,	११	प्रायोरिटि	प्रायोरिटी
,,	अन्तिम से २	मह रावल श्री लक्षमणसिह	महारावल श्री लक्ष्मणसिह
२८६७	२	ती	तो
,,	अन्तिम से ११	पु तकें	पुस्तकें
२९००	अन्तिम	लगान	लगाना
२९०२	६	कर था	कर रहा था
२९०४	अन्तिम से १७	सेन्टर की ने	सेन्टर ने
२९०७	१६	आपको	आपकी
२९०९	१५	में	में
२९१०	अन्तिम से ६	बिमारी	बीमारी
२९१३	अन्तिम से ४	अपन	अपने
२९१४	अन्तिम से ३	सो-दो सो	सौ- दो सौ
२९२६	अन्तिम से ८	शमा	शर्मा
२९२९	अन्तिम से ३	कट मोसन्स	कट मोशन्स
,,	अन्तिम से २	सो बार	सौ बार
२९३०	अन्तिम	जस कुछ ह हा नहा ।	जैसे कुछ है ही नहीं ।
२९३२	१२	देखने नहीं आया	देखने में नहीं आया
,,	अन्तिम से १२	आर	और
२९३३	१	कांग्रस	कांग्रेस
२९३४	८	उन्होने	उन्होंने
,,	अन्तिम से ५	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिह
,,	अन्तिम	गोवर	गोबर
२९३५	३	सदम्य	सदस्य
२९३६	अन्तिम से ६	दि ।।	दिया
२९३७	१०	अ नी	अपनी
२९३८	१९	अपके	आपके
२९३९	अन्तिम से १०	रह	रहे
,,	अन्तिम से ३	आदेशों	आदेशों
२९४१	अन्तिम से ५	सिड्यूल्ड	शिड्यूल्ड
२९४४	शीर्षक	जनलेखा एवं प्रा, स० विन० सं०	जनलेखा एवं प्रा० स० निर्वाचन सम्बन्धी

१	२	३	४
२९४५	११	गरींबो	गरीबी
,,	१४	पूति	पूर्ति
,,	अन्तिम से ५	मैं	में
२९४६	२	प्रयत्न	प्रयत्न
,,	६	ईन्वेस्टभेन्ट	इन्वेस्टमेन्ट
,,	९	वढे	बढे
,,	१०	वढने लिए	बढने के लिए
,,	१७	जाहे	चाहे
२९४७	२	इरिगेशन	इरिगेशन
,,	८	के	——
,,	९	क्योंकि	क्योंकि
२९४८	३	कान	काम
,,	अन्तिम से ४	वात	बात
२९४९	१०	में समझता	में समझता
,,	११	में भो राजस्थान	में भी राजस्थान
२९५०	२६	में वहुत	में बहुत
२९५१	४	वे	वे
,,	६	विसान	किसान
,,	२४	आइ है, फर्क	आई हैं, फर्क
२९५४	१	तीसरी	तीसरो
,,	१५	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिह
,,	२१,२५	एक्सपन्डोचर	एक्सपेन्डोचर
२९५६	अन्तिम से २	ज्याना	ज्यादा
२९५७	५	नही	नहीं
२९५८	२५	इगलैण्ड	इंग्लैण्ड
२९५९	१	इडस्ट्री	इन्डस्ट्री
२९६०	अन्तिम से ४	इरिगेशन	इरिगेशन
२९६३	शोर्षक	अग्रेतर	अग्रेत्तर
२९६४	१४	रिसोर्सेज	रिसोर्सेज
२९६५	४	डेवलपाट	डेवलपमेन्ट
,,	अन्तिम से ६	श्री लक्ष्मणसिंह	श्री लक्ष्मणसिंह
२९६६	९	नही	नहीं
,,	१८	श्री मोहनलाल सुखाडिया	श्री मोहनलाल सुखाडिया
,,	२०	महारावल श्री लक्ष्मणसिंह	महारावल श्री लक्ष्मणसिंह
२९६७	शोर्ष	(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)	(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
,,	८	नही	नहीं
,,	९	पर्फोटनेस	पर्फेक्टनेस
,,	१७	दृष्टिकोण	दृष्टिकोण
२९६८	१६	महरावल श्री लक्ष्मणसिंह	महारावल श्री लक्ष्मणसिंह
,,	अन्तिम	।।हा।	साहब
२९७०	शोर्षक	विचार विमश	विचार विमर्श

१	२	३	४
२६७०	१८	श्री भंरोसिंह	श्री भैरोंसिंह
,,	२०	भो	भी
,,	अन्तिम से ५	श्री मोहन लाल सुखाडिया	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
२६७१	२, ६, १३, व अन्तिम से २	,,	,,
,,	११	श्री महारावल लक्ष्मणसिंह	महारावल श्री लक्ष्मणसिंह
,,	अन्तिम से ६	पूर्ति	पूर्ति
,,	अन्तिम से ४	नहींष,	नहीं,
२६७२	२३	महारावल श्री लक्ष्मणसिंह	महारावल श्री लक्ष्मणसिंह
,,	२७	माननीय अ मक्ष जो,	माननीय अध्यक्षजी,
२६७३	६	श्री मोह लाल सुखाड़िया	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
,,	१०, १८–१६	छूआछुत	छूआछूत
,,	१३	श्रीभैरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
,,	२० व अन्तिम से २	श्री मोहनलाल सुखाडिया	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
२६७४	१७	चुछ	कुछ
,,	१६	शिड्यूल्डट्राईब्स	शिड्यूल्ड ट्राइब्स
,,	अन्तिम से ५	नहीं	नहीं
,,	अन्तिम से ४	श्री मोहनलाल सुखाडिया	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
२६७५	४	एग्रीकल्चरल	एग्रीकल्चर
,,	१५	श्री मोहनलाल सुखाडिया	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
२६७६	८	फिर	फिर
,,	१५	पब्लि	पब्लिक
,,	२१	श्री गोकुलप्रसद शर्मा	श्री गोकुलप्रसाद शर्मा
,,	२५,३–१	श्री मोहनलाल सुखाडिया	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
२६७७	६	निनेदन	निवेदन
,,	८	चहता	चाहता
२६७८	६	पाकिस्तान	पाकिस्तान
,,	१३	सुखाडिया	सुखाड़िया
,,	२०	उतके	उसके
,,	२५	श्री भैरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
,,	अन्तिम २	चाईनीज	चाइनीज
२६८०	१८	सुखाडिया	सुखाड़िया
,,	२४	श्री भैरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
२६८१	१३	श्री कृष्णकुमर गोयल	श्री कृष्णकुमार गोयल
,,	२०	सरेंडर	सरेंडर
२६८२	१६	सुखाडिया	सुखाड़िया
,,	२४	चिठि्ठयां	चिट्ठियां
२६८३	१६	चिठि्ठयां	,,
,,	२०	चिठि्ठयां	,,
,,	२२	सिक्योटिटी	सिक्योरिटी
२६८४	अन्तिम से ४	उसों	उसमें

६

१	२	३	४
२९८७	१	श्री मरोंसिह	श्री मेरोंसिह
,,	१७	के क	के कई
२९८९	अन्तिम	फरवरी	फरवरी
२९९५	अन्तिम से २	गवनमेंट	गवर्नमेन्ट
३०००	,, ,, ५	श्री मोहनलाल सुखाडिया	श्री मोहनलाल सुखाडिया
३००३	३	श्री मार्नसिंह महार	श्री मानसिंह महार
३००६	१	विड्रॉ	विद्ड्रॉ
,,	२४, २७	सबसीडाइज्ड	सब्सीडाईज्ड
,,	२५	(आसीलम)	(आसीन्द)
३०१०	अन्तिम से २	१७ मार्च, १९६६ के	१७ मार्च, १९६६ के म. पू.